चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 10 फरवरी –16 फरवरी 2014 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

मुसलमानों को कांग्रेस ने सिर्फ़ धोखा दिया

मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक़ अल्पसंख्यकों का है. जब उन्होंने यह कहा था, तो लगा कि मुसलमानों की समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं. अब चुनाव होने वाले हैं. मनमोहन सिंह की विदाई तय हो चुकी है. आज यही कहा जा सकता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से देश के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयानों में यह बयान सबसे बड़ा छलावा साबित हुआ.

पिछले 10 सालों में मुस्लिम समुदाय विकास की मुख्य धारा से बाहर हो चुका है. इसकी कई वजहें हैं. शिक्षा और शिक्षा का स्तर एक बड़ी वजह है. मुस्लिम युवा वर्तमान की प्रतियोगी दुनिया में पिछड़ रहे हैं. निजी क्षेत्र में पक्षपात का भी मामला है. सरकारी क्षेत्र में भी जहां इंटरव्यू का मामला होता है, वहां भी वे भेदभाव के शिकार होते हैं. मीडिया और राजनीति ने ऐसा वातावरण बना दिया है, जिससे मुसलमान मुख्य धारा से विमुख होते जा रहे हैं.

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

यह मुसलमानों को याद करने का मौसम है. उनकी समस्याओं पर बहस का मौसम है. यह मुसलमानों को ख़तरे बताने का मौसम है. यह मुसलमानों को डराने का मौसम है. यह चुनाव का मौसम है. यही वजह है कि हर राजनीतिक दल में मुसलमानों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है. मुसलमानों के दु:ख पर आंसू बहाए जा रहे हैं. ऐसा हर चुनाव से पहले होता है. हर बार मुसलमानों को बरगलाने के दांव खेले जाते हैं. हाल तो यह है कि एक बार घड़ियाल के आंसू पर यकीन हो जाए, गिरगिट के रंग पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन देश के राजनीतिक दलों की चालबाजी पर एक फ़ीसद भी यकीन करना मूर्खता होगी. दरअसल, राजनीतिक दलों की नज़रों में मुसलमान इंसान नहीं, महज एक वोटबैंक हैं, जिन्हें कुछ झूठे वादे करके, बहला-फुसला कर, पैसे देकर, आरएसएस एवं मोदी का ख़ौफ दिखाकर भ्रमित किया जा सकता है और वोट लेकर उन्हें दुत्कार कर फेंका जा सकता है. हकीकत भी यही है. मुसलमान जज्बाती लोग हैं, धर्म की राह पर जीवन बिताने वाले लोग हैं, ईमान पर चलने वाले लोग हैं. इसीलिए राजनीतिक दलों को लगता है कि उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है. अफसोस तो इस बात का है कि इन राजनीतिक दलों को मुस्लिम समुदाय के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो अपने स्वार्थ की खातिर पूरे समुदाय के भविष्य का सौदा कर लेते हैं. 2014 का चुनाव सिर पर है, इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार ने किस तरह मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर कर दी है.

मनीष कुमार

कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों पर डोरे डालने शुरू कर दिए. पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे कोशिशें हो रही हैं. एक तरफ़ मुस्लिम नेताओं से बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ़ टीवी में प्रचार. स्वयं सोनिया गांधी एवं मनमोहन सिंह द्वारा सम्मेलन करके मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है. चौथी दुनिया लगातार मुसलमानों की समस्याओं और हकीकत पर रिपोर्टें छापता रहा है और हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ यह बताना चाहते हैं कि यूपीए सरकार मुसलमानों को लेकर जितनी भी बातें कह रही है, वे सरासर झूठ हैं और लोगों को गुमराह करने वाली हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चौथी दुनिया ने कांग्रेस के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया था. हमने साबित किया था कि किस तरह चुनाव से पहले सलमान खुर्शीद ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कहकर मुसलमानों के साथ एक भद्दा मजाक किया. कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि वह आरक्षण का मामला कहां दब गया? अब कांग्रेस पार्टी आरक्षण पर क्यों नहीं कुछ बोलती या फिर जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान क्यों नहीं करती? दरअसल, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को धोखा देकर वोट पाने की जुगत में है, इसलिए एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है. चाहे वह सोनिया गांधी हों या मनमोहन सिंह या फिर यूपीए का कोई मंत्री या नेता, सब के सब झूठ बोल रहे हैं.

मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक़ अल्पसंख्यकों का है. जब उन्होंने यह कहा था, तो लगा कि मुसलमानों की समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं. अब चुनाव होने वाले हैं. मनमोहन सिंह की विदाई तय हो चुकी है. आज यही कहा जा सकता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से देश के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयानों में यह बयान सबसे बड़ा छलावा साबित हुआ. वोट न जाने इंसान से क्या-क्या करा लेता है. मनमोहन सिंह ने मुसलमानों के हालात समझने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया था, ताकि यह पता चल सके कि मुसलमानों की हालत क्या है और समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कांग्रेस को आईना दिखाया. सच सामने आ गया. रिपोर्ट ने बताया कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से मुसलमानों की हालत दलितों जैसी है. रिपोर्ट आई और चली गई. अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ़ रिसर्च में होता है. मुसलमानों के मुद्दे वहीं के वहीं पड़े हैं. वही भूख, वही अशिक्षा, वही बेरोज़गारी, वही दंगे और वही लाचारी.

लेकिन कांग्रेस का चरित्र देखिए. चुनाव आते ही हलचल होने लगती है. कांग्रेस ने एक और कमेटी बनाई. इसका नाम था रंगनाथ मिश्र कमीशन. मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर इसकी रिपोर्ट में भी इसी बदहाली को बताया गया और इससे बाहर निकलने की दवा लिखी गई, लेकिन केंद्र सरकार ने तो अपनी फितरत के अनुसार इसे संसद में पेश ही नहीं किया. दो-तीन सालों तक इसकी रिपोर्ट सड़ती रही, लेकिन जब चौथी दुनिया ने पूरी रिपोर्ट को छापा, तो सरकार को इसे संसद में पेश करने को मजबूर होना पड़ा. अफ़सोस की बात यह है कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को जिस तरह से संसद में रखा गया, उससे तो यही लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में घोर विरोधाभास है. सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, क्योंकि उसने रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट के साथ कोई एटीआर नहीं रखी. अब तक देश की जनता को यह पता भी नहीं चल पाया कि सरकार इस रिपोर्ट का क्या करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी का रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर रवैया क्या है. शायद राजनीति में मर्यादा का उल्लंघन कोई अपराध नहीं होता, झूठ बोलने को गुनाह नहीं माना जाता, इसलिए चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार के आला नेता अपनी पीठ थपथपाने वोट के बाज़ार में कूद पड़े.

दिल्ली के विज्ञान भवन में बीती 29 जनवरी को अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास कार्यों से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस हुई. यह कॉन्फ्रेंस बड़े प्रचार-प्रसार के साथ बुलाई गई. पूरे देश में इसे टीवी चैनलों के माध्यम से

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दस वर्षों के वादों का हिसाब चाहिए 03

दिल्ली चलो 05

एनजीओ युग की देन है आम आदमी पार्टी 07

साईं की महिमा 12

मुसलमानों को कांग्रेस ने सिर्फ़ धोखा दिया

पृष्ठ एक का शेष

लाइव दिखाया गया. यहां पहले सोनिया गांधी का भाषण हुआ. उन्होंने मुसलमानों को बहलाने के लिए कई झूठ बोले. सोनिया गांधी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की विभिन्न स्कीमों की वजह से उनके विकास में दस गुना तेजी आई है. अजीब मजाक है. मजे की बात यह है कि यह इतना बड़ा झूठ है कि किसी अख़बार को छापने की हिम्मत नहीं हुई. वैसे सच्चर कमेटी बताती है कि मुसलमानों की हालत दलितों जैसी है और सोनिया गांधी दस गुना विकास का सपना दिखा रही हैं. सोनिया गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मुसलमानों को स्कॉलरशिप की योजनाओं का लाभ हो रहा है और उनकी बेरोज़गारी दूर हो रही है. जब भाषण में झूठ ही बोलना था, तो कम से कम उन्होंने यह भी बता दिया होता कि पिछले 10 सालों में कितने मुस्लिम छात्रों को स्कालरशिप मिली और कितने लोगों को सरकार की नीतियों की वजह से नौकरी मिली. सच्चाई यह है कि यूपीए सरकार वक्त–वक्त पर, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र सिर्फ़ घोषणाएं करती रही, जिनका मकसद मुसलमानों को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें झांसा देकर वोट लेना था. 2006 में प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की भी घोषणा की थी, लेकिन सरकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बदहाली दूर करने में विफल रही.

इसके बावजूद सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का एकमात्र मकसद अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाना है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन किन–किन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है, यह बताना वह भूल गईं. सोनिया ने कहा कि नई रोशनी योजना के तहत बहुत काम हुआ है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए कई क़दम उठाए गए. सोनिया गांधी को शायद हकीकत का पता नहीं है कि 2009 में गठित नई रोशनी योजना, जो 2012 तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही और जब डेढ़ साल पहले शुरू हुई, तो पैसों की बंदरबांट बहुसंख्यक संगठनों के बीच कर दी गई. महिलाओं के लिए नई रोशनी योजना के अंतर्गत ग्यारह राज्यों में 25 संगठनों को धनराशि प्रदान की गई, जिनमें अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संगठनों को दरकिनार कर दिया गया. मुस्लिम संगठनों को यह कहकर पैसा देने से इंकार कर दिया गया कि वे आवश्यक पैमाने पर पूरे नहीं उतर पाए. सोनिया गांधी को तो कम से कम यह ज़रूर पता होगा कि पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने किस कारण से नेशनल एडवाइजरी कमेटी से इस्तीफा दिया था. हर्ष मंदर इस बात से नाराज थे कि योजनाओं को सीधे मुसलमानों से न जोड़कर अल्पसंख्यकों से क्यों जोड़ दिया गया. 10 सालों तक यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों की योजनाओं की बात तो करते रहे, लेकिन आज हालात यह हैं कि यूपीए सरकार एक भी योजना सफल होने का दावा करने की स्थिति में नहीं है.

इस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी के बाद मनमोहन सिंह ने भाषण दिया. उन्होंने वक्फ़ बोर्ड के बारे में बात की और बताया कि उनके उपहार मोर्टगेज एवं एक्सचेंज पर रोक लगा दी गई है, लेकिन वह यह नहीं बता सके कि आज भी वक्फ़ की अनगिनत संपत्तियां सरकारी एवं ग़ैर–सरकारी संस्थाओं के क़ब्जे में क्यों हैं. कई लोगों का मानना है कि वक्फ़ की संपत्तियों का अगर ढंग से सिर्फ़ मैनेजमेंट हो जाए, तो देश के मुसलमानों की समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं. इस पर कोई काम तो हुआ नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह दावा करते हैं कि सच्चर कमेटी के अधिकतर सुझावों पर अमल किया जा चुका है. केंद्रीय मंत्री के रहमान खान का दावा है कि उनके मंत्रालय ने सच्चर कमेटी की 76 अनुशंसाओं में से 73 को लागू कर दिया है. चौथी दुनिया ने जब पड़ताल की, तो पता चला कि आरंभिक 22 अनुशंसाओं में 12 अनुशंसाओं को यूपीए सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है. यूपीए सरकार के मंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं. सरकार ने अपनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में अल्पसंख्यक मंत्रालय को 7 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए थे. मंत्रालय का दावा है कि उसने उन रुपयों में से 6,824 करोड़ रुपये ख़र्च कर दिए हैं. जबकि सच्चाई यह है कि मंत्रालय ने राज्यों को जो राशि आवंटित की थी, उनमें से अधिकतर राशि ख़र्च ही नहीं की गई. हाल में जारी सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 के अनुसार, 2007–2012 के दौरान राज्य सरकारों ने केंद्र की ओर से जारी की गई अल्पसंख्यकों से संबंधित धनराशि में से आधी रकम भी ख़र्च नहीं की. 12 राज्यों ने अल्पसंख्यकों से संबंधित पैसा 50 प्रतिशत से भी कम ख़र्च किया, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्य सूची में ऊपर हैं. कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां पर केवल 20 प्रतिशत राशि ही ख़र्च की गई. सच्चाई यह है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वर्ष 2008–09 में केंद्र सरकार को 33.63 करोड़, 2009–10 में 31.50 करोड़ और 2010–11 में 587 करोड़ रुपये इसलिए वापस लौटा दिए, क्योंकि उन पैसों को ख़र्च ही नहीं किया जा सका. अल्पसंख्यक मंत्रालय की असमर्थता को देखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 90 ज़िलों में बहुक्षेत्रीय विकास के तहत विभिन्न योजनाओं पर ख़र्च करने के लिए केंद्र की ओर से इस मंत्रालय को जो 462.26 करोड़ रुपये दिए गए थे, वे भी इसने केंद्र को लौटा दिए. इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 24 करोड़, मैट्रिक स्कॉलरशिप के 33 करोड़, मैरिट कोमेंस स्कॉलरशिप के 26 करोड़ और वक्फ़ बोर्ड के कंप्यूटरीकरण के 9.3 करोड़ रुपये की धनराशि अल्पसंख्यक मंत्रालय ख़र्च करने में असफल रहा और नतीजतन यह पूरी धनराशि इसे केंद्र को वापस करनी पड़ी. ऐसी स्थिति में, अल्पसंख्यकों, विशेषत: मुसलमानों के विकास के बारे में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के सभी दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं. सच्चर कमेटी ने सबसे अधिक ज़ोर मुसलमानों की अशिक्षा एवं पिछड़ेपन को दूर करने पर दिया था, लेकिन 7 वर्ष बाद भी मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के लिए ठोस क़दम नहीं उठाए गए हैं. सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए अलग से किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था भी अब तक नहीं की जा सकी है.

हक़ीक़त यह है कि पिछले 10 सालों में मुस्लिम समुदाय विकास की मुख्य धारा से बाहर हो चुका है. इसकी कई वजहें हैं. शिक्षा और शिक्षा का स्तर एक बड़ी वजह है. मुस्लिम युवा वर्तमान की प्रतियोगी दुनिया में पिछड़ रहे हैं. निजी क्षेत्र में पक्षपात का भी मामला है. सरकारी क्षेत्र में भी जहां इंटरव्यू का मामला होता है, वहां भी वे भेदभाव के शिकार होते हैं. मीडिया और राजनीति ने ऐसा वातावरण बना दिया है, जिससे मुसलमान मुख्य धारा से विमुख होते जा रहे हैं. सरकार को इन बातों की चिंता नहीं है. मुसलमानों से जुड़े किसी भी आंकड़े पर आप नज़र डालें, तो पता चलता है कि उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक हालत दलितों से ज़्यादा खराब है. मुसलमानों की बस्तियों में स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, रोज़गार के अवसर नहीं हैं. समझने वाली बात यह है कि शिक्षा को लेकर सरकारी आंकड़े भ्रमित करने वाले होते हैं. अपना नाम लिखने और पढ़ने वालों को हम शिक्षित मान लेते हैं. गांवों में रहने वाले मुसलमान मदरसे में पढ़ते हैं. वे शिक्षित लोगों की गिनती में तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पढ़ाई का फायदा नौकरी या रोज़गार दिलाने में नहीं मिलता. ग़रीबी की वजह से मुस्लिम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते. समाज के हर क्षेत्र में देश के मुसलमान पिछड़ रहे हैं और उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है या यूं कहें कि उन्हें सहायता नहीं दी जा रही है. आर्थिक नीतियां ऐसी अपनाई गई हैं, जिनसे मुसलमानों की स्थिति पिछले 10 सालों में बद से बदतर होती जा रही है.

सरकार की नव–उदारवादी आर्थिक नीति ग़रीबों को और ग़रीब बना रही है. गांवों में जीना मुश्किल हो रहा है. मुसलमान ग़रीब हैं. इसलिए वर्तमान अर्थिक नीति का सबसे बुरा प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है. आंकड़े बताते हैं कि छोटे एवं मंझोले कृषक मुसलमानों को जीने के लिए अपनी बची–खुची ज़मीन बेचनी पड़ रही है. वे धीरे–धीरे किसान से मज़दूर बनते जा रहे हैं. अब देश में 60 फ़ीसद से ज़्यादा ग्रामीण मुसलमानों के पास जमीन नहीं है. हैरान करने वाली बात यह है कि हर साल एक फ़ीसद जमीन मुसलमानों के हाथ से खिसक रही है. मुसलमानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. एक तरफ़ गांवों से जमीन जा रही है, तो दूसरी तरफ़ सरकार की नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों का बुरा असर पड़ रहा है. कामगार और अपने हुनर के जरिए पैसा और नाम कमाने वाले व्यापार धीरे–धीरे बंद होने लगे हैं. पारंपरिक व्यापार में ताला लग चुका है. ऐसे लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है. मुसलमान इस बाज़ार संचालित आर्थिक व्यवस्था से बिल्कुल विमुख होता जा रहा है. शहरों में जो रोज़गार भी मिलते हैं, वे सबसे निम्न किस्म के होते हैं. मुसलमान सरकार की नीतियों की वजह से पहले मुख्य धारा से विमुख होते गए और अब पिछले 10 सालों में बदले हुए सामाजिक और आर्थिक परिवेश में वे खुद को तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं. लेकिन दु:ख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी इस पर अफ़सोस जताने और माफी मांगने के बजाय खुद की पीठ ठोंक रही है, खुद को ही सर्टिफिकेट दे रही है.

एक तरफ़ मुस्लिम समुदाय की मूलभूत समस्या है और दूसरी तरफ़ तेजी से बदलता हुआ सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश है. मुसलमानों के सामने ख़तरनाक चुनौती है. ख़तरनाक इसलिए, क्योंकि हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां थोड़ी–सी चूक या देरी पूरे मुस्लिम समुदाय को समाज के सबसे निचले स्तर पर ले जाएगी. दलित विकास की राह पर आ चुके हैं. कई अनुसूचित जातियां काफी आगे निकल चुकी हैं. कई पिछड़ी जातियां ऊंची जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. अल्पसंख्यकों में भी जैन, सिख, ईसाई पारसी वगैरह पहले से ही काफी आगे हैं. सिर्फ़ मुसलमान पिछड़ रहे हैं. ऐसी क्या बात है कि मुस्लिम समुदाय ही अकेला बच गया है, जो अशिक्षा, बेरोज़गारी, बीमारी और अतीत काल की ओर जा रहा है. इसे मुस्लिम समुदाय को ही रोकना होगा. अलग–अलग विचारधाराओं के नाम पर दुकान चलाने वाले राजनीतिक दलों से कोई आशा नहीं करनी चाहिए. चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के साथ मुस्लिम वोटों का सौदा करने वाले सामाजिक और धार्मिक नेताओं से भी आशा नहीं करनी चाहिए. विभिन्न राजनीतिक दलों में मौजूद मुस्लिम नेताओं से भी कोई उम्मीद नहीं है. पुरानी पीढ़ी से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में कई तरह के पूर्वाग्रह मौजूद हैं. वर्तमान समस्याओं से निपटने और भविष्य का नक्शा तैयार करने के लिए नई पीढ़ी, यानी युवा ही आगे आएंगे और मुस्लिम समुदाय को इस दलदल से निकालेंगे. इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है. ■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 49
दिल्ली, 10 फरवरी –16 फरवरी 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022–42296060
	+91–8451050786
	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

भ्रष्टाचार के विरुद्ध सक्रियता

चुनाव नजदीक आने के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की नौकरशाही के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई की रफ्तार तेज दी है. 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लोगों के बीच बातचीत का विषय रही है. इसकी वजह से उन्हें तारीफ भी मिलती रही है. लेकिन, चुनाव का समय नर्वस करने वाला होता है और नीतीश कुमार शायद इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वह पूर्व की सफलता को आसानी से नहीं ले सकते. सूत्रों के अनुसार, आगामी दो महीनों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से राज्य में लगभग 576 नौकरशाहों पर निष्कासन का ख़तरा मंडरा रहा है. राज्य के मुख्य सचिव ए के सिन्हा को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रत्येक सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक करके इन मामलों की समीक्षा और फिर सख्त कार्रवाई करें. शायद यह यूपीए शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार और आम आदमी पार्टी के उदय का ही नतीजा है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया. नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की इस बीमारी को वश में करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते. ■

दबाव में निर्णय

नौकरशाही में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए यूपीए सरकार के स्वयं के मानकों के अनुसार यह एक तेज प्रक्रिया ही मानी जाएगी. उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार के नागरिक उड्डयन महानिदेशक के तौर पर नामित होने के बाद से अन्य अधिकारी कयास लगा रहे हैं. प्रभात कुमार इस साल की शुरुआत से ही इस पद का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे. ऐसा कहा जाता है कि प्रभात कुमार नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह के नजदीकी हैं और उनके विश्वासपात्र भी. इसके अलावा, इस पर निगाह रखने वाले लोग एक अन्य कारण भी बताते हैं कि आख़िर क्यों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने यह निर्णय इतनी जल्दी लिया?

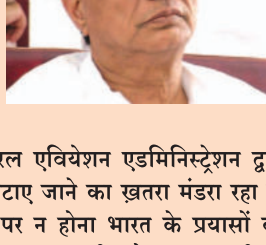

दरअसल, डीजीसीए पर यूएस फेडरल एवियेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सुरक्षा मानकों के आधार पर दर्जा घटाए जाने का ख़तरा मंडरा रहा है. किसी बेहतर व्यक्ति का शीर्ष पद पर न होना भारत के प्रयासों को कमजोर कर सकता है. यह बात इस जल्दबाजी को स्पष्ट करती है. लेकिन, सरकार ने ऐसी ही जल्दबाजी दूसरी नागरिक उड्डयन एजेंसियों के प्रमुखों को नामित करने में नहीं दिखाई. उक्त तीन एजेंसियां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ सिविल एवियेशन सिक्योरिटी और पवन हंस हेलिकॉप्टर्स हैं, जो वर्तमान समय में नौकरशाहों द्वारा अतिरिक्त प्रभार के जरिये ही संचालित हो रही हैं. ■

राजनीतिक लड़ाई

पूर्व गृह सचिव आर के सिंह द्वारा अपने पूर्व बॉस सुशील कुमार शिंदे की निंदा किए जाने के बाद नौकरशाहों के राजनीतिक दलों में जाने का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है. 1975 बैच के आईएएस अधिकारी आर के सिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और उसके बाद से ही उन्होंने शिंदे पर कई आरोप लगाए हैं. इस बात को लेकर भी आश्चर्य जताया जा रहा है कि आर के सिंह द्वारा शिंदे की आलोचना करना कहीं उनके आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से जुड़ा हुआ तो नहीं है. यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आर के सिंह की शिंदे के साथ कभी घनिष्टता नहीं रही. इसके बावजूद आर के सिंह गृह सचिव के पद पर बने रहे. इस दौरान शिंदे ने जम्मू–कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार पर ज़्यादा भरोसा किया, जिन्हें स्पेशल ड्यूटी पर मंत्रालय में लाया गया था, जो बाद में गृह सचिव भी बने. नौकरशाहों के कूलिंग ऑफ पीरियड के अनुसार, जिस प्रकार वे सेवानिवृत्त होने के बाद प्राइवेट सेक्टर नहीं ज्वाइन कर सकते, शायद उसी प्रकार के कुछ नियम उनके लिए राजनीतिक दल ज्वाइन करने को लेकर भी बनाए जा सकते हैं. ■

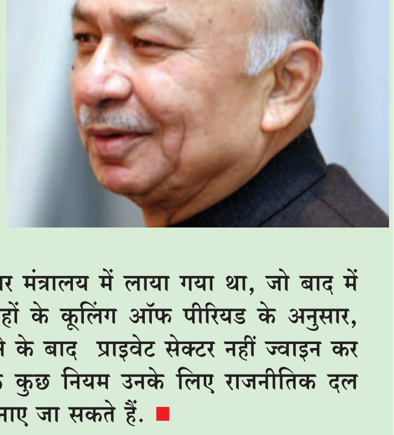

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

शारदा और मनोज संयुक्त सचिव बनेंगे

1990 बैच एवं केरल कैडर की आईएएस अधिकारी शारदा मुरलीधरन को भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल करने के लिए उनका नाम पैनल में शामिल किया गया है. इसी तरह 1994 बैच के आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ जल्द ही जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ संयुक्त सचिव के रूप में जुड़ सकते हैं. पिंगुआ हाल में अध्ययन के लिए अवकाश पर गईं 1984 बैच की आईआईएस अधिकारी साधना राउत का स्थान लेंगे.

बाहरी वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी एस के बाहरी को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है. बाहरी वर्तमान में राजस्थान सरकार के साथ प्रधान महालेखाकार के रूप में कार्यरत हैं.

दिनेश आयुक्त नियुक्त

1983 बैच एवं आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार को कपड़ा मंत्रालय में विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है. अभी हाल में दिनेश को केंद्र सरकार के साथ अपर सचिव अथवा उसके समकक्ष पद के लिए पैनल में शामिल किया गया था. वह बलविंदर कुमार का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल में दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वर्तमान में दिनेश भारतीय खाद्य निगम में कार्यकारी निदेशक (परिवहन) के रूप में कार्यरत हैं.

साथियावथि अपर सचिव बनीं

1982 बैच एवं अरुणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम संघीय प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी एम साथियावथि को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में रिक्त पड़े अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार पद के लिए चुना गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अजीब बात तो यह है कि विज्ञान भवन में आयोजित इस सरकारी कार्यक्रम को सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहा. यही कारण है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण अधिकतर अपने हिमायतियों को दिए. जिसके फलस्वरूप बहुत से संजीदा लोग इसमें न आ सके. जब इस संबंध में चौथी दुनिया ने ऐसे लोगों से इसमें सम्मिलित न होने का कारण पूछा तो उन्होंने छूटते ही कहा कि वह तो कांग्रेस को शो था, अतएव हमलोग क्यों जाते?

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

दस वर्षों के वादों का हिसाब चाहिए

ए यू आसिफ

गत 29 जनवरी 2014 को कांग्रेस के झूठ की पोल एकबार और खुल गई जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं यूपीए के साथ कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के कामों की प्रशंसा के पुल को एक 37 वर्षीय सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने धाराशायी कर दिया. फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है. युनानी चिकित्सक हकीम फहीम बेग के मुंह को पहले कुछ हाथों से जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की गई और जब उन्होंने प्रधानमंत्री से मुख़ातिब होकर बोलना बंद नहीं किया तब उन्हें सुरक्षाकर्मियों के द्वारा प्रधानमंत्री एवं सोनिया गांधी के सामने ही विज्ञान भवन के हॉल बाहर पहुंचा दिया गया. ये सुबह साढ़े दस बजे की घटना है. अवसर था सच्चर समिति की रिपोर्ट में अनुशंसा नंबर 40 के अनुसार मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए वक्फ संपत्ति के विकास के पेशेनजर नेशनल वक्फ डेवेलपमेंट कॉर्पोशन लिमिटेड (नवादको) के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन का. इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी विशिष्ठ अतिथि थीं.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हकीम फहीम बेग ने इस महत्वपूर्ण एवं असाधारण अवसर पर सरकार और सत्तारुढ़ ग्रुप के सबसे जिम्मेदारों के सामने देश के एक जिम्मेदारी शहरी का रोल ही नहीं अदा किया है बल्कि देश व समुदाय का प्रतिनिधित्व भी किया है, दोनों जिम्मेदारों के झूठे दावों की क़लई खोली है और खुले रूप में प्रत्येक व्यक्ति के दिल की बात कह दी है कि अल्पसंख्यक योजनाएं भले वो प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय प्रोग्राम की हों या घनी अल्पसंख्यक आबादी वाले 90 जिलों में मल्टीसेक्टोरल डेवेलपमेंट प्रोग्राम(एमएसडीपी) की, जमीनी सतह पर नहीं पहुंच पा रही हैं, अतएव पीएम एक और अधिक नई योजना को शुरू करने की बजाए पूर्व की योजनाओं पर पहले अमलदरामत करवाएं.

चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए खिड़कीवालान (बल्लीमारान), नई दिल्ली में 15 फरवरी 1977 को आपातकाल की समाप्ति की घोषणा के बाद जन्म लिए और कानपुर विश्वविद्यालय यूनानी चिकित्सा का बीयूएमएस कोर्स करने के बाद अब जाफराबाद में रह रहे और पत्नी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हकीम फहीम बेग पूछने पर कि उन्हें इस अवसर पर यह सबकुछ विचार क्यों और कैसे आया व क्या यह सबकुछ पूर्व नियोजित था, कहा कि 'पूरे देश में 90 घनी अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में दिल्ली के अंदर एक ही जिला नार्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां कांग्रेस के एमएलए चौधरी मतीन अहमद के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र मे जाफराबाद से इनका संबंध है. अतएव मैं यहां मल्टीसेक्टोरल डेवेलपमेंट प्रोग्राम पर अमलदरामत के बारे स्थानीय डिप्टी कमीशनर रेवेन्यू से मालूम करता रहा और प्रधानमंत्री के दफ्तर को भी 150 पत्र लिखे एवं इस सिलसिले में पीएम से मिलकर बात करने का निवेदन भी किया मगर कोई जवाब नहीं आया और फिर 29 जनवरी को श्रीमति सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनने के बाद मुझे अचानक स्वाभाविक तौर पर यह विचार आया कि इन्हीं से मुखातिब हुआ जाए जबकि मैं अवसर मिलने पर उन्हें सौंपने के लिए एक स्मरणपत्र लेकर आया था. प्रधानमंत्री के कहने पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान खां एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने मुझसे बातचीत तो की और वादा किया कि वे लोग उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात करवाएंगे. वैसे अभी तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई है.' ग़ौरतलब है कि उपरोक्त जिले की समस्या दिल्ली विधानसभा में भी उठाई गई थी. इसके अलावा ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वित्तीय सचिव मुशर्रफ हुसैन ने एक अवसर पर जब उस समय की कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्रीमति शीला दीक्षित से इस संबंध में सही स्थिति जाननी चाही तो उन्होंने छूटते ही कहा कि मुस्तफाबाद के कांग्रेसी एमएलए हसन अहमद एमएसडीपी के मामलों के प्रभारी हैं लिहाजा इस संबंध वही बेहतर बता सकते हैं. इस पर मुशर्रफ हुसैन उन्हें तब बताया कि उन्होंने हसन अहमद से इस संबंध में मालूम किया था जिसपर उनका कहना था कि इस जिले में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राशि आई थी परंतु उसे इस्तेमाल न किए जाने पर वापस कर दिया गया. आश्चर्य की बात तो यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उनकी इस बात का कोई उत्तर दिए बिना सभा स्थल से चली गईं.

सच तो यह है कि अल्पसंख्यक स्कीमों के जमीनी सतह तक न पहुंचने की जो बात फहीम बेग ने कही है वह मात्र एक व्यक्ति की प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस और यूपीए की मुखिया से नहीं है बल्कि ये कांग्रेस के इन दो जिम्मेदारों से देश व मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों की बात है. प्रश्न यह है कि क्या ये दोनों जिम्मेदार 10 वर्षों के दो कालों के अंतिम क्षण में भी जागेंगे और अब तक अपने ही किए गए तमाम वादों का विश्लेषण करेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट की वकील इज़हार करीम अंसारी ने चौथी दुनिया से विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'ये कांग्रेस के लिए ख़तरे की घंटी है और इसबात का खुला इशारा है कि कांग्रेस के पांव तले से मुस्लिम अल्पसंख्यक का वोट खिसक चला है क्योंकि अल्पसंख्यकों की योजनाएं जमीनी सतह नहीं पहुंच पा रही हैं. मामला मात्र एक घनी अल्पसंख्यक आबादी वाले ज़िले दिल्ली के नार्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तक एमएसडीपी फंड के पहुंच कर इस्तेमाल होने का नहीं है बल्कि तमाम घनी आबादी वाले जिलों का भी यही हाल है.'

अजीब बात तो यह है कि विज्ञान भवन में आयोजित इस सरकारी कार्यक्रम को सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी

लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहा. यही कारण है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण अधिकतर अपने हिमायतियों को दिए. जिसके फलस्वरूप बहुत से संजीदा लोग इसमें न आ सके. जब इस संबंध में चौथी दुनिया ने ऐसे लोगों से इसमें सम्मिलित न होने का कारण पूछा तो उन्होंने छूटते ही कहा कि वह तो कांग्रेस को शो था, अतएव हमलोग क्यों जाते? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ दिल्ली के अध्यक्ष इंजिनियर इमदादुल्लाह जौहर ने कहा कि शायद यही कारण कि मेरे सामने ही निमंत्रण पत्र बांटे गए लेकिन मुझे नहीं दिया गया क्योंकि मैं कांग्रेस का हिमायती नहीं था. इसीलिए गैरसंजीदा लोग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आ गए जिन्हें इस बात की चिंता ही नहीं थी कि नेशनल वक्फ डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मतलब और मक़सद क्या है और इस अवसर पर फहीम बेग ने अल्पसंख्यकों की योजनाओं की जमीनी सतह तक न पहंचने का मसला क्यों उठा दिया बल्कि इसके विपरीत आधे घंटे के प्रोग्राम के समाप्त होते ही ' हाई टी ' पर इस तरह टूट पड़े और फ्रायउ चिकन और फिश को लाते समय इस तरह लूटने लगे कि शायद उनके लिए यही महत्वपूर्ण था जिसके फलस्वरूप वहां उपस्थित मुस्लिम अल्पसंख्यक का सम्माननीय एवं संजीदा तबक़ा महरूम रहा. मगर कांग्रेस की रणनीति काम न आई और फहीम बेग ने मुल्क की सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए कटु सत्य को सामने ला दिया. कार्यक्रम के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लग गई और इस सिलसिले में उर्दू मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की. यही कारण है कि दो–तीन अखबारों इंकलाब, ख़बरें एवं हिंद न्यूज को छोड़कर सभी उर्दू अखबारों ने इस खबर को डाउन प्ले किया. पूछने पर कुछ उर्दू पत्रकारों ने चौथी दुनिया को नाम न लेने की शर्त पर बताया कि इस संबंध में मौखिक निर्देश दिए गए थे कि सावधानी से काम करो वरना 'धन्यवाद' के लिए मिलने वाले पुर्ण पृष्ट के इश्तहार से वंचित कर दिए जाओगे. यहां यह भी गौरतलब है कि 31 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग के तुरंत बाद अल्पंसख्यक मंत्री के. रहमान खां ने कुछ पत्रकारों को अपने निवास पर बात करने के लिए बुलाया था और उनसे विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि फहीम बेग को 29 जनवरी की कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने की क्या आवश्यकता थी? इस अवसर पर दिल्ली एवं लखनऊ से एकसाथ छप रहे एक उर्दू समाचार पत्र के संवाददाता ने उपरोक्त कॉन्फ्रेंस की खबर को लीड के तौर पर छापने एवं फहीम बेग की खबर को डाउन प्ले करने का भी क्रेडिट लिया. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर क्या–क्या हो रहा है? मगर इससे इसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ खुशामद पसंद लोगों का जमघट है और अंतिम समय में ये क्या तीर मार लेगी?

थिंक टैंक इंस्टिट्यूट ऑफ ऑबजेक्टिव स्टडीज़(आइओएस) के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम कहते हैं कि' यह क्षण बडा ही ऐतिहासिक था सच्चर रिपोर्ट की एक अनुशंसा पर अमल करते हुए सरकार ने नवादको का उद्घाटन किया था जो कि एक बहुत बड़ी अल्पसंख्यक योजना जैसी है. इस अवसर पर हकीम फहीम बेग ने जो कुछ कहा कि मुस्लिमों की दुखती हुई आवाज है और यही कारण है कि इसे सुनते ही सारे लोगों के कान और आंख खुल गए परंतु उनकी बात के लंबे हो जाने से संजीदा वातावरण डिस्टर्ब जरूर हुआ. अवएव उन्हें अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहिए था.'

अल्पसंख्यकों को कांग्रेस की ओर से लॉलीपॉप देकर उनके असल मुद्दों से ध्यान हटाने की संसदीय चुनाव से ठीक पहले नवादको जैसी ये अकेली एवं एकमात्र चाल नहीं है. ये इस तरह की चाल हमेश चलती रही है और इस चाल के तीसरे दिन भी सोनिया गांधी ने बिहार के पशमांदा इलाके किशनगंज जो कि दिल्ली के नार्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरह 90 घनी अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में शामिल है, अलीगढ मुस्लिम युनिवर्सिटी का शिलान्यास करने गई. संसदीय चुनाव से ठीक पहले यह भी एक चाल थी जबकि ये समस्या एक लंबे समय से चली आ रही थी. इस अवसर पर दूसरे रोज उर्दू अखबारों में एक फरवरी को छपी तस्वीर में विशेष रूप से एएमयू सेंटर का उदघाटन करते हुए उनके साथ किशनगंज से कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार निर्वाचित लोकसभा सदस्य एवं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना असरारुल हक क़ासमी को दिखाया गया. ये भी अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा एक पैगाम था जो कि सरासर झूठ था क्योंकि ये वही मौलाना साहब हैं जो कि कांग्रेस के टिकट पर 2009 के संसदीय चुनाव में सफल हुए शायद बिहार के अकेले व्यक्ति थे और तमाम मांगों के बावजूद उन्हें उस समय बने केंद्रीय मंत्रीमंडल में सम्मिलित नहीं किया गया था. उन्हें सामाजिक और शैक्षिक कामों के दिलचस्पी के तकाजा के तौर पर पिछले पांच वर्षों में जिन्हें कोई अहम जिम्मेदारी भी नहीं दी गई थी और जिसके कारण संसदीय क्षेत्र के वोटर कांग्रेस से सख्त नाराज चल रहे थे.

एएमयू सेंटर की चर्चा होते ही स्वाभाविक तौर पर एएमयू के अल्पसंख्यक के दर्जे के संबंध में 2005 में कांग्रेस की ओर से किए गए वादे याद आ जाते हैं. उस समय जब एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अंतिम निर्णय आने के समय तक रोक दिया गया था. तब उन दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्व. अर्जुन सिंह ने वादा किया था कि यह मामला अदालत में है परंतु सरकार इसकी सुनवाई में तेजी लाने को कहेगी और जरूरत पडने पर आवश्यक कारांवई करके इसके अल्पसंख्यक दर्जे को फिर से बहाल करवाएगी और वह इसके लिए वचनबद्ध है. इस वादे को भी नौ वर्ष गुजर गए और वादे वादे ही रह गए. प्रश्न यह है कि कांग्रेस जब अब एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा ही बहाल न कर सकी है तो वह किशनगंज में एएमयू सेंटर स्थापित करने अल्पसंख्यकों के लिए किया गया काम कह कर क्यों क्रेडिट ले रही है? यह भी सच कि यह सब कुछ भी धोखा ही है.

जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने पिछले दस वर्षों में सिर्फ धोखा ही दिया है लिहाजा यह बात बिल्कुल मुनासिब है कि अल्पसंख्कों को मात्र ऐलान ही नहीं बल्कि दस वर्षो के वादों का हिसाब चाहिए. सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने काम के इस हिसाब को देने के लिए तैयार है? ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

अकेले तो यह देश बना नहीं है,
हमने एक-दूसरे का साथ दिया,
तभी तो बना यह भारत।

कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया,
देश को तरक्की की राह पर,
तो क्यूं न कहें, हम सबने मिलकर
बनाया यह भारत।

65वां गणतंत्र दिवस

davp 22202/13/0101/1314

अलागिरी चूंकि परिवार से ही हैं और पार्टी प्रमुख पद पर अपना बराबर का हक़ समझते हैं, इसलिए उनके तेवर उग्र हैं. ठीक एक वर्ष पहले भी वह इसी बात को लेकर आक्रोशित हुए थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री एवं संगठन सचिव पद से इस्तीफ़ा दे दिया था तथा कहा था कि द्रमुक कोई शंकराचार्य का मठ नहीं है, जहां उत्तराधिकारी की घोषणा करनी हो. 2जी मामले में भी दोनों भाइयों के बीच तब मतभेद साफ़ दिखाई दिए थे, जब कनिमोझी की गिरफ्त–ारी पर अलागिरी चुपचाप रहे, जबकि करुणानिधि और स्टालिन तिहाड़ जेल में कनिमोझी से कई बार मिलकर आए.

अलागिरी के अलगाव की वजह

नीरज सिंह

दक्षिण भारतीय राजनीति एक बार फिर चर्चा में है. द्रविण मुनेत्र कषगम के प्रमुख एम करुणानिधि ने अपने बेटे एमके अलागिरी को पार्टी से निकाल दिया, तो अलागिरी विद्रोही तेवर अपनाते हुए अपनी ही पार्टी को निपटाने और पार्टी के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार की कलई खोलने की घोषणा कर रहे हैं. वास्तव में यह राजनीतिक उलटफेर कई सवाल खड़े करता है. आख़िर अपने ही पिता और अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ अलागिरी क्यों उतर आए हैं? सवाल यह भी है कि अपने ही बेटे को आख़िर करुणानिधि पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं. इन सभी सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें पहले करुणानिधि के परिवार और द्रमुक की राजनीति को समझने की ज़रूरत है.

द्रमुक परिवार में चल रही राजनीतिक उत्तराधिकार की लड़ाई ढाई दशक पुरानी है. करुणानिधि ने चार शादियां की हैं. राज्य की विधानसभा और देश की संसद में कुल मिलाकर इस परिवार के 16 प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें उनके पुत्र-पुत्रियां, दामाद, उनकी पत्नी की ओर के रिश्तेदार शामिल हैं. एमके अलागिरी एवं एमके स्टालिन एक ही मां दयालु अम्मल के बेटे हैं. दक्षिण और खासकर, इस परिवार की राजनीति को क़रीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि करुणानिधि अपने छोटे बेटे स्टालिन को शुरू से ही ज़्यादा प्यार करते थे. छोटे भाई के प्रति पिता का ज़्यादा प्यार बड़े बेटे अलागिरी को हमेशा खटकता था. थलपति (पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एमके स्टालिन इसी नाम से लोकप्रिय हैं) न केवल पिता, बल्कि द्रमुक कार्यकर्ताओं के बीच भी अलागिरी की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय हैं. शायद यही वजह है कि करुणानिधि हमेशा चाहते रहे कि स्टालिन ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बने. लेकिन उनके सामने भी वही समस्या थी, जो उत्तराधिकार को लेकर दूसरे राजनीतिक परिवारों में दिखाई देती है. पहले भी ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक दिग्गजों के परिवारों में उत्तराधिकार को लेकर बंटवारे हुए हैं. हरियाणा में ऐसी ही मुश्किलें चौधरी देवीलाल को आई थीं, जिन्हें अपने बेटे रणजीत सिंह और ओम प्रकाश में से किसी योग्य को अपनी विरासत सौंपनी थी. ऐसी ही दिक्कत कुछ दिनों बाद ओम प्रकाश चौटाला को आएगी, क्योंकि उनके भी दो बेटे अजय और अभय हैं. हरियाणा में ही भजन लाल और बंसी लाल भी ऐसी ही मुश्किलों से दो-चार हो चुके हैं. महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को भी कमोबेश ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने पार्टी की कमान अपने भतीजे के बजाय बेटे को सौंप दी, तो राज ठाकरे बगावत पर उतर आए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली. लालू प्रसाद यादव के सामने भी यह संकट है कि वह अपनी राजनीतिक कमान किसे दें, तेज प्रताप को या तेजस्वी को.

बहरहाल, अलागिरी किसी भी क़ीमत पर नहीं चाहते थे कि उत्तराधिकार स्टालिन को मिले, इसीलिए उन्होंने हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की, जो स्टालिन के पक्ष में जा रही थी. करुणानिधि के भतीजे दिवंगत मुरासोली मारन के अख़बार दिनाकरन ने 2007 में एक सर्वे छापा, जिसके मुताबिक, करुणानिधि के उत्तराधिकारी के रूप में जनता की पहली पसंद स्टालिन थे. इससे नाराज होकर अलागिरी समर्थकों ने अख़बार के दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग मारे भी गए. इस घटना के बाद करुणानिधि और मारन परिवार के संबंध भी काफी खराब हुए. दयानिधि मारन को उन्होंने संचार मंत्रालय से हटवा दिया और उनकी जगह ए राजा को मंत्री बनाया. इस घटना के बाद करुणानिधि ने कलानिधि मारन से बात करना भी बंद कर दिया.

एक सवाल यह भी है कि आख़िर करुणानिधि स्टालिन और अलागिरी में स्टालिन को ही ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं. करुणानिधि स्टालिन की सांगठनिक क्षमता के हमेशा ही कायल रहे हैं. ऐसा कहा जाता है कि अपने बड़बोलेपन के चलते अलागिरी कई बार राजनीतिक भूलें कर बैठते हैं, जबकि अपेक्षाकृत स्टालिन का पार्टी कैडर पर व्यापक नियंत्रण है. उनके नेतृत्व में अन्नाद्रमुक सरकार के ख़िलाफ़ तमिलनाडु में चलाया गया जेल भरो आंदोलन काफी सफल रहा था. यही वजह है कि 1990 के मध्य में करुणानिधि ने उन्हें (स्टालिन को) चेन्नई का मेयर बनाया और फिर पूर्ववर्ती द्रमुक सरकार के दौरान स्टालिन को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. हालांकि, तब उत्तराधिकारी संबंधी किसी घोषणा से करुणानिधि ने परहेज किया था. बाद में परिस्थितियां ऐसी बनीं कि करुणानिधि के सामने एक विकल्प के तौर पर स्टालिन ही बचे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के रूप में एमके अलागिरी की पहचान एक निष्क्रिय मंत्री की थी और उनके बेटे दुरई दयानिधि करोड़ों रुपये के अवैध खनन के मामलों का सामना कर रहे थे. दूसरी ओर बेटी कनिमोझी 2जी मामले में अपनी साख गंवा चुकी हैं और मारन परिवार भी इस समय द्रमुक प्रमुख के ज़्यादा क़रीब नहीं नज़र आ रहा है. साथ ही पार्टी में भी ऐसा कोई चेहरा नहीं, जिसकी राज्य भर में धमक हो और वह अपने बलबूते चुनाव जिताने की क्षमता रखता हो.

करुणानिधि की घोषणा से पार्टी में विरोध का स्वर उनके बेटे अलागिरी ने ही उठाया है. उनके अलावा कोई और विरोध नहीं कर रहा है. इसकी भी वजह है. पार्टी के बाकी नेता पार्टी प्रमुख पद का सपना ही नहीं देखते, क्योंकि दल को पारिवारिक व्यवसाय की भांति जो चलाया जाता है. अलागिरी चूंकि परिवार से ही हैं और पार्टी प्रमुख पद पर अपना बराबर का हक़ समझते हैं, इसलिए उनके तेवर उग्र हैं. ठीक एक वर्ष पहले भी वह इसी बात को लेकर आक्रोशित हुए थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री एवं संगठन सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था तथा कहा था कि द्रमुक कोई शंकराचार्य का मठ नहीं है, जहां उत्तराधिकारी की घोषणा करनी हो. 2जी मामले में भी दोनों भाइयों के बीच तब मतभेद साफ़ दिखाई दिए थे, जब कनिमोझी की गिरफ्तारी पर अलागिरी चुपचाप रहे, जबकि करुणानिधि और स्टालिन तिहाड़ जेल में कनिमोझी से कई बार मिलकर आए. अलागिरी ने तब पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया था. इससे करुणानिधि तिलमिलाए भी, नाराज भी बहुत हुए थे, पर उनकी पत्नी दयालु अम्मल ने उन्हें समझाया कि फिलहाल वह ऐसा न करें, वरना दोनों बेटों के बीच टकराव बढ़ जाएगा. यही वजह है कि तब करुणानिधि मान गए थे और उन्होंने स्टालिन को उत्तराधिकारी बनाने की अपनी घोषणा फिलहाल स्थगित कर दी थी.

तब एक योजना के तहत करुणानिधि ने अलागिरी को चेन्नई से दूर रखने के लिए दक्षिणी तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी. इसके लिए उन्हें खास तौर से संगठन का सचिव बनाया गया, लेकिन अलागिरी की वहां भी नहीं चली. जब स्टालिन ने विजयकांत के साथ सीटों के तालमेल की बात करनी शुरू की, तो अलागिरी ने फिर उनका विरोध करना शुरू कर दिया. उन्हें लगा कि विजयकांत के साथ जाने से दक्षिण तमिलनाडु में उनका आधार साफ़ हो जाएगा. उन्हें इसमें अपने भाई स्टालिन की साजिश नज़र आई. लिहाजा इस गठबंधन को पलीता लगाने के लिए उन्होंने विजयकांत के ख़िलाफ़ फिर बयानबाजी शुरू कर दी. जवाब में विजयकांत ने कहा कि वह 2011 में ही द्रमुक के साथ तालमेल करने का मन बना चुके थे, पर अलागिरी के कारण उन्होंने अपना फ़ैसला बदल दिया.

स्टालिन ऐसे ही एक मौक़े की तलाश में थे. उन्होंने पहले से ही अलागिरी के समर्थकों को तोड़ना शुरू कर दिया था और पार्टी की मदुरै इकाई भी भंग कर दी थी. अलागिरी की बयानबाजी के बाद अपनी बहन कनिमोझी के साथ उन्होंने करुणानिधि से मुलाकात करके कहा कि अब पानी सिर से गुजर रहा है. अगर लोकसभा चुनाव भी हार गए, तो अगली सरकार और ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगी. मालूम हो कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में ए. राजा एवं कनिमोझी, दोनों ही जेल जा चुके हैं और मामला अदालत में चल रहा है. अक्सर दोनों बेटों में समझौता कराने वाली दयालु अम्मल इन दिनों काफी बीमार चल रही हैं, इसलिए फिलहाल समझौते की कोई तस्वीर भी नज़र नहीं आई और करुणानिधि ने स्टालिन को अपना उत्तराधिकार सौंपने की घोषणा कर दी. अलागिरी के बगावती तेवर जारी हैं. उनका दावा है कि उनके पिता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इसके जवाब में करुणानिधि का यह बयान भी समझ से परे हैं कि उन्होंने अलागिरी को पार्टी से इसलिए निकाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि तीन महीने में स्टालिन की मौत हो जाएगी. भला एक बाप यह कैसे सुन सकता है.

जो भी हो, करुणानिधि ने जिस पारिवारिक राजनीतिक वटवृक्ष को मजबूती दे रखी थी, वह अब कमजोर पड़ रहा है. अब देखना यह है कि अलागिरी हर बार की तरह किसी ऑफर के साथ पार्टी में लौट आते हैं या फिर बगावत के साथ द्रमुक के लिए घातक साबित होते हैं. ■

स्टालीन

आलागिरि

feedback@chauthiduniya.com

चुनावी चक्रव्यूह में फंसे समाजवादी

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी को टिकट बंटवारे में छींके आने लगी हैं. साल भर पूर्व जिन नेताओं को लोकसभा का टिकट दिया गया था, चुनावी संध्या में उनमें से कई के टिकट कट गए. पहले सपा नेतृत्व ने वफादार समाजवादियों को टिकट थमाया था, लेकिन अब प्रत्याशियों की योग्यता का निर्धारण वफादारी की बजाय चुनाव जीतने की क्षमता का आकलन करके किया जा रहा है. अन्य दलों से आने वाले नेताओं के अलावा पुराने समाजवादियों के लिए भी पार्टी ने टिकट के दरवाजे खोल रखे हैं. सारा दारोमदार मुलायम सिंह ने अपने कंधों पर ले रखा है. उनकी टीम प्रत्याशियों की तो समीक्षा कर ही रही है, इसके अलावा ऐसे नेताओं की तलाश में भी लगी है, जो स्वयं चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों, साथ ही वे आसपास के जिलों की चुनावी तस्वीर भी बदल सकें. सपा में अभी तक क़रीब डेढ़ दर्जन प्रत्याशी बदले जा चुके हैं. सपा सरकार के मंत्री राजकिशोर, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी और दुर्गा प्रसाद यादव, जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इस बार मैदान में नहीं दिखेंगे. ये सभी नेता 2009 में लोकसभा चुनाव हार गए थे. इसके अलावा 2009 में लोकसभा लड़े, लेकिन हार गए सपा नेताओं, महराजगंज से अजीत मणि, बांसगांव से शारदा देवी, डुमरिया से माता प्रसाद, घोसी से अरशद जमाल एवं सलेमपुर से हरिकेवल प्रसाद भी साइकिल की सवारी करते नहीं दिखेंगे. टिकट बदलने के बाद पार्टी में नेतृत्व के ख़िलाफ़ आक्रोश की चिंगारी साफ़ दिखाई पड़ रही है. आलाकमान द्वारा कुछ नेताओं को लालबत्तियां बांटकर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें ज़रूर की गईं, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. बागी नेताओं द्वारा कहीं खुलकर, तो कहीं भीतरघात करके सपा प्रत्याशियों को कमजोर किया जा रहा है.

सबसे ताजा बदलाव और बगावत के सुर सहारनपुर में देखने को मिले, जो कई मायने में सपा के लिए ख़तरे की घंटी साबित हो सकते हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज, लेकिन सजायाफ्ता नेता सांसद रशीद मसूद, जिनका पूर्व में कांग्रेसीकरण हो गया था, की ताकत पहचानते हुए सपा ने उनके बेटे सादान मसूद को सहारनपुर से मैदान में उतारा है. पहले यहां से रशीद मसूद के भतीजे इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे थे. इमरान के कारण ही रशीद ने सपा से किनारा कर लिया था. मसूद कहते भी हैं कि उनका नेताजी से कोई मतभेद नहीं था, बस इमरान को लेकर थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था. इमरान अब नया ठिकाना तलाश रहे हैं. सुल्तानपुर में हाल में प्रत्याशी बदला गया है. यहां का बदलाव भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सपा ने यहां शकील अहमद का टिकट काटकर बाहुबली अतीक अहमद को अपना नया प्रत्याशी घोषित किया है. अतीक अहमद बसपा राज में भागे-भागे फिर रहे थे. यहां तक कि उन्हें यूपी छोड़ना पड़ गया था. टिकट मिलते ही अतीक ने पूरे दमखम के साथ सुल्तानपुर में एंट्री की. उधर टिकट कटने से नाराज शकील अहमद विरोध के रास्ते पर चल पड़े. पानी सिर से ऊपर होता देख अतीक को वहां से श्रावस्ती चलता कर दिया गया और शकील फिर टिकट पा गए. भाजपा ने यहां से वरुण गांधी को उतारने का मन बनाया है, तो बसपा ने बाहुबली पवन पांडेय को मैदान में उतारा है.

सपा में बगावत के सुर पूर्वांचल की लालगंज सीट पर भी उभरे. आजमगढ़ जिले में पड़ने वाली इस संसदीय सीट से पूर्व सांसद दारोगा प्रसाद सरोज को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बाद में विधायक बेचई सरोज को प्रत्याशी बना दिया गया. दारोगा का टिकट कटा, तो उनके समर्थक विरोध पर उतर आए. दो माह तक विरोध का सिलसिला चलता रहा, फिर भी बात नहीं बनी, तो सरोज भगवा रंग में रंग गए. जौनपुर में भी सपा की अंदरूनी राजनीति का पारा डॉ. केपी यादव का टिकट कटने से चढ़ा हुआ है. उन्हें नवंबर 2012 में प्रत्याशी घोषित किया गया था. वह एक साल तक सड़कों पर संघर्ष करते रहे. फिर अचानक उनकी जगह कैबिनेट मंत्री एवं कद्दावर नेता पारसनाथ यादव को उम्मीदवार बना दिया गया. विरोध में डॉ. केपी यादव के समर्थकों ने हंगामा किया. डॉक्टर साहब कहते हैं, टिकट कटने के बाद हफ्ते भर तक मैं लखनऊ में मुलायम सिंह से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बात नहीं बनी. 27 सालों से नेताजी से जुड़ा हूं. 36 बार गिरफ्तार हुआ, 12 बार जेल गया. 2002 में विधानसभा टिकट काटा गया, तो नेताजी ने मजबूरी बताई. 2007 में भी षड्यंत्र की राजनीति का शिकार हो गया. एक साल से तैयारियों में जुटा रहा, लेकिन बिना पूछे टिकट काट दिया गया. कानपुर में किसी पुराने समाजवादी की जगह हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव को लड़ाए जाने का जबर्दस्त विरोध हो रहा है. राजू आज जनता के बीच अपनी पैठ भी नहीं बना पा रहे हैं.

ऐसे ही हालात फर्रुखाबाद के हैं. यहां भी प्रत्याशी बदलना सपा नेतृत्व को भारी पड़ रहा है. यहां राज्यमंत्री नरेंद्र यादव के तेवर तीखे हैं. उनके समर्थक मंत्री पुत्र का टिकट कटने से आहत हैं. सचिन का टिकट काटकर अलीगंज (एटा) के विधायक रामेश्वर यादव को प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है, लेकिन सचिन का चुनाव अभियान बदस्तूर चल रहा है. जबकि पिछले दिनों वह पार्टी के प्रमुख नेताओं के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए थे. सचिन भी बगावत कर सकते हैं, बस पेंच सचिन के पिता का पड़ रहा है, जो अखिलेश सरकार में मंत्री हैं और अपनी लालबत्ती नहीं खोना चाहते. मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर काफी सतर्क सपा आलाकमान अन्य दलों के सांसदों को भी अपने पाले में खींच रहा है. हाथरस से राष्ट्रीय लोकदल की सांसद सारिका सिंह बघेल और अमरोहा से निर्दलीय सांसद देवेंद्र नागपाल को पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया है. सारिका को तो आगरा से टिकट भी दे दिया गया है. संभल के बसपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क भी सपा का दामन थामने की फिराक में हैं. बसपा से बर्क को टिकट की हरी झंडी नहीं मिल पाई थी. मुजफ्फरनगर के बसपा सांसद कादिर राणा के प्रति भी सपा नरम रुख अख्तियार किए हुए है. वह भी सपा से टिकट की चाहत पाले हुए हैं. सपा प्रमुख पूरे हालात पर नज़र रखे हुए हैं. बगावत वाली सीटों पर मुलायम सिंह स्वयं डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं. इसके लिए प्रभारियों से रिपोर्ट ली जा रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बगावत स्थानीय स्तर पर चल रही है, शीर्ष नेतृत्व से कोई खफा नहीं है. हां, इसका नुकसान ज़रूर पार्टी को उठाना पड़ सकता है.

टिकट बंटवारे को लेकर फंसते जा रहे समाजवादी नेतृत्व के लिए मुसीबत कई मोर्चों पर मुंह फैलाए खड़ी है. पार्टी से विद्रोह करने वालों से निपटना भी उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. सपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बगावत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सोमपाल शास्त्री का चुनाव लड़ने से इंकार, 2009 के लोकसभा चुनाव में साइकिल की सवारी करने वाले भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का भगवाकरण, मुलायम सरकार में मंत्री रहे देवरिया के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद और हरदोई के पूर्व विधायक सतीश वर्मा का भाजपा में जाना भी सपा के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

ममता की हुंकार

दिल्ली चलो

भारतीय राजनीति में वैसे तो दिल्ली चलो का नारा काफ़ी पुराना है, लेकिन आम चुनाव के मौक़े पर यह नारा नेताओं के बीच लोकप्रिय हो जाता है. हालांकि, इस बार दिल्ली चलने का आह्वान बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने किया है. इसमें कोई शक नहीं कि ममता केंद्र की राजनीति में किंग मेकर बनना चाहती हैं. क्या उनका यह ख़्वाब पूरा होगा और क्या वह देश की प्रधानमंत्री बन पाएंगी, यह देखना दिलचस्प होगा?

नवीन चौहान

आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह के गठबंधन को ख़ारिज करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली चलो के नारे के साथ चुनाव अभियान की शुरूआत कर दी है. पिछले दिनों कोलकाता के परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम देश में न तो वंशवादियों की सरकार चाहते हैं न ही दंगाइयों की. लिहाज़ा वह एकला चलो की नीति पर अमल करेंगी और देश भर में टीएमसी उम्मीदवारों को खड़ा करेंगी. उन्होंने क्षेत्रीय दलों से एक बार फिर संघीय मोर्चा बनाने का आह्वान किया है. साथ ही उन्होंने यह बात भी साफ़ कर दी है कि बंगाल केंद्र में नई सरकार के गठन में प्रमुख भूमिका अदा करेगा. ममता की इस घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं. ममता के मुताबिक़, इस बार दिल्ली के लिए भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों को सीधी चुनौती देंगे. तृणमूल कांग्रेस को एकमात्र विकल्प बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और माकपा के ख़िलाफ़ उनकी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा. उनके अनुसार, तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार के विरुद्ध सदैव संघर्षरत है. ममता बनर्जी ने यह दोहराया कि केंद्र में ईमानदार और लोकहित के लिए काम करने वाली सरकार का गठन करना ही उनका मक़सद है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस केंद्र में ऐसे लोगों की सरकार नहीं चाहती, जो कि दंगाइयों को प्रोत्साहित करे. उनके अनुसार, आने वाले दिनों में बंगाल ही देश को रास्ता दिखाएगा. ममता ने आगामी चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को हराने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस का विकल्प भाजपा नहीं है.

एक तरफ जब देश में सादगी, शुचिता और सुशासन की बात चल रही है, वहीं लोगों का ध्यान सूती साड़ी और स्लीपर पहनने वाली ममता बनर्जी की ओर नहीं जा रहा है. ममता बनर्जी ने संघर्ष करके न सिर्फ माकपा की बुनियाद कमज़ोर की, बल्कि तीन दशकों से बंगाल की राजनीति में क़ाबिज माकपा को सत्ता से भी उखाड़ फेंका. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ममता बनर्जी साधारण से मकान में रहती है और कहीं आने-जाने के लिए छोटी कार का इस्तेमाल करती हैं. हालांकि, मीडिया को ममता बनर्जी की यह सादगी नज़र नहीं आती.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उनकी ग़लत नीतियों की वजह से ही आज देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है. उनके मुताबिक़, तृणमूल कांग्रेस का संघर्ष भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है.

उन्होंने बताया कि केंद्र में अगली सरकार के गठन में तृणमूल कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे बंगाल में अधिक सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करें. ग़ौरतलब है कि पिछले दिनों बंगाल में संपन्न पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भी तृणमूल कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी. इस जीत का असर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में साफ देखा जा सकता है. सियासी जानकारों की मानें, तो अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अधिक सीटें जीतने में कामयाब होती हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका किंगमेकर की होगी. ग़ौरतलब है कि लोकसभा सीटों के लिहाज़ से पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद तीसरे नंबर पर आता है. बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं. वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं. यूपीए सरकार से बाहर जाने और फंड की कमी के बावजूद ममता बनर्जी बंगाल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब हुई हैं. ममता यह बात बख़ूबी जानती हैं कि केंद्र सरकार में दख़ल रखे बिना, वह पश्चिम बंगाल को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने का सपना पूरा नहीं कर सकतीं. पंचायत और नगर निकाय चुनावों में मिली जीत यह बताने के लिए काफ़ी है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जड़ें और मज़बूत हुईं हैं. ममता ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल आज जो सोचता है, भारत उसे कल सोचता है. बंगाल एक बार फिर से देश का नेतृत्व करेगा. यदि राज्य को शक्तिशाली बनाना है, तो प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतना ज़रूरी है.

उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी आगामी लोकसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में भी तृणमूल उम्मीदवार उतारने की बात कही है. याद रहे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी तृणमूल कांग्रेस ने 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें मथुरा ज़िले की माट सीट से श्याम सुंदर शर्मा विजयी रहे थे. मणिपुर,अरुणाचल प्रदेश और असम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद तृणमूल कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. वैसे तो तृणमूल कांग्रेस का संगठन देश के कई राज्यों में है. यह अलग बात है कि उसके उम्मीदवार जीत हासिल करने में असफल रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में अग्रसर है. लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने जो राजनीतिक संकेत दिए हैं, उसके काफी मायने हैं. अलबत्ता लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में बनने वाली नई सरकार में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

असम में हिंदीभाषियों पर हमला

शांति प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश

पिछले दिनों नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के हथियारबंद लोगों ने कोकराझार ज़िले में बस से शिलांग जा रहे आठ हिंदीभाषियों की हत्या कर दी. असम में उत्तर भारतीय लोगों को ऐसे वक्त पर निशाना बनाया गया है, जब भारत सरकार और अलगाववादियों के बीच शांति वार्ता चल रही है. क्या है इस हमले के पीछे की रणनीति? क्या असम में जारी युद्ध विराम पर इसका कोई असर पड़ेगा? पेश है इसी मसले पर चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट...

अभिषेक रंजन सिंह

अमूमन पूर्वोत्तर में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समय हिंसक घटनाओं में वृद्धि हो जाती है. बीते दिनों कोकराझार में हिंदीभाषियों की हत्या की ज़िम्मेदारी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (संगविजित गुट) ने ली, जो भारत सरकार के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता के सख्त ख़िलाफ़ है. हालांकि, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (रंजन दैमारी गुट) इन दिनों भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल है. एनडीएफबी (एस) के कमांडर इन चीफ संगविजित पर असम पुलिस ने दस लाख रुपये का ईनाम घोषित कर रखा है. असम में हिंसा का समर्थन करने वाले संगविजित का कहना है कि सेना राज्य में दमनचक्र चला रही है, इसलिए उनके कैडर हिंदीभाषियों को निशाना बना रहे हैं.

हालांकि, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (रंजन दैमारी गुट) कुछ साल पहले तक भारत सरकार से शांति वार्ता के सख्त ख़िलाफ़ था. रंजन दैमारी को असम में हुए कई हमलों का ज़िम्मेदार भी माना जाता था. ग़ौरतलब है कि एनडीएफबी के रंजन दैमारी गुट ने 30 अक्टूबर, 2008 को असम में सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम दिया था, जिसमें सौ लोगों की मौत हो गई थी. उक्त बम धमाके गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगईगांव और बारपेटा में हुए थे. इस घटना के बाद रंजन दैमारी को वर्ष 2009 में बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक़ तत्कालीन शेख हसीना सरकार ने उसे भारत को सौंप दिया था. कई साल जेल में बंद रहने के बाद जून 2013 में आख़िरकार रंजन दैमारी को जमानत मिल गई. अपनी रिहाई के बाद रंजन दैमारी ने भारत सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू करने की इच्छा जताई. एनडीएफबी की इस सकारात्मक पहल के बाद उसके बाकी साथियों को भी अदालत ने जमानत दे दी, ताकि शांति वार्ता की प्रक्रिया में तेज़ी आए और असम में बेकसूर लोगों की हत्याएं बंद हों.

बात अगर उल्फा की करें, तो परेश बरुआ इन दिनों चीन में रह रहे हैं. वह भी भारत सरकार के साथ किसी तरह की शांति वार्ता के प्रबल विरोधी रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ़ अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाली उल्फा (स्वाधीन) भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल है. अरविंद राजखोवा को जनवरी, 2011 में जमानत मिली थी. इसमें कोई शक नहीं कि भारत सरकार पूर्वोत्तर में अलगाववादियों के साथ शांति वार्ता करने के लिए सकारात्मक पहल कर रही है. यही वजह है कि उल्फा के राजनीतिक विचारक कहे जाने वाले भीमकांत बरगोहैन को भी दिसंबर, 2010 में जमानत दे दी गई. क़रीब सात वर्षों तक जेल में रहने वाले भीमकांत बरगोहैन अकेले ऐसे अलगाववादी नहीं हैं, जिन्हें क़ैद से रिहा किया गया है. ग़ौरतलब है कि अरविंद राजखोवा और भीमकांत बरगोहैन जैसे शीर्ष उल्फा नेताओं के अलावा, उपाध्यक्ष प्रदीप गोगोई, मिथिंगा दैमरी, राजू बरुआ, सशा चौधरी, चित्रबन हजारिका और प्रणति डेका को भी शांति वार्ता के मद्देनज़र रिहा किया गया था.

उल्लेखनीय है कि असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का असर मुख्यत: कोकराझार, चिरांग और बोंगई गांव में है, जबकि राज्य के ज़्यादातर हिस्सों, ख़ासकर ऊपरी असम में उल्फा का प्रभाव है. क़रीब तीन दशकों से सक्रिय उल्फा और एनडीएफबी ने राज्य में काफी रक्तपात किया. हालांकि, असम की न्यायप्रिय जनता ने इस हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं किया. असम की अर्थव्यवस्था में उत्तर भारतीय लोगों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता. प्रदेश के चाय बागानों, जूट उद्योगों, हस्तशिल्प एवं बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मज़दूर काफ़ी संख्या में काम करते हैं. राजस्थान की एक बड़ी आबादी दशकों से असम में व्यापार कर रही है और कई पीढ़ियों से वे लोग असम में रह रहे हैं. कोकराझार में हिंदीभाषियों की हत्या के बारे में गुवाहाटी निवासी पत्रकार राजीव कुमार ने चौथी दुनिया को बताया कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने गणतंत्र दिवस से पहले निर्दोष हिंदीभाषियों को इसलिए निशाना बनाया, ताकि केंद्र सरकार दबाव की स्थिति में आ जाए. उनके मुताबिक़, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (रंजन दैमारी गुट) अपनी रिहाई के बाद से भारत सरकार के साथ जारी शांति वार्ता में शामिल है, लेकिन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (संगविजित गुट) इस पहल का तीव्र विरोध कर रहा है. गुवाहाटी से ही प्रकाशित हिंदी अख़बार द संेटीनल के संपादक दिनकर कुमार के अनुसार, भारत सरकार के साथ शांति प्रक्रिया में उल्फा (स्वाधीन) के अध्यक्ष अरविंद राजखोवा शामिल हैं, लेकिन परेश बरुआ आज भी अपने रुख़ पर अड़े हैं. उनके मुताबिक़, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने जिस मक़सद से कोकराझार में बिहारी मज़दूरों की हत्या की, उसमें वह सफल नहीं हो सका, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले पूर्वोत्तर के लोगों को खरोंच तक नहीं आई. शायद एनडीएफबी के लिए इससे निराशाजनक बात कुछ और नहीं हो सकती. कुल मिलाकर असम समेत पूर्वोत्तर में जैसे हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि भारत सरकार के साथ जारी शांति वार्ता में वही अलगाववादी संगठन बाधा पहुंचा रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

परेश बरुआ को मौत की सज़ा

असम के प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन उल्फा के शीर्ष नेता परेश बरुआ को बीती 30 जनवरी को बांग्लादेश में फांसी की सज़ा सुनाई गई है. बरुआ के अलावा 13 अन्य लोगों को भी हथियारों की तस्करी के आरोप में मौत की सज़ा दी गई. चटगांव में न्यायाधीश मुजीबुर्रहमान की अदालत ने क़रीब 10 साल पहले हथियारों की तस्करी के मामले में बरुआ को फांसी की सज़ा सुनाई है. ग़ौरतलब है कि अप्रैल, 2004 में बांग्लादेश सरकार ने चटगांव में हथियारों से लदे 10 ट्रकों को पकड़ा था. हालांकि यह बात कभी साबित नहीं हो पाई कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार कहां से आए, लेकिन बार-बार आरोप लगे कि उक्त हथियार भारत से तस्करी करके लाए गए थे. भारत सरकार ने उल्फा को 1990 में आतंकवादी संगठन बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है. उल्फा के कई नेताओं पर बांग्लादेश में छिपने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने कई उल्फा नेताओं को भारत के हवाले भी किया है.

सक्रिय प्रमुख अलगाववादी संगठन

गृह मंत्रालय के अनुसार, असम में एक दर्जन से ज़्यादा अलगाववादी संगठन सक्रिय हैं, लेकिन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं. संगठनों की सूची निम्नवत है:-

- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा).
- नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी).
- यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (यूपीडीएस).
- कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ).
- कार्बी लांग्री नेशनल लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ).
- कार्बी नेशनल वॉलियंटर्स (केएनवी).
- कोच राजवंशी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केआरएलओ).
- कार्बी पीपुल्स फ्रंट (केपीएफ).
- बिरसा कमांडो फोर्स (बीसीएफ).
- बंगाली टाइगर फोर्स (बीटीएफ).
- आदिवासी टाइगर फोर्स (एटीएफ).
- गोरखा टाइगर फोर्स (जीटीएफ).

राज्य में अलगाववादी हिंसा पर एक नज़र

- दिसंबर 2000 में उल्फा ने 26 ग़ैर-असमिया लोगों की हत्या की.
- अक्टूबर 2002 में उल्फा ने डिब्रूगढ़ में 15 हिंदीभाषियों को मौत के घाट उतारा.
- नवंबर 2003 में राज्य के अलग-अलग ज़िलों में उल्फा ने 100 से अधिक हिंदीभाषियों की हत्या की.
- 2006 में गुवाहाटी के फैंसी बाज़ार और पाथर क्वारी में बम धमाके, जिसमें 14 हिंदीभाषी मारे गए.
- 23 नवंबर, 2006 को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर बम धमाका, 3 लोग मारे गए.
- 30 अक्टूबर, 2008 को गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगईगांव और बारपेटा में उल्फा ने सिलसिलेवार बम धमाके किए, जिनमें 100 लोगों की मौत हुई.
- 18 जनवरी, 2014 को कोकराझार में एनडीएफबी (संगविजित गुट) ने 8 हिंदीभाषियों की गोली मारकर हत्या कर दी.

जदयू ने जो तीन नाम दिए, उसकी मार्फत यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि पार्टी में कोई अपने आपको छोटा न समझे. ज़रूरत के हिसाब से और उचित समय पर सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा. लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए अपने अतिपिछड़ा और मुस्लिम कार्ड का एक नमूना नीतीश कुमार ने रामनाथ ठाकुर और कहकशां परवीन को प्रत्याशी बनाकर पेश कर दिया.

राज्यसभा के बहाने लोकसभा की तैयारी

सरोज सिंह

पिछले हफ्ते बिहार और झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के बहाने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अमलीजामा पहनाने की कवायद जोर-शोर से की गई. सोशल इंजीनियरिंग को आधार बनाकर ऐसी राजनीतिक लाइन खींचने की कोशिश लगभग हर दल ने की, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उसे वोटों का फायदा तो हो ही, साथ-साथ यह संदेश भी दे दिया जाए कि टिकटों के वितरण में अगर किसी ने हाय-तौबा मचाई, तो फिर उसे उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा. लालू प्रसाद ने झारखंड में केवल पांच विधायकों के दम पर अपने प्रिय प्रेम गुप्ता को राज्यसभा भेजकर यह साबित किया कि अभी भी उनमें राजनीतिक जोड़-तोड़ का दमखम बाकी है. लेकिन, लालू प्रसाद की असली परीक्षा बिहार में होनी है, क्योंकि उनके दल के कई बड़े नेता गठबंधन को लेकर नाराज हैं. सूत्रों पर भरोसा करें, तो नाराजगी इस हद तक है कि राजद की एकजुटता भी दांव पर लग सकती है.

बात जदयू से ही शुरू करते हैं. हमेशा की तरह सबको चौंकाते हुए नीतीश कुमार ने अपने तीनों वर्तमान सांसदों शिवानंद तिवारी, साबिर अली एवं एनके सिंह को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कर्पूरी ठाकुर के बेटे एवं पूर्व मंत्री रामनाथ ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश और कहकशां परवीन को राज्यसभा के लिए अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया. शिवानंद तिवारी को लेकर पहले से ही अंदाजा था कि इस बार उनका पत्ता कट सकता है. राजगीर के पार्टी सम्मेलन में उन्होंने जो तेवर दिखाए थे, उसके बाद तो यह आशंका काफी बढ़ गई थी, लेकिन साबिर अली और एनके सिंह का टिकट क्यों कटा, इसे लेकर तरह-तरह की बातें चर्चा में हैं. एनके सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उनसे तीन कारणों से बेहद नाराज थे. पहला यह कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मिशन में वह पूरी तरह नाकाम रहे. एक बार तो उन्होंने नीतीश कुमार को यहां तक भरोसा दिला दिया कि आप जैसा चाहते थे, वैसा ही हो गया. जदयू कार्यालय में ढोल-नगाड़े बजने लगे और महत्वपूर्ण घोषणा के लिए मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालय भी पहुंच गए, लेकिन जब सच्चाई पता चली, तो उन्होंने खुद को संभाल लिया. लेकिन जितनी किरकिरी होनी थी, वह तो हो गई थी. नीतीश कुमार की नाराजगी की दूसरी वजह यह थी कि जदयू का कांग्रेस के साथ तालमेल कराने में भी एनके सिंह नाकाम रहे.

सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी से मुलाकात तो दूर, वह फोन के माध्यम से भी दोनों नेताओं की बात नहीं करा पाए. इसके अलावा बिहार में पूंजी निवेश का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था, उसे भी अमलीजामा पहनाने में एनके सिंह फेल हो गए. मसलन एनके सिंह ने नीतीश कुमार के किसी भी टास्क को पूरा नहीं किया. इसलिए एनके सिंह का चैप्टर क्लोज होना ही था. जहां तक साबिर अली का सवाल है, तो इन दिनों उनका कद पार्टी में काफी बढ़ गया था, इसे लेकर पार्टी के कई नेता दु:खी थे. ऐसे सभी नेता साबिर अली को सबक सिखाने में लग गए. दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम ने ऐसे नेताओं को एक खूबसूरत मौक़ा दे दिया. शोएब इकबाल को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. जो एक जीता, उसके प्रचार में नीतीश कुमार साबिर अली के गलत फीडबैक के कारण गए ही नहीं. नतीजा यह हुआ कि जदयू अपनी एकमात्र जीत को भी नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं भुना पाया. उसके तुरंत बाद लोजपा से तालमेल का टास्क साबिर अली ने खुद ही अपने ज़िम्मे ले लिया. बात कुछ आगे बढ़ी, तो खैरख्वाही में साबिर अली ने नीतीश कुमार को चिराग पासवान से मुलाकात करने की सलाह दे डाली. सूत्र बताते हैं कि साबिर अली की इस सलाह से नीतीश बेहद खफा हो गए और उसी दिन यह तय हो गया कि राज्यसभा के लिए उनका टिकट कटना तय है. देखा जाए, तो अलग-अलग कारणों से इन तीनों नेताओं के टिकट काटे गए, पर नीतीश कुमार ने एक सामूहिक संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा और कोई कितना बड़ा नाम क्यों न हो, पार्टी कोई भी क़दम उठाने से नहीं हिचकेगी.

जदयू ने जो तीन नाम दिए, उसकी मार्फत यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि पार्टी में कोई अपने आपको छोटा न समझे. ज़रूरत के हिसाब से और उचित समय पर सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा. लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए अपने अतिपिछड़ा और मुस्लिम कार्ड का एक नमूना नीतीश कुमार ने रामनाथ ठाकुर और कहकशां परवीन को प्रत्याशी बनाकर पेश कर दिया. नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्होंने यह दांव खेलने में जरा भी देरी नहीं की. बताया जा रहा है कि दलित, महादलित, कुशवाहा एवं वैश्यों को टिकट और विधान परिषद के मनोनयन में उचित जगह देकर नीतीश कुमार अपने सोशल इंजीनियरिंग के नेटवर्क को पूरा करने की तैयारी में लग गए हैं. नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी ताकत कहां है, इसलिए बिना किसी गफलत के वह अपने आधार वोट को मजबूत करने में लग गए हैं, ताकि लोकसभा चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके. मिशन राजकुमार सिंह में फेल हो जाने के बाद नीतीश कुमार के लिए यह ज़रूरी हो गया था कि वह किसी साफ-सुथरी छवि वाले राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाएं और हरिवंश जी ने उनका यह काम बेहद आसान कर दिया. इससे पहले राजकुमार सिंह को अपने पाले में लाने के लिए नीतीश कुमार ने काफी कोशिश की, लेकिन राजकुमार सिंह मानने को तैयार ही नहीं हुए. अंतिम हथियार के तौर पर सूबे के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह को राजकुमार सिंह को मनाने दिल्ली भेजा गया, लेकिन तब तक देर हो गई थी. उसके दो दिन पहले ही राजकुमार सिंह नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से मिलकर सब कुछ तय कर चुके थे.

भाजपा राजकुमार सिंह को लोकसभा चुनाव में बड़ा हथियार बनाने जा रही है. सूबे में सड़कों का जो जाल बिछा है, उसकी बुनियाद राजकुमार सिंह ने ही रखी थी और उनकी इस उपलब्धि का भाजपा पूरा फायदा उठाना चाहती है. देखा जाए, तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव में पूरी कोशिश की कि कम से कम नुकसान झेलकर जनता के बीच यह संदेश दिया जाए कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और ख़तरा उठाने की ताकत भी रखती है. नीतीश कुमार को उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस संदेश का फायदा पार्टी को ज़रूर मिलेगा. लेकिन लालू प्रसाद के लिए धर्मसंकट बड़ा है. झारखंड सरकार गिराने की चेतावनी देकर भले ही वह अपने सबसे प्रिय प्रेम गुप्ता को राज्यसभा भेजने में सफल रहे, पर उसकी भारी क़ीमत उन्हें बिहार में चुकानी पड़ सकती है. कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें हासिल करने और विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए झारखंड में राजद को सहयोग कर दिया, पर इस वादे को निभाने में लालू प्रसाद कहीं बिहार में अपनी पार्टी को ही भारी नुकसान न पहुंचा दें. कांग्रेस का प्रत्याशी झारखंड में जीतने की हैसियत नहीं रख रहा था, ऐसे में पार्टी को झामुमो को समर्थन देना ही था, लेकिन बीच में राजद के आ जाने से कांग्रेस को खोने में भी फायदा नज़र आ गया और बिना किसी हिचक के राजद के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया.

अब लाख टके का सवाल है कि लालू प्रसाद अपने इस वादे को निभाएंगे कैसे? अगर गठबंधन के कारण अब्दुल बारी सिद्दीकी, सम्राट चौधरी, रघुनाथ झा, तस्लीमुद्दीन और ललन पासवान जैसे नेता चुनाव नहीं लड़ पाए, तो राजद को एकजुट रख पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा. सूत्र बताते हैं कि ये नेता किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार बैठे हैं. राजद के विधायक पहले से ही जदयू और भाजपा के साफ्ट टारगेट रहे हैं. जदयू की तरफ़ से तो उन्हें सरकार में शामिल होने का भी न्योता है. यह बात भी जानकारी में आई है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है. हालांकि सम्राट चौधरी साफ़ करते हैं कि यह राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक केस के सिलसिले में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी. अब सम्राट चौधरी की सफ़ाई में कितना दम है, उसका फ़ैसला आप खुद कर लीजिए. वैसे जानकार बताते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की उपेक्षा से राजद के कई नेता और बड़े स्तर पर कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं. ऐसे नेताओं का कहना है कि अगर मधुबनी सीट कांग्रेस को ही देनी है, तो फिर झारखंड से प्रेम गुप्ता के बजाय अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेज दिया जाता. इससे मुसलमानों में एक अच्छा संदेश जाता और गठबंधन बनाने में भी सहूलियत होती, पर ऐसा लालू प्रसाद ने नहीं किया, क्योंकि उन्हें दरबारी लोग ज़्यादा पसंद हैं.

सम्राट चौधरी खगड़िया से लड़ने पर अड़े हैं, तो ललन पासवान सासाराम से. इसलिए लालू प्रसाद के लिए यह मुश्किल भरा दौर है. तेज प्रताप के छपरा और मीसा भारती के पाटलीपुत्र सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा से भी लालू प्रसाद की आलोचना जोर पकड़ रही है. कहा जा रहा है कि अपने बेटी और बेटे के लिए तो वह सीट बचा ले गए, पर दल के मजबूत और समर्पित नेताओं की उन्होंने परवाह नहीं की. इसलिए यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने तो राज्यसभा चुनाव के बहाने लोकसभा की अच्छी तैयारी कर ली, पर राजद उसमें पिछड़ गया. जहां तक सवाल भाजपा का है, तो उसने भी बिना हिचक दिखाए सीपी ठाकुर और आरके सिन्हा को टिकट देकर यह साफ़ कर दिया कि अगड़ी जातियों का समर्थन उसके लिए बेहद अहम है. इसके बाद जातीय तालमेल बैठाने के जो प्रयोग करने हैं, वे भाजपा लोकसभा का टिकट देने और विधान परिषद में मनोनयन में करेगी. सूबे में जो माहौल भाजपा के पक्ष में बन रहा है, उसे गति देने के लिए यह ज़रूरी है कि सटीक सोशल इंजीनियरिंग का नमूना पेश किया जाए, क्योंकि बाकी तो फिर नरेंद्र मोदी के नाम और काम को करना है. कमोबेश इसी लाइन पर भाजपा सूबे में अपना होमवर्क कर रही है और यही बात ग़ैर-भाजपाई दलों के लिए चिंता का सबब बन गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

»

अब लाख टके का सवाल है कि लालू प्रसाद अपने इस वादे को निभाएंगे कैसे? अगर गठबंधन के कारण अब्दुल बारी सिद्दीकी, सम्राट चौधरी, रघुनाथ झा, तस्लीमुद्दीन और ललन पासवान जैसे नेता चुनाव नहीं लड़ पाए, तो राजद को एकजुट रख पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा. सूत्र बताते हैं कि ये नेता किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार बैठे हैं. राजद के विधायक पहले से ही जदयू और भाजपा के साफ्ट टारगेट रहे हैं. जदयू की तरफ़ से तो उन्हें सरकार में शामिल होने का भी न्योता है.

मेरी दुनिया....

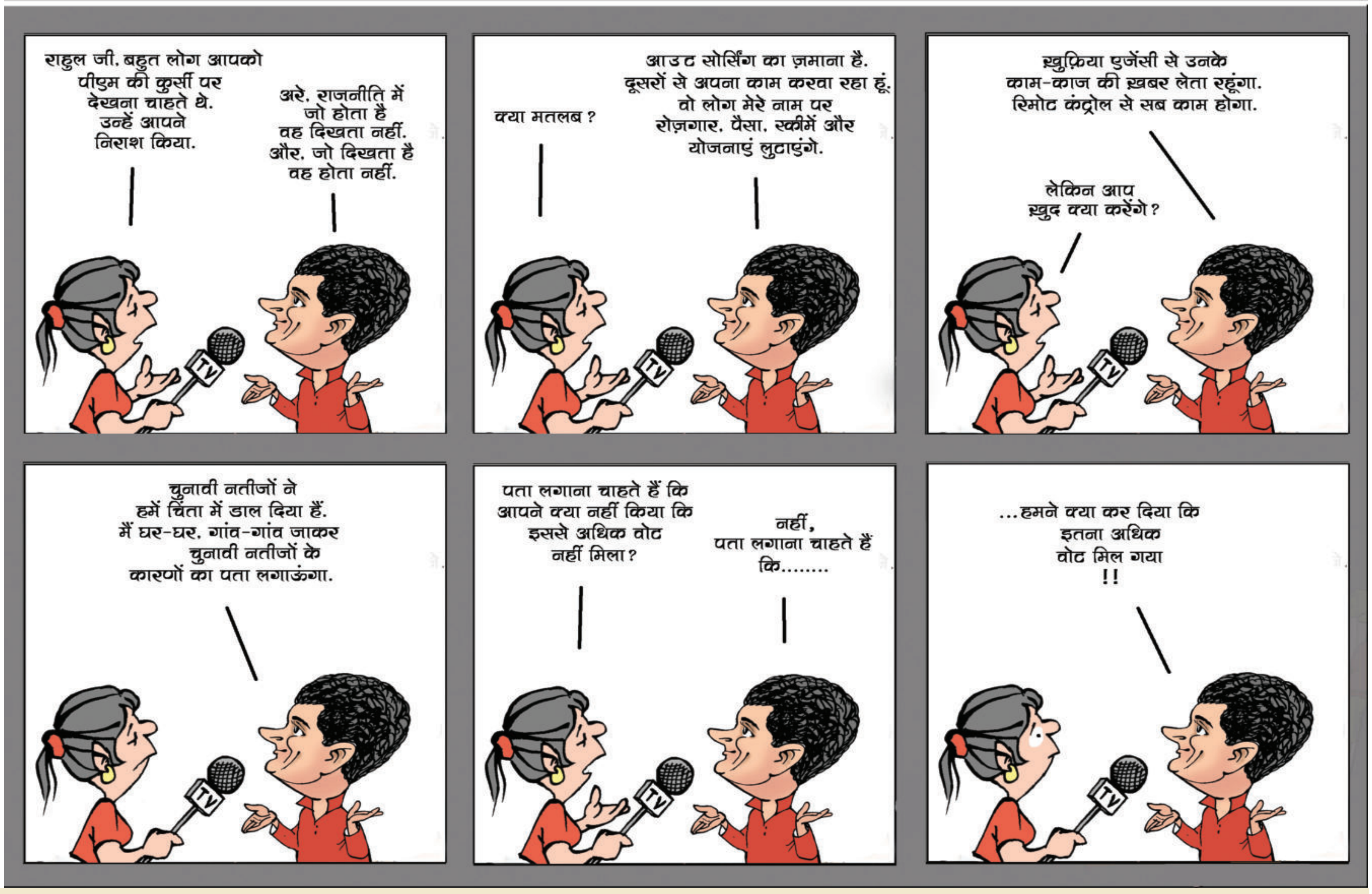

आम आदमी पार्टी को लेकर मुझे कभी कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि यह मुख्यतः एनजीओ फॉर्मेशन की पॉलिटिक्स है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही जनता का अराजनीतिकरण करना है. आम आदमी पार्टी कॉर्पोरेट्स के इंट्रेस्ट को एक अलग तरीक़े से पेश कर रही है. दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बेशक हमारे मतभेद हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो डी–पोलिटिसाइज मास का प्रतिनिधित्व करती है. जनांदोलनों में आम आदमी पार्टी का कोई इतिहास नहीं है. यह एक तरह की एजेंसी है, जिनमें विदेशी ताक़तों मसलन, फोर्ड फाउंडेशन के हित भी जुड़े हुए हैं. लिहाज़ा वह अपने घोषणा–पत्र में क्या कहते हैं, यह मायने नहीं रखता.

एनजीओ युग की देन है आम आदमी पार्टी

देश के लोकतंत्र में लोक की भागीदारी बढ़ रही है, जिन लोगों ने अवाम को बरगलाने का काम किया उनकी भूमिका अब संदेह के घेरे में है. जनता उन्हें कठघरे में खड़ा कर रही है. इन बदलावों के बावजूद कई बुनियादी मसलों पर राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत को कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता बदलाव की राजनीति बता रहे हैं, लेकिन एनजीओ और कॉरपोरेट घरानों को लोकपाल क़ानून से बाहर रखे जाने पर भी एक बहस छिड़ गई है. इन बुनियादी सवालों का जवाब देश की सरकार से मांगने के लिए और आम आदमी को गुमराह करने वाली ताकतों को बेनकाब करने के लिए ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह 7 से 16 फरवरी तक जंतर-मंतर पर घरने पर बैठ रहे हैं. क्या हैं उनकी मांगे और एजेंडा क्या है यह जानने के लिए उनसे बातचीत की चौथी दुनिया संवाददाता नीरज सिंह ने, प्रस्तुत है उसके मुख्य अंश...

आपकी मांगे क्या हैं और इन मांगों के माध्यम से आप क्या बदलाव देख रहे हैं ?

देखिए, देश एक बार फिर बदलाव के पक्ष में है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर हमें और लड़ाईयां लड़नी है. मिसाल के तौर पर लोकपाल क़ानून पारित हो गया है, लेकिन कॉरपोरेट घरानों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है. कॉरपोरेट घरानों और ग़ैर–सरकारी संगठनों को लोकपाल क़ानून के दायरे से बाहर रखना समझ से परे है. आम आदमी पार्टी समेत वे तमाम लोग, जो लोकपाल को एक केंद्रीय विषय बनाकर राजनीति में कर रहे हैं, उनसे यह जानना चाहता हूं कि आख़िर इस बुनियादी सवाल पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है ? संसद में ख़ासतौर पर राज्यसभा में, जहां सिर्फ़ 19 लोगों ने कॉरपोरेट घरानों को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए मत दिया था. ऐसे में सवाल यह है कि, जो लोग लोकपाल को ही आधार बनाकर राजनीति में आए थे, वे इस मामले में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं?

पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की यह कोशिश थी कि रोज़गार का अधिकार मौलिक अधिकार बने. इसे वह नीति निदेशक तत्वों से निकालकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाना चाहते थे. मेरे ख्याल से नई आर्थिक नीतियों ने समाज की जिन तीन श्रेणियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, उसमें एक श्रेणी युवाओं की है. मनमोहन सरकार के मौजूदा विकास मॉडल में रोज़गार सृजन की संभावनाएं नगण्य हैं. इस बाबत संप्रग सरकार चाहे जो आंकड़े जारी करे, लेकिन सच्चाई है यह कि देश में रोज़गार का बड़ा संकट है. मौजूदा अर्थव्यवस्था में रोज़गार की संभावनाएं विलुप्त हो चुकी हैं. आखिर यह मनमोहन सरकार रोज़–गारपरक अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है ? सरकार को चाहिए कि वह रोज़गार परक अर्थव्यवस्था का निर्माण करे, क्योंकि जैसे ही आप रोज़गार से जुड़े सवालों को हल करेंगे, वैसे ही खेती–किसानी का संकट, छोटे उद्योगों के समक्ष चुनौतियां और मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आने वाली गिरावट का संकट हल हो जाएगा. इसलिए रोज़गार के प्रश्न को हमने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया है.

तीसरा सवाल है नेशन बिल्डिंग का, क्योंकि हमारे देश में जगह–जगह गोधरा जैसे प्रयोग हो रहे हैं. सांप्रदायिक दंगों की वजह से लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को विवश हैं. इसीलिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न एक महत्व–पूर्ण प्रश्न है. सरकार को इस विषय में गंभीरता–पूर्वक विचार करना चाहिए. साथ ही साथ सांप्रदायिकता विरोधी बिल को भी इसी सत्र में पारित कराना चाहिए. अदालत ने जिन लोगों को बेकसूर क़रार दिया है, उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था होनी चाहिए.

हमारा चौथा प्रश्न है संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर, जिसे आम आदमी पार्टी ने भी उठाया था. हालांकि, यह दुर्भाग्य है कि वे इस वादे से मुकर रहे हैं. जो लोग ठेके (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए. ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों की इतनी आय भी नहीं है कि वे ठीक तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. महंगाई का रोना रोकर सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकती. लोग ज़्यादा खा रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, इस तरह का बयान ग़रीबों के साथ मजाक है. दरअसल, सट्टेबाज़ी की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है. मानवाधिकारों की गारंटी भी एक महत्वपूर्ण सवाल है. चाहे पूर्वोत्तर हो या कश्मीर हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा, हर जगहों पर मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए.

आपकी जो मांगे, उसका ज़िक्र आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में भी किया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि वह अपने वायदों से मुकर रही है. आख़िर आपको ऐसा क्यों लग रहा है?

आम आदमी पार्टी को लेकर मुझे कभी कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि यह मुख्यतः एनजीओ फॉर्मेशन की पॉलिटिक्स है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही जनता का अराजनीतिकरण करना है. आम आदमी पार्टी कॉर्पोरेट्स के इंट्रेस्ट को एक अलग तरीक़े से पेश कर रही है. दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बेशक हमारे मतभेद हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो डी–पोलिटिसाइज मास का प्रतिनिधित्व करती है. जनांदोलनों में आम आदमी पार्टी का कोई इतिहास नहीं है. यह एक तरह की एजेंसी है, जिनमें विदेशी ताक़तों मसलन, फोर्ड फाउंडेशन के हित भी जुड़े हुए हैं. लिहाज़ा वह अपने घोषणा–पत्र में क्या कहते हैं, यह मायने नहीं रखता.

क्या यह मान लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार विदेशी ताक़तों के माध्यम से हमारे ऊपर थोपी हुई सरकार है?

संप्रग सरकार की आर्थिक नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास और वामदलों की कमज़ोर होती ज़मीन की वजह से मौजूदा राजनीति में एक शून्य पैदा हुआ है. इसी स्थिति का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मिला. जनमुद्दों की बात उठाकर आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति शुरू की. सभी राजनीतिक दल जनता की उपेक्षा कर रहे हैं, यह भावना लोगों के मन में थी और इसी आधार पर दिल्ली की जनता ने उन्हें एक मौक़ा दिया. हालांकि, अब केजरीवाल सरकार का असली रूप भी दिखने लगा है. कई लोकतांत्रिक ताक़तें, जो आम आदमी पार्टी को लेकर मुग़ालते में थीं, उनकी ग़लतफ़हमी भी धीरे–धीरे दूर हो रही हैं.

कुछ लोग कह रहे हैं कि इस सरकार की मंशा ग़लत नहीं है, हो सकता है कि उनका तरीक़ा ग़लत हो?

आपकी मंशा क्या है यह राजनीति में अहम सवाल नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि आप कर क्या रहे हैं? खिड़की एक्सटेंशन मामले में आप सरकार का रवैया और उसका राजनीतिक आचरण सभ्य समाज के लिए कलंक है. कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अराजकतावादी हैं, लेकिन फासीवादी नहीं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि फासीवाद की उत्पत्ति अराजकतावाद के गर्भ से ही होती है. हिटलर के राजनीतिक उत्थान में लुम्पेन प्रोलैतेरिएत ने बड़ी भूमिका निभाई थी. आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और उसके कार्यकर्ता हमारे संपर्क में रहे हैं. मैं उनके विचारों से भी अवगत हूं. यह पार्टी जनआकांक्षाओं को पूरा करेगी, ऐसी उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि उसके पास कोई ठोस नीति नहीं है. उत्तर आधुनिक युग में जो एनजीओ खड़े हुए, उन्होंने सबसे ज़्यादा हमला विचारधारा पर किया और एक विचारधाराविहीन विचारधारा विकसित करने की कोशिश की. मुझे आश्चर्य नहीं होता, जब अरविंद केजरीवाल यह कहते हैं कि क्या रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़े प्रश्नों को कोई विचारधारा हल कर सकती है. मेरे ख्याल से दुनिया का कोई आदमी बग़ैर विचारधारा के नहीं रह सकता. अगर कोई विचारधारा जनता के बुनियादी सवालों को हल नहीं कर सकती है, तो वह कौन सा राजनीतिक दर्शन है, जो रोटी–कपड़ा और मकान के प्रश्न हल कर सकता है. यह अ–राजनीति की जो विचारधारा है, यह देश के लिए घातक है. जो लोग फासीवादी ताक़तों से निपटने में इनकी भूमिका देख रहे हैं, दरअसल वे गफ़लत में हैं, क्योंकि इससे तानाशाही ताकतें और मज़बूत होंगी.

आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह जनव–ादी नीतियों की पोषक हैं, वहीं आपका ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट भी जनपक्षधरता की बात करती है. आप दोनों की जनपक्षीय नीतियों में क्या फ़र्क़ है?

हमारी राजनीति के केंद्र में किसान है और उसके केंद्र में पीपुल्स नेशन अर्थव्यवस्था है, जो लगातार नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध संघर्षरत हैं. हमने अपने संविधान में स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी विदेशी सहायता के पक्षधर नहीं है. इसलिए हमारी और उनकी कोई तुलना ही नहीं है. आम आदमी पार्टी भी उसी श्रेणी में खड़ी नज़र आती है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा है. हम लोग आम आदमी पार्टी विरोधी अभियान का हिस्सा नहीं हैं. इस मामले में मैं अपना रुख़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं. अरविंद केजरीवाल से मेरी तक़रीबन चार बार मुलाक़ात हुई है. मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर काम करना बेहद ज़रूरी है. भारत सरकार में वित्त सचिव थे एसपी शुक्ला, उनकी अध्यक्षता में हमने नेशनल कैंपेन कमेटी बनाई है. मैं इस कमेटी का नेशनल कैंपेनर हूं. हम लोगों ने इस बाबत अरविंद को एक पत्र भी लिखा, जिसमें इसका ज़िक्र है. हालांकि, हमारे पत्र का इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया. कृषि की समस्या और भूमि अधिग्रहण के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मसले पर बाद में बात करेंगे.

इस देश में नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों की विचारधाराएं पहले ही ख़ारिज हो चुकी हैं. अगर ऐसा नहीं होता, तो वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान बन रहा था, उसी समय भारत भी हिंदू राष्ट्र बन गया होता. हिंदुत्व की इसी विचारधारा को मोदी और आरएसएस अलग-अलग तरीक़े से पेश करते हैं. जीडीपी बढ़ना और सड़कें चौड़ी होना ही विकास का सूचक नहीं है. दरअसल, यह ग्रोथ विश्व बैंक का मॉडल है. इस तथाकथित विकास में आम आदमी कहां है? नरेंद्र मोदी भी मीडिया की उपज हैं. मोदी एक तरफ 56 इंच सीने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आईआईटी की भी बात करते हैं. ऐसे में आप यह बखूबी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की राजनीति सामंती समाज की बुनियाद पर और उनकी अर्थव्यवस्था सट्टे पर आधारित है.

नरेंद्र मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया से आप कितना सहमत हैं?

इस देश में नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों की विच–ारधाराएं पहले ही ख़ारिज हो चुकी हैं. अगर ऐसा नहीं होता, तो वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान बन रहा था, उसी समय भारत भी हिंदू राष्ट्र बन गया होता. हिंदुत्व की इसी विचारधारा को मोदी और आरएसएस अलग–अलग तरीक़े से पेश करते हैं. जीडीपी बढ़ना और सड़कें चौड़ी होना ही विकास का सूचक नहीं है. दरअसल, यह ग्रोथ विश्व बैंक का मॉडल है. इस तथाकथित विकास में आम आदमी कहां है? नरेंद्र मोदी भी मीडिया की उपज हैं. मोदी एक तरफ 56 इंच सीने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आईआईटी की भी बात करते हैं. ऐसे में आप यह बखूबी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की राजनीति सामंती समाज की बुनियाद पर और उनकी अर्थव्यवस्था सट्टे पर आधारित है.

इस बात की क्या गारंटी की आपकी मांगो को मान लेने के बाद सारी समस्याएं हल ही हो जाएंगी?

देखिए जो नीतियां अभी हैं जैसे अगर मनरेगा की करें, तो इस योजना के नाम पर 40 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च हो रहे हैं. भला 40 हज़ार करोड़ रुपये में 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित हो पाएगा? कुछ समय पहले वनाधिकार क़ानून बना. अकेले उत्तर प्रदेश में 97 हज़ार लोगों ने ग्राम समितियों को इस अधिकार के लिए आ–वेदन कर रखा था. उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ख़ारिज कर दिया. हमने हाईकोर्ट में इस बाबत याचिका दायर की थी. न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शासन के उस आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि नए सिरे से वनाधिकार समितियों का गठन किया जाए. मेरा मानना है कि इस देश में क़ानून बनने के समय ही, उसे निष्प्रभावी बनाने की साज़िश होने लगती है. हमारे देश में जिन राजनीतिक दलों ने शासन किया, वे काफ़ी चतुर रहे हैं. देश में कानून का अनुपालन बेहद ज़रूरी है साथ ही मौजूदा राजनीतिक ढांचे में बदलाव भी आवश्यक है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

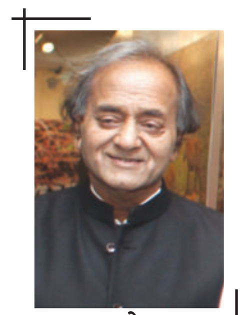

कमल मोरारका

गुजरात में, अहमदाबाद में यहां तक कि पूरे देश में लोग यह मानते हैं कि 2002 में गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं. इसलिए शरद पवार जैसे वरिष्ठ और समझदार नेता को अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहिए कि वे एक रुख अख्तियार करें कि हमें न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए. आगे जरूरत पड़ने पर नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, आज के माहौल में सिद्धांत गौण हो गए हैं, हर कोई वही करना चाहता है जिससे कोई फायदा हो, फायदा भी दूरगामी न होकर तात्कालिक हो.यह बेहद खेदपूर्ण है.

राहुल गांधी चूक गए

बीते दिनों की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी का अरनब गोस्वामी द्वारा लिया लंबा इंटरव्यू रहा. हालांकि मुश्किल यह है कि राहुल गांधी ने शुरुआत करने में काफी देर लगा दी. अगर उन्होंने यही पहल तीन साल पहले कर दी होती तो अब तक उनकी साक्षात्कार देने की कला में निखार आ गया होता और वह राजनीतिक सवालों के सही जवाब देने में महारत हासिल कर चुके होते. दरअसल, सही नीयत और गंभीरता का होना ही पर्याप्त नहीं है. उन्होंने अपनी ओर से सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में चूक गए. यह सिख समुदाय के लिहाज से बहुत संवेदनशील मुद्दा है. व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस गोधरा दंगों के मसले को हमेशा उठाती रही है ऐसे में वह 1984 के दंगों को सिरे से दरकिनार नहीं कर सकती है. आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए था. इस मसले पर सिख समुदाय से माफी मांगने का राहुल गांधी के पास एक बेहतरीन मौका था लेकिन दुर्भाग्यवश वह इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने यह मौका गंवा दिया. वह कमजोर पड़ गए और मजबूत नेता के रूप में सामने नहीं आ सके.

दूसरी तरफ उन्हें यह भी समझना होगा कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और वह भावनाओं में बहकर किसी नई पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की तरह हवा-हवाई वादे नहीं कर सकती है. भाजपा भावनाओं से ओतप्रोत पार्टी है जो वादे पर वादे तो करती जाती है लेकिन जब सत्ता में आती है तब आर्थिक नीतियों आदि के मामलों में या तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है या फिर वो भी कांग्रेस की लीक पर चलने लगती है. कांग्रेस के साथ वास्तविक परेशानी यह है कि उसके पास काम के नाम पर लोगों को दिखाने के लिए केवल सूचना का अधिकार और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ही हैं. जो कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल की उपलब्धियां हैं. इनकी वजह से ही यूपीए को दूसरी बार सरकार बनाने के लिए लोगों का भारी समर्थन मिला था. दुर्भाग्यवश यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों का एक-एक करके खुलासा होने लगा जो कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लिए वास्तविक परेशानी है. यहां सवाल यह नहीं है आज पार्टी का क्या रुख है, उन्होंने अब तक क्या किया और क्या करेंगे? समस्या यह है वे अपने दो शासनकालों के दौरान बेशर्मी से किए गए कोयला और राष्ट्रमंडल खेल घोटालों पर क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर धांधली होने का उल्लेख किया है और आंकड़े बताते हैं कि यह कितने बड़े घोटाले थे. दुर्भाग्य से बहस इस बात में उलझ गई कि सरकार को इनसे कितना घाटा हुआ, जिसका कोई औचित्य नहीं है. जबकि सच्चाई यह है कि सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है और यह व्यावसायिक नुकसान नहीं है बल्कि यहां पर गलत तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके और नियमों का तोड़-मरोड़कर अपने करीबियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया गया.

भारत की जनता बहुत समझदार है वह सब देख और समझ रही है और यह कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का कारण है. कांग्रेस के थिंक टैंक में जो भी लोग हैं उन्हें एक साथ बैठकर यह विचार करना चाहिए कि इन आरोपों का सामना किस तरह किया जाए, उन्हें कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण ढूंढना होगा, न्यायिक आयोग का गठन या कुछ ऐसा करना होगा जिससे ऐसा प्रतीत हो कि कांग्रेस के हाथ साफ-सुथरे हैं.

भारत की जनता बहुत समझदार है वह सब देख और समझ रही है और यह कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का कारण है. कांग्रेस के थिंक टैंक में जो भी लोग हैं उन्हें एक साथ बैठकर यह विचार करना चाहिए कि इन आरोपों का सामना किस तरह किया जाए, उन्हें कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण ढूंढना होगा, न्यायिक आयोग का गठन या कुछ ऐसा करना होगा जिससे ऐसा प्रतीत हो कि कांग्रेस के हाथ साफ-सुथरे हैं. आप मामलों पर पर्दा डालने और उसकी लीपा-पोती में जुटे हुए हैं. यह बात आदर्श सोसायटी के मामलें में भी लागू होती है. सही या गलत किसी भी तरह यदि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को इस मामले में दोषी पाया गया है बावजूद इसके उनका साथ दिया जा रहा है क्योंकि वह युवा हैं और मुख्यमंत्री बनते समय वे राहुल गांधी की पसंद थे. यह सही रास्ता नहीं है. पार्टी के भले के लिए आप हमेशा अपने तरीके से नहीं चल सकते. आपके लिए भी कुछ नियम कायदे हैं. आपको भी उनका पालना करना चाहिए. ऐसा करने के बावजूद आपको नुक्सान हो तो फिर यह आपकी बदकिस्मती है.

दूसरा, कार्यवाही को लेकर, उच्चतम न्यायालय ने टू जी स्पेक्ट्रम का आवंटन रद्द कर दिया था लेकिन कोयला खदानों के मामले में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है. इसी तरह आदर्श सोसायटी के मामले में भी हुआ. आदर्श सोसायटी के मामले में सरकार को इमारत अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए थी. लोगों ने सोसायटी में जो भी पैसे जमा किए थे उन्हें वो पैसे वापस कर देने चाहिए थे क्योंकि वह ज़मीन बेहद कीमती है और ज़मीन की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है. यदि वे इमारत को धराशाई कर देते फिर भी सरकार को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता. सरकार को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, निर्णय लेने के मामले में पशोपेश की स्थिति क्यों बनी हुई है या तो वो निर्णय लेने से घबरा रहे हैं या स्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं. लेकिन इस सबके बाद कुल मिलाकर कांग्रेस की छवि पर बट्टा लगा है.

एक दूसरा वक्तव्य प्रफुल्ल पटेल का है. उन्होंने कहा कि वह नरेंद्र मोदी से जुड़े मामलों में न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका केवल एक मतलब है कि उन्होंने यह मान लिया है कि भाजपा कांग्रेस से आगे है और आम चुनाव के बाद यूपीए की बजाए एनडीए के साथ गठबंधन के विकल्प खुले हुए हैं. न्यायिक आदेश ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, न्यायिक निर्णयों के आधार पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में सैकड़ों लोगों को सजा सुनाई गई, लेकिन गोधरा के मामले मे न के बराबर लोगों को सजा सुनाई गई. आप यह नहीं मान सकते हैं कि न्यायिक निर्णय जनता की धारणा है. गुजरात में, अहमदाबाद में यहां तक कि पूरे देश में लोग यह मानते हैं कि 2002 में गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं. इसलिए शरद पवार जैसे वरिष्ठ और समझदार नेता को अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहिए कि वे एक रुख अख्तियार करें कि हमें न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए. आगे जरूरत पड़ने पर नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, आज के माहौल में सिद्धांत गौण हो गए हैं, हर कोई वही करना चाहता है जिससे कोई फायदा हो, फायदा भी दूरगामी ने होकर तात्कालिक हो.यह बेहद खेदपूर्ण है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोक उम्मीदवार के लिए मतदान

ठाकुर दास बंग

किस पद्धति से मतदान होगा?

उसी पद्धति से, जिसके द्वारा गांव-गांव की प्राथमिक इकाई से निर्वाचक मंडल के लिए प्रतिनिधि चुने गए थे.

मतलब यह कि जितने नाम आएंगे, उन पर बारी-बारी से मतदान होगा और हर बार सबसे कम वोट पाने वाला छंटता जाएगा?

हां, लेकिन जब दो नाम रह जाएं, तो मतदान बंद हो जाए.

दो नामों में अंतिम नाम कैसे तय होगा?

चिट्ठी डालकर.

यह तो किस्मत का खेल हो गया!

कुछ हिकमत, कुछ किस्मत, दोनों को मिलाकर काम होगा, तो शिकायत के लिए गुंजाइश नहीं रह जाएगी.

अगर निर्वाचक मंडल चाहे कि अंतिम दो नामों में भी वोट से ही निर्णय हो, तो क्या वह ऐसा कर सकता है?

क्यों नहीं? निर्णय उसे करना है. लोक उम्मीदवार के चयन के लिए उसे जो भी तरीका अच्छा मालूम हो, वह अपना सकता है. तरीका कोई हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्वाचक मंडल में कटुता न पैदा हो और पूरा काम शांति एवं सद्भावना के वातावरण में हो, ताकि उम्मीदवार तय हो जाने के बाद गांव-गांव के मतदाता चुनाव के काम में उत्साह के साथ लग सकें.

चयन के बाद मतदान का काम जटिल है. चुनाव लड़ाई है. उसमें क्या-क्या होता है? चुनाव की लड़ाई लोक उम्मीदवार की ओर से कौन लड़ेगा, कौन खर्च देगा? आजकल तो बूथ कैप्चर होता है और न जाने क्या-क्या होता है?

कौन नहीं जानता कि मतदान में क्या-क्या होता है, लेकिन आजकल जो हो रहा है, उसी को मानकर सोचने से काम कैसे चलेगा? सोचना यह चाहिए कि जब उम्मीदवार के चयन का तरीका नया सोचा गया, तो चुनाव लड़ने का तरीका भी नया सोचना चाहिए. अगर वह न हुआ, तो दलीय उम्मीदवार की जगह लोक उम्मीदवार से क्या फायदा?

आज के वातावरण में लोक उम्मीदवार चुनाव की लड़ाई कैसे लड़ेगा?

अगर दलीय उम्मीदवार की लड़ाई दल लड़ता है, तो लोक उम्मीदवार की लड़ाई लोक को लड़नी पड़ेगी. लोक यानी मतदाताओं को. आपको अपना उम्मीदवार जिताने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी.

कैसे?

सोचिए, जिस उम्मीदवार को गांव-गांव के मतदाताओं के प्रतिनिधियों ने तय किया है, उसकी जड़ कितनी मजबूत होगी. इससे ज़्यादा मजबूत जड़ किस उम्मीदवार की हो सकती है?

फिर भी लड़ाई तो होगी ही, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार भी होंगे, दल के हों या स्वतंत्र. क्या नहीं होंगे?

क्यों नहीं होंगे? लोक उम्मीदवार का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे कोई उम्मीदवार नहीं हो सकते. चुनाव के नियम के अनुसार किसी को भी खड़ा होने से मना नहीं किया जा सकता.

तब लड़ाई से जान कैसे बचेगी?

लड़ाई तो होगी, सिर्फ़ उसका ढंग नया होगा.

किन बातों में नया होगा? कौन सा ढंग नया अपनाया जाएगा?

लोक उम्मीदवार का चुनाव अभियान उम्मीदवार के चयन के बाद शुरू हो जाएगा यानी सरकार द्वारा मतदान की घोषणा के काफी पहले. निर्वाचक मंडल की बैठक से लौटकर प्रतिनिधि अपने-अपने गांव के मतदाताओं को बुलाकर बताएंगे कि निर्वाचक मंडल ने राम या श्याम नामक व्यक्ति को अपना उम्मीदवार तय किया है, इसलिए उसी को वोट देना है. इस तरह एक साथ क्षेत्र के हर गांव में यह ख़बर फैल जाएगी. निर्वाचक मंडल के सदस्य, जिन्होंने लोक उम्मीदवार का चयन किया है, उसे जिताने की कोई कोशिश बाकी नहीं रखेंगे. इसके अलावा तीन काम विशेष रूप से करने पड़ेंगे. (1) लोक उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र के हर गांव में जाए और मतदाताओं से मिले. (2) क्षेत्र में चार-छह जगह बड़ी सभाएं की जाएं और लोक उम्मीदवार का नया विचार अच्छी तरह समझाया जाए. इसके लिए पर्चे, फोल्डर आदि भी छपवा लिए जाएं. (3) चुनाव के दिन अधिक से अधिक मतदान कराया जाए और बूथ कैप्चर आदि की गुंजाइश न रहने दी जाए.

कठिन काम है यह, कैसे होगा? खर्च भी लगेगा, रुपया कहां से आएगा?

मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. लड़ाई है, तो लड़नी पड़ेगी. जो खर्च लगेगा, उसके लिए धन जनता से मांगकर जुटाना पड़ेगा. लेकिन यह जान लीजिए कि खर्च आज जितना लगता है, उससे बहुत कम लगेगा, बल्कि नहीं के बराबर लगेगा. लोक उम्मीदवार लोकतंत्र में एक नया प्रयोग है. इस प्रयोग में रुचि रखने वाले साथी इतना मानकर घर नहीं बैठ सकते कि उम्मीदवार का चयन हो, तो चुनाव लड़ना उम्मीदवार का काम है, हारे या जीते. ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल होगी. तब तो यही मानना पड़ेगा कि लोक उम्मीदवार के प्रयोग का महत्व लोगों ने समझा ही नहीं. जिन चार सौ लोगों ने निर्वाचक मंडल में बैठकर लोक उम्मीदवार का चयन किया, उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी. उनका काम होगा कि वे हर मतदान केंद्र, बल्कि हर बूथ के लिए कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाएं, गांव-गांव में गोष्ठी करें, जगह-जगह सभाएं करें और मतदाताओं में यह भावना पैदा करें कि लोक उम्मीदवार का चुनाव आज की गंदी, स्वार्थी राजनीति से मुक्ति का एक मोर्चा है. इस मोर्चे पर जीत उम्मीदवार से अधिक स्वयं मतदाताओं की जीत है, इसलिए मतदाताओं का कर्तव्य है कि वे अपने उम्मीदवारों को जिताएं. वे समझें कि चुनाव की यह लड़ाई उनके अधिकार की लड़ाई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कौन नहीं जानता कि मतदान में क्या-क्या होता है, लेकिन आजकल जो हो रहा है, उसी को मानकर सोचने से काम कैसे चलेगा? सोचना यह चाहिए कि जब उम्मीदवार के चयन का तरीका नया सोचा गया, तो चुनाव लड़ने का तरीका भी नया सोचना चाहिए. अगर वह न हुआ, तो दलीय उम्मीदवार की जगह लोक उम्मीदवार से क्या फायदा?

पाठकों की दुनिया

नीयत साफ़ नहीं है

मुख्य आलेख-नीति और नीयत साफ़ नहीं है (अंक 27 जनवरी-02 फरवरी) पढ़ा. मनीष कुमार ने तथ्यों पर आधारित अपने इस लेख के जरिये आम आदमी पार्टी की सच्चाई पर रोशनी डाली है कि आप किस प्रकार जनता को ख्वाब दिखाकर दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हुई. आम आदमी पार्टी को लेकर जो भ्रम थे, वे दूर हो गए. यह पार्टी केवल सत्ता के लिए सारी नौटंकी कर रही है.

-विकास कुमार, *शाहदरा, नई दिल्ली.*

बासी मुद्दे

आलेख-पुराने पड़ चुके हैं राजनीतिक मुद्दे पढ़कर ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं यह सच है. भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पुराने मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं. भाजपा ज़रूर अपने कुछ पुराने मुद्दे, मजबूरी या अन्य वजहों से नहीं उठा रही है. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, नए वादे करते हैं, जिससे वह युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, लेकिन कांग्रेस पुराने राजनीतिक मुद्दों पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने की फिराक में है. एक नई पार्टी आई है, जो लोगों को ख्वाब दिखाकर सत्ता हासिल करना चाहती है. समय आ गया है कि राजनीतिक दलों को अपनी सोच, अपनी नीति और अपने कार्यक्रम बदलने चाहिए, क्योंकि अब जनता भी बदलाव चाहती है.

-प्रदीप, *रांची, झारखंड.*

मूर्ख बनाती सरकार

27 जनवरी-02 फरवरी के अंक में प्रकाशित आलेख-मुसलमानों को कब तक मूर्ख बनाती रहेगी यूपीए सरकार देश में मुस्लिम समुदाय की बदहाली को बयां करता है. क़मर तबरेज़ सही कहते हैं कि मुसलमान राजनीतिक दलों के लिए केवल एक वोट बनकर रह गया है. मुसलमानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में स्कूल नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती. मुसलमान बेरोज़गार है, बद से बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर है.

-आफताब आलम, *बरेली, उत्तर प्रदेश.*

यूपीएससी का रवैया

अरुण तिवारी का आलेख-प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहरे मापदंड (27 जनवरी-02 फरवरी) पढ़ा. लगता है कि यूपीएससी हिंदीभाषी प्रतियोगियों की मेहनत पर पानी फेरना चाहती है. वह चाहती है कि हिंदी माध्यम के छात्र-छात्राएं उसकी परीक्षाओं में शामिल न हों. यह असमानता को बढ़ावा देने वाला क़दम है. यह हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों के साथ धोखा है. यूपीएससी में बदलाव बड़े शहरों और कॉन्वेंट स्कूलों के छात्र-छात्राओं को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं. आख़िर यह दोहरा मापदंड क्यों?

-पुष्कर सिंह, *इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश.*

शासन चलाने की मजबूरियां

आजकल अचानक डब्ल्यू डब्ल्यू एफ रेसलिंग की टीआरपी एकदम नीचे गिर गई है. लोगों का रुझान दिल्ली के मंत्रियों एवं विधायकों का ड्रामा देखने में बढ़ गया है. विधायक विनोद विन्नी ने तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन केजरीवाल को ही चुनौती दे दी, मुकाबला देखने वाला होगा. सोचने वाली बात यह है कि केजरीवाल का गठबंधन तो सिर्फ़ एक पार्टी से है, तो इतना समझौता! जबकि मनमोहन सिंह तो अनेक पार्टियों के गठबंधन की सरकार चला रहे हैं. शायद अब केजरीवाल को शासन चलाने की मजबूरियां समझ में आ गई होंगी. इसीलिए तो कहते हैं कि यह भारत है, विविधताओं का देश!

-अनिल शरण अग्रवाल, *ई-मेल से.*

एक सवाल

जो लोग, जैसे जावेद अख्तर एवं उनकी पत्नी शबाना आजमी, अन्य मुस्लिम लोग और कांग्रेस आदि कहते हैं कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आतंकी दल हैं, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कितने मानव बमों द्वारा निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं कीं, जितने इस्लामिक आतंकी प्रतिदिन करते हैं? इन तीनों ने कितने वायुयान गिराकर निर्दोषों सिखों की हत्याएं की?

-चंदर कोहली, *ई-मेल से.*

शर्म उनको मगर आई नहीं...

वर्ष 2014 राजनीतिक मायनों में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव है, लेकिन इस नए वर्ष के प्रथम पखवाड़े में देश के सफेदपोशों में बेशर्मी को लेकर एक होड़-सी मचती दिखी. खुद को समाजवादियों का ठेकेदार बताने वाली मुलायम सिंह एंड फैमली कंपनी ने सैफई महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपये लुटा दिए. जबकि उन्हीं के राज्य में मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को डेढ़ सौ रुपये का एक कंबल भी नसीब नहीं हुआ. उक्त दंगा पीड़ित उसी अल्पसंख्यक समुदाय के थे, जिनका रहनुमा कहलाने में समाजवादियों को बड़ा गर्व होता है. जिस समय माधुरी दीक्षित और सलमान खान अपने ठुमकों से सैफई में भारतीय लोक-संस्कृति की रक्षा कर रहे थे, ठीक उसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री एवं विधायक स्टडी टूर के नाम पर विदेश भ्रमण के लिए निकल पड़े. इन दोनों कार्यक्रमों में जनता के पैसे की खुलकर बर्बादी हुई. जिस दिन उत्तर प्रदेश के उक्त जनप्रतिनिधि स्टडी टूर के लिए विदेश रवाना हुए, उसी दिन कर्नाटक के मंत्री विदेश दौरे से वापस आए. यह वही कर्नाटक राज्य है, जहां के किसान सूखे की मार से परेशान हैं और कई किसानों ने तो आत्महत्या तक कर ली. जो पैसा कर्नाटक सरकार की तरफ़ से मंत्रियों के विदेश दौरे के लिए खर्च किया गया था, उस पैसे से राज्य में आई इस प्राकृतिक विपदा से प्रभावित लोगों का कुछ तो भला अवश्य हो सकता था.

-संजय कुमार, *समस्तीपुर, बिहार.*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

भारत की राजनीति एक नए दरवाजे पर खड़ी है

मैंने 30 जनवरी को दो रैलियां देखीं. एक रैली 30 जनवरी, 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुई थी, जिसमें अन्ना हजारे ने अपना व्यवस्था परिवर्तन का रुख देश के सामने रखा था. उस रैली में लगभग पौने दो लाख लोग आए थे और उस रैली में खर्चा सात लाख रुपये के आसपास हुआ था. दूसरी रैली मैंने 30 जनवरी, 2014 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में देखी. लगभग 20 लाख लोग परेड ग्राउंड के अंदर, 10 लाख लोग परेड ग्राउंड के आसपास और 3 लाख से 4 लाख लोग सड़कों के ऊपर परेड ग्राउंड की तरफ़ झुंड के झुंड आते हुए, लेकिन रास्ता न मिल पाने की वजह से कहें, तो रेंग रहे थे. ये दोनों रैलियां दो जननायकों की रैली थी और ये रैलियां बताती हैं कि लोग किस तरह से अपनी परेशानियों को लेकर छटपटा रहे हैं.

कोलकाता की रैली पिछले 40 सालों के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी रैली है. ममता बनर्जी को एहसास था कि 15 लाख लोग आएंगे, लेकिन लगभग 30-35 लाख लोग आएंगे, यह अंदाजा कोलकाता में किसी को नहीं था. पूरा ब्रिगेड परेड ग्राउंड खचाखच भरा, नारे लगे. लोग 24 घंटे पहले से कोलकाता में आना प्रारंभ कर चुके थे. लोग भी कौन? बंगाल के हर कोने से आए हुए लोग. कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था, जहां के लोग रैली में नहीं आए थे. रैली पूर्णतया जन-आधारित रैली थी. लोग खाने का सामान साथ लिए हुए थे. लोग बसों में आए, रेलगाड़ी से आए, पैदल आए. गाना गाते हुए आए, नाचते हुए आए. इस दृश्य को देखना इतना अभूतपूर्व था कि जनता कैसे खड़ी होती है और कैसे आकर सिंहनाद करती है, इसका वर्णन शब्दों से बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता.

मेरे इस वर्णन को कुछ लोग शायद पसंद न करें. उन्हें यह अतिश्योक्ति लगे, लेकिन उन लोगों को मैं यह बता दूं कि ऐसे दृश्य सिर्फ़ देखकर महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें शब्दों में ढाला नहीं जा सकता. कोलकाता की रैली इतनी बड़ी रैली थी कि वह कैमरे के फोकस के अंदर नहीं आ पा रही थी. पूरी रैली का एक फोटो नहीं खींचा जा सकता था. टेलीविजन के कैमरे इस रैली की विशालता को भांपने में असमर्थ साबित हो रहे थे. फिर भी कोशिश करके बंगाल के चैनलों ने इस रैली को दिखाया. शायद चैनलों ने सोचा था कि रैली इतनी बड़ी नहीं होगी. इसलिए वहां पर सिर्फ़ चंद क्रेन लगे कैमरे थे. वे कैमरे लोगों का चेहरा पढ़ने में, उनका उत्साह भांपने में और विशालता को अपने अंदर कैद करने में असमर्थ साबित हो गए थे.

इस रैली में ममता बनर्जी ने एक लंबा भाषण दिया. उस भाषण में उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम नया बंगाल बना रहे हैं, वैसे ही हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे. उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और मंच से ललकारा, दंगा पार्टी चाइ ना. यानी दंगा पार्टी नहीं चाहिए और भीड़ उत्साह से चिल्ला पड़ी, दंगा पार्टी चाइ ना, कांग्रेस चाइ ना. भीड़ ने भी पलट कर जवाब दिया, कांग्रेस नहीं चाहिए, कांग्रेस चाइ ना. ममता बनर्जी ने सारे देश में चुनाव लड़ने की घोषणा की. इसका मतलब है कि अब देश में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला होने वाला है. मुकाबला करने का दावा टीवी चैनलों के दम पर आम आदमी पार्टी भी कर रही है और दूसरी तरफ़ नीतीश कुमार वामपंथी पार्टियों और शरद पवार की कांग्रेस के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाने में लगे हैं.

दरअसल, ये सारे मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के अलावा चुनाव लड़ने की बात कहने वाले दल कितने प्रासंगिक होंगे, यह अभी देखना बाकी है. पर बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह नरेंद्र मोदी और कांग्रेस का नाम लेकर ललकारा और सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने भाजपा को दंगा पार्टी कहा, वह महत्वपूर्ण है. ममता बनर्जी का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 15 दिन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कोलकाता की एक मझोली रैली में यह आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से मिली हुई हैं और 30 जनवरी की रैली में ममता बनर्जी का यह वक्तव्य कि दंगा पार्टी चाइ ना, बुद्धदेव भट्टाचार्य के उस बयान का झूठ लोगों को बता गया.

यह समझ में नहीं आता कि क्यों राजनीति में लोग एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए राजनीतिक लड़ाई की जगह एक भ्रष्ट लड़ाई लड़ते हैं. बुद्धदेव भट्टाचार्य और पूरी वामपंथी पार्टी को अच्छी तरह से मालूम है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ हैं. इसके बावजूद उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ने की कोशिश करना बंगाल के सेक्युलर वोटों को अपनी तरफ़ मोड़ने की कोशिश माना जा सकता है, लेकिन यह ईमानदार कोशिश नहीं है. ममता बनर्जी का साथ बंगाल के लोगों ने वामपंथी शासन के ख़िलाफ़ इसलिए दिया, क्योंकि 35 सालों में प्रशासन की व्यवस्था लुंजपुंज हो गई थी. सारा प्रशासन वामपंथी कैडरों के हाथों में चला गया था और उससे सामान्य जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा था. यही बात मैंने जानने की कोशिश की और रैली में आए लोगों से बातचीत करके मुझे यह लगा कि अभी भी वे सारे सवाल, जिनके उत्तर में लोगों ने ममता बनर्जी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया, उनके दिमाग में जिंदा हैं और वे उन सवालों का सामना दोबारा नहीं करना चाहते. इसका मतलब यह है कि जैसी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई, वैसी ही जीत बंगाल के पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की हुई और शायद वैसी ही जीत अब लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की होने जा रही है.

ममता बनर्जी देश का चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर चुकीं, पर वह चुनाव लड़ेंगी कैसे? उनके सिद्धांत क्या होंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे, उनके उम्मीदवार कैसे होंगे और उन उम्मीदवारों के ऊपर लोगों को भरोसा कैसे आएगा? मुझे यह पता चला है कि ममता बनर्जी की पार्टी के महासचिव मुकुल रॉय ने एक खत अन्ना हजारे को लिखा है और उस खत में उन्होंने अन्ना हजारे के आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार किया है. उन्होंने उस खत में यह भी लिखा है कि हम इन कार्यक्रमों को देश में लागू करने में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं. तो क्या ममता बनर्जी और अन्ना हजारे मिलकर इस देश में कोई अभियान चलाएंगे? क्योंकि, अन्ना हजारे का आर्थिक कार्यक्रम किसी दल का आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, अन्ना हजारे का आर्थिक कार्यक्रम इस देश में चल रही बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था के ख़िलाफ़ जन-आधारित आर्थिक कार्यक्रम है. ममता बनर्जी ने 30 जनवरी के अपने लंबे भाषण में प्रो-पीपुल गवर्नमेंट शब्द का उद्घोष किया. इसका मतलब है कि वह दिल से अन्ना हजारे के कार्यक्रम को स्वीकार कर रही हैं. क्या आर्थिक आधार पर कोई एकजुटता देश में हो सकती है, 30 जनवरी की रैली से यही एक सवाल उठ खड़ा हुआ है.

वामपंथी पार्टियों के आर्थिक कार्यक्रम से ज़्यादा क्रांतिकारी अन्ना हजारे का आर्थिक कार्यक्रम है. वामपंथी पार्टियों से ज़्यादा देश के लोगों को अन्ना हजारे का आर्थिक कार्यक्रम समझ में आने वाला है और उस कार्यक्रम को स्वीकार करने वाली ममता बनर्जी न केवल देश की पहली मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक बड़े सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की अध्यक्ष भी हैं. यह घटना भारत की राजनीति को एक नई दिशा में ले जाने वाली साबित हो सकती है और मुझे लगता है कि शायद भारत की राजनीति एक नए दरवाजे पर खड़ी है, जहां नकली चेहरों की चमक उतरेगी और सामान्य जन की चमक आगे बढ़ेगी. ममता बनर्जी का बयान मेरी आंखों के आगे से गुजरा है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है, मैं किसी से डरती नहीं हूं और जब तक जिंदा रहूंगी, शेरनी की तरह रहूंगी.

ममता बनर्जी की रैली में 20-30 लाख लोगों का आना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास काडर नहीं है, जबकि वामपंथी दलों, जिन्होंने 20-30 साल तक शासन किया वह काडर बेस्ड पार्टी है. इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 30 लाख लोग आए तो सड़कें तो जाम हुईं, ट्रैफिक पर असर हुआ, लेकिन एक खोमचा तक नहीं लुटा. अन्ना के आंदोलन के समय भी ऐसा ही हुआ था. उस लिहाज से अगर देखें तो अन्ना के समर्थन में पूरे देश से लोग जुटे थे, लेकिन यहां तो सारे बंगाल से लोग कोलकाता आए थे, यह ममता के प्रति लोगों का विश्वास, शांतिप्रियता और अनुशासन बताता है.

ममता के जनसंपर्क का एक उदाहरण मुझे कोलकाता में मिले सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया. 26 जनवरी को ममता बनर्जी दो किलोमीटर पैदल चलते हुई भीड़ का दोनों हाथों से अभिवादन करते हुए अपने स्थान पर आकर बैठ गईं. परेड समाप्ति के बाद वह फिर उठीं और दो किलोमीटर पैदल चलते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए वहां से विदा हुईं. यह ममता का लोगों से संपर्क का नायाब उदाहरण है. दूसरी ओर दिल्ली में राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी कि वे 26 जनवरी की परेड आम जनता के साथ बैठकर देखेंगे, लेकिन उस दिन वे बिना कोई कारण बताए अति सुरक्षा वाले क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रियों के बगल में बैठकर परेड देखते हुए दिखे.

इस रैली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसे देश में न दिखाया जाना है. बंगाल के चैनल इस रैली को आद्योपांत दिखा रहे थे और चौबीस घंटे से इस रैली के महत्व के ऊपर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी हिंदी चैनल और अंग्रेजी चैनल ने इस रैली को कोलकाता से लाइव नहीं किया. नरेंद्र मोदी की रैली एक लाख की हो, 50 हज़ार की हो, 5 लाख की हो, लगातार मीडिया में सुर्ख़ियां पाती रहती है और लाइव दिखाई जाती है. राहुल गांधी की छोटी सी छोटी रैली लाइव होती है, लेकिन ममता बनर्जी की 20 से 30 लाख की रैली देश के मीडिया के लिए कोई स्थान नहीं रखती. यह मीडिया का कैसा चेहरा है, समझ में नहीं आता. टाइम्स ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि दो मिलियन की यह रैली थी यानी 20 लाख की रैली थी, लेकिन अपने अख़बार में वह संख्या नहीं छापता. वह कहता है, ह्यूज रैली. यह हमारे देश का मीडिया है. मुझे लगता है कि हमारे साथियों को भी समझने की ज़रूरत है. हमें पत्रकारिता को उस जगह नहीं ले जाना चाहिए, जहां लोग हमें देखें और देखकर हंसें. हमें देखें और हमें किसी का भोंपू मानकर हमारा मजाक उड़ाएं. हमें अपनी गरिमा और सत्य को देखने की क्षमता न केवल बरकरार रखनी चाहिए, बल्कि उसे बढ़ाना चाहिए.

बहरहाल, अगले 15 दिनों में देश में बड़े राजनीतिक परिवर्तन की संभावना है. नए गठजोड़ों की संभावना है. और, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि जो गठजोड़ आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर होगा, वही गठजोड़ देश की गद्दी की तरफ़ तेजी से अपना क़दम बढ़ाएगा, क्योंकि इस देश को बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था से, भ्रष्टाचार से मुक्ति की ज़रूरत है. यहां पर गांव को स्वावलंबी बनाना चाहिए, गांव को ताकत देनी चाहिए. ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर शहरी अर्थव्यवस्था को चलना चाहिए और शहर एवं गांव के बीच का औद्योगिक तालमेल तत्काल लागू करना चाहिए. वरना यह देश गृहयुद्ध की तरफ़ बढ़ेगा. बंगाल में 30 जनवरी को हुई तृणमूल कांग्रेस की रैली लोगों की रैली थी, लोगों का समुद्र था, लोगों की आकांक्षाओं का उद्घोष था, जिसमें ममता बनर्जी ने शेरनी की तरह दहाड़ कर कहा, दिल्ली चलो. इसलिए कि दिल्ली में मानुष सरकार चाहिए. यानी दिल्ली में इंसानों की सरकार चाहिए. देखते हैं, ममता की दिल्ली चलो दहाड़ का कोई असर होता है या फिर यह जंगल का शोर बनकर रह जाती है.■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

आंदोलनों और जनता के गुस्से ने कई बार नेताओं की सत्ता उखाड़ फेंकी है. जेपी आंदोलन के छात्र नायक लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव एवं नीतीश कुमार अब स्थापित नेता हो चुके हैं. यद्यपि किसी भी व्यक्ति को इन नेताओं के युवा आदर्शों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. आंदोलन लगातार दबावों के बीच फलते-फूलते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसमें बहुत परेशानियां सहनी पड़ती हैं. आंदोलन एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर घूमते रहते हैं.

जीत कर तंत्र को सुधारें मोदी

साठ के दशक में ज़्यादातर विकसित देशों में छात्र आंदोलन फैल गया था. वर्षों तक तेज विकास और पूर्ण रोज़गार के बाद भी इन देशों में छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था. उम्रदराज लोग इन आंदोलनों से हैरान थे. शुरुआत में लोगों ने छात्र आंदोलन को ज़्यादा तरजीह नहीं दी और बाद में उन्होंने इसके लिए छात्रों की आलोचना की. आख़िरकार उन्होंने छात्रों के आगे हार स्वीकार कर ली. वहीं अमेरिका में वियतनाम युद्ध के विरोध में हो रहे आंदोलनों की वजह से तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. फ्रांस में चार्ल्स डे गाउले को भी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इसी तरह पराग्वे में हुई क्रांति ने सोवियत संघ द्वारा एलेक्जेंडर ड्यूबेक पर लगाए गए झूठे आरोपों का मजाक बना दिया था.

हाल में उस तरह के कुछ नेताओं ने राजनीति में क़दम रखा है. कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राइन इनमें से एक हैं. सोरबोन के नायक डैनी कोहन बेंडिट इस समय एक यूरोपीय सांसद हैं. बड़ी-बड़ी सत्ताओं को उखाड़ फेंकने वाले आंदोलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं. भारत की राजनेता चुनने की अपनी एक प्रक्रिया है, जिसके तहत यहां के राजनीतिक दल अपने छात्र संगठन में युवा नेताओं को तैयार करते हैं, जो आगे चलकर पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंचने का प्रयास करते हैं. मेरी याद में, ऐसे बहुत से बड़े नेता नहीं हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की हो, लेकिन कुछ नाम लिए जा सकते हैं. कांग्रेस की बात करें, तो वह एक ऐसी पार्टी है, जिसमें नेता बनने के लिए छात्रनेता होना ज़रूरी नहीं है. इसका उदाहरण राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड है, जिसमें सभी युवराज हैं, कोई भी आम आदमी नहीं है.

आंदोलनों और जनता के गुस्से ने कई बार नेताओं की सत्ता उखाड़ फेंकी है. जेपी आंदोलन के छात्र नायक लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव एवं नीतीश कुमार अब स्थापित नेता हो चुके हैं. यद्यपि किसी भी व्यक्ति को इन नेताओं के युवा आदर्शों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. आंदोलन लगातार दबावों के बीच फलते-फूलते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसमें बहुत परेशानियां सहनी पड़ती हैं. आंदोलन एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर घूमते रहते हैं. उनके पास संतोष नामक कोई चीज नहीं होती है. 1968 में एलएसई संघर्ष के दौरान एक स्लोगन में यह लिखा भी गया था, जब तुम हमारी एक मांग पूरी कर दोगे, तो दूसरे दिन एक और नई तैयार कर देंगे. लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में क्या राय है? यहां एक ऐसा आंदोलन था, जो एक राजनीतिक पार्टी बनाने से इंकार कर रहा था. आश्चर्यजनक रूप से इसकी सरकार भी बन गई और इसने एक महीना भी पूरा कर लिया. कम समय के दौरान ही इस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय काफी विवादित रहे. रेल भवन के बाहर दिए गए धरने ने दिल्लीवासियों के धैर्य की काफी परीक्षा ली.

यह दरअसल, एक धरना न होकर एक पलायनवादी काम था. केजरीवाल कभी भी अन्ना हजारे की तरह आमरण अनशन नहीं करेंगे. वह अपनी कमियां जानते हैं और यह भी जानते हैं कि कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाए. मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि जल्द ही वह अच्छी तरह से सरकार चलाना शुरू कर देंगे. लेकिन, उनकी वह जल्दबाजी कहां है, जो वह दूसरी सरकारों से चाहते थे? आगामी आम चुनावों तक का समय उनके लिए कठिन है, उन्हें तब तक लोगों की निगाहों में बने रहना चाहिए. उनके लिए यह दूसरी सरकारों की तरह नहीं होगा, जो अपने शुरुआती सौ दिनों की कामयाबी की चर्चा करती हैं अथवा यह बताती हैं कि शुरुआती साल में उन्होंने कैसा शासन किया, क्योंकि केजरीवाल की सरकार एक आंदोलन के बाद बनी है और उससे लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं. मेट्रो के बंद हो जाने से लोगों को हुई परेशानियां देखकर स्थापित पार्टियों को खुशी मिली और उन्होंने सोचा कि अब लोग आम आदमी पार्टी को समर्थन देना बंद कर देंगे, लेकिन केजरीवाल के खेल को इस तरह समझना गलत होगा, क्योंकि लोगों का सरकारी तंत्र में विश्वास ख़त्म हो चुका है. इसके लिए यूपीए सरकार ज़िम्मेदार है. कोई भी केजरीवाल पर दोषारोपण नहीं करेगा, बल्कि लोगों की निगाह में नेता की यह आम छवि बन चुकी है कि वह अपने दर्जन भर सुरक्षाकर्मियों के साथ जनता के बीच आएगा. वह सिर्फ़ अपने समर्थकों एवं फाइनेंसरों के लिए ही काम करेगा. केजरीवाल का यह नया व्यवहार अपने आप में अलग है, ऐसा पहले कभी भाजपा या कांग्रेस ने नहीं किया है.

भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एक ऐसा बाहरी व्यक्ति है, जो कभी एक चाय वाला रहा है और उसकी तरफ़ कांग्रेसी अपनी प्राचीन ब्राह्मण विचारधारा की तिरछी निगाहों से ही देख रहे हैं. नरेंद्र मोदी के पास केजरीवाल से सीखने के लिए काफी कुछ है, अगर वह फिर से सरकारी तंत्र में लोगों का विश्वास एक बार फिर से पैदा करना चाहते हैं. उन्हें 1977 में जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बारे में ज़रूर याद करना चाहिए, जो देश में फासिस्ट शासन समाप्त करने का पहला प्रयोग था और यह प्रयास बेकार हो गया था, क्योंकि जीतने वाले लोग सिर्फ़ खुशी में मग्न हो गए थे. अब वह समय आ गया है, जब एक बाहरी व्यक्ति जीत दर्ज करे और सड़े हुए तंत्र की गरिमा फिर से स्थापित करे.■

feedback@chauthiduniya.com

कब होगी न्यायालय की अवमानना?

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

चौथी दुनिया ब्यूरो

पिछले अंक में हमने आपको आरटीआई के तहत तीसरे पक्ष के बारे में बताया था. हम उम्मीद करते हैं कि आपको लोक सूचना अधिकारी की तरफ से ऐसा जवाब मिले कि तीसरे पक्ष से जुड़े होने के कारण आपको अमुक सूचना नहीं दी सकती है, तब आप लोक सूचना अधिकारी को पत्र लिखकर उन्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपके द्वारा मांगी गई सूचना को सार्वजनिक करने से जनसाधारण को लाभ पहुंचेगा. इसके बाद फिर भी लोक सूचना अधिकारी आपकी बातों से सहमत नहीं होता है, तब आप अपने तर्कों के साथ प्रथम या द्वितीय अपील ज़रूर करेंगे.

इस अंक में हम आपको ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित बातें बता रहे हैं, जिसका संबंध न्यायालय से है और जिसके बारे में कहा जाता है कि अमुक सूचना को सार्वजनिक करने से न्यायालय की अवमानना होती है. लोक सूचना अधिकारी न्यायालय की अवमानना की बात कहकर भी कई बार सूचना देने से मना कर देते हैं. हो सकता है कई बार यह तर्क सही भी हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि लोक सूचना अधिकारी इस तर्क का ग़लत इस्तेमाल करते हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि आवेदक को न्यायालय की अवमानना की परिभाषा के बारे में जानकारी हो. इस अंक में हम आपको उदाहरण सहित यह बता रहे हैं कि न्यायालय की अवमानना कब और कैसे होती है. किन-किन परिस्थितियों में आपको सूचना देने से मना किया जा सकता है और किन-किन परिस्थितियों में नहीं. हमें उम्मीद है कि इसके बाद आप आरटीआई खूब इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे. अगर इस संबंध में आपको कोई परेशानी हो, तो हमें ज़रूर बताएं. हम हर क़दम पर आपको मदद देने के लिए तैयार हैं. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(बी) में ऐसी सूचनाएं, जिनके प्रकाशन पर किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंध लगाया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो, उसके सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाई गई है. अगर कोई मामला किसी कोर्ट में निर्णय के लिए विचाराधीन है, तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उससे संबंधित कोई सूचना नहीं मांगी जा सकती. विचाराधीन मामलों के संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक किए जाने से कोर्ट की अवमानना हो, यह ज़रूरी नहीं है. कोई विशेष सूचना, जिसे न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी हो, अगर उसे सार्वजनिक किए जाने की बात होगी तो न्यायालय की अवमानना ज़रूर होगी. गोधरा जांच के दौरान उच्च न्यायालय ने अपने एक फ़ैसले में रेल मंत्रालय को विशेष तौर पर निर्देश दिए थे कि वह गोधरा नरसंहार की जांच रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत न करे. न्यायालय ने रिपोर्ट के सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी. यह सूचना दिए जाने से कोर्ट की अवमानना भी हो सकती थी और धारा 8(1)(बी) का उल्लंघन भी. ऐसे मुद्दों पर अधिकारियों को केवल वही सूचनाएं देने से मना करना चाहिए, जिन्हें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक किए जाने से निषिद्ध कर रखा हो. कुछ मामलों में देखा गया है कि सरकारी अधिकारी इस धारा का इस्तेमाल सूचना न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं. अफरोज़ ने एम्स और दिल्ली पुलिस से बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी और दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के संबंध में जानकारी मांगी थी. जवाब में उन्हें बताया गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस संबंध में सूचना नहीं दी जा सकती, जबकि न्यायालय द्वारा सूचना सार्वजनिक न किए जाने के संबंध में दिया गया ऐसा कोई भी आदेश प्रकाश में नहीं आया.

ऐसे में सूचना आयुक्तों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है.

क्या कहता है कानून

सूचना के अधिकार क़ानून में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है. इसे समझने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 का सहारा लिया जा सकता है. अधिनियम की धारा 2(ए)(बी) और (सी) में बताया गया है,

ए दीवानी या फ़ौजदारी दोनों तरह से कोर्ट की अवमानना हो सकती है.

बी यदि किसी न्यायालय के निर्णय/डिक्री/आदेश/निर्देश/याचिका अथवा न्यायालय की किसी प्रक्रिया का जानबूझकर उल्लंघन किया जाए या न्यायालय द्वारा दिए गए किसी वचन को जानबूझकर कर भंग किया जाए, तो यह न्यायालय की दीवानी अवमानना होगी.

सी किसी प्रकाशन, चाहे वह मौखिक/लिखित/सांकेतिक या किसी अभिवेदन या अन्य किसी कृत्य द्वारा,

1) बदनाम या बदनाम करने की कोशिश या अभिकरण/न्यायालय को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए.
2) किसी न्यायिक प्रक्रिया में पक्षपात या हस्तक्षेप.
3) न्यायिक व्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तक्षेप या उसे बाधित करना/ बाधित करने की कोशिश करना न्यायालय की अवमानना हो सकती है. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301, ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

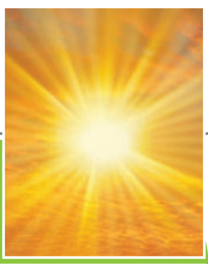

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आपकी लोकप्रियता आपको कामयाबी दिलाएगी. आपकी रचनात्मक प्रतिभा भी आपको सम्मान दिलाएगी. आप नए लोगो से मिलेंगे-जुलेंगे. कोई ऐसा, जो आपके लिए खास है, उसका व्यवहार आपके प्रति बदल सकता है. एकतरफ़ा आकर्षण से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. आपके धैर्य की परीक्षा होने वाली है. यह समय स्थिति में परिवर्तन लाने का है. अगर कोई आपको परेशान करता है, तो कुछ कहने से पहले ज़रूर सोच लें. सभी के फायदे के लिए नकारात्मकता दूर करनी होगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आप स्वयं पर गर्व महसूस करेंगे कि आपने जो चाहा, वह आपको मिल गया. आपका मित्र कोई ज़रूरी जानकारी देना भूल जाएगा. आप सावधान रहें. किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए आप अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल करें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह आप तनाव महसूस करेंगे. आपका पराक्रम बढ़ेगा. स्वास्थ्य में भी हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी, दोनों वर्ग आर्थिक रूप से मज़बूत होंगे. अब आप कोई काम करने की ठान लेंगे, तो वह ज़रूर पूरा होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आप अपने कार्यस्थल को संगठित करेंगे. इस सप्ताह संबंध मजबूत होंगे. यदि आप आत्मविश्वास से कोई कार्य करेंगे, तो वह आसान हो जाएगा. पारिवारिक सुख भरपूर मिलेगा. संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आपकी रचनात्मकता को मंच मिलेगा. कोई ऐसा काम, जिसके बारे में काफी समय से सोचते आ रहे हैं, उस पर अमल करेंगे. कोई प्रॉपर्टी, जो काफी समय से आपकी नहीं हो पा रही है, आपको मिल सकती है. वरिष्ठों एवं राजनीति से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आय के नए स्रोत बनेंगे. आपकी सकारात्मक सोच वित्तीय तौर पर मजबूत बनाने में सहायता करेगी. अपने समय को संगठित करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे तनाव न हो. लंबे समय के बाद आप किसी मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
वाहन संभल कर चलाएं, जल्दबाजी में न रहें. पारिवारिक माहौल को खुशनुमा बनाकर रखें. नौकरीपेशा और व्यापारी, दोनों वर्ग आम तौर पर खुश रहेंगे. उदार और दानी प्रवृत्ति के कारण आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
भावुकता में आकर या किसी के कहने पर निवेश न करें, यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है. सोच-विचार कर ही किसी तरह का निवेश करें. समय को संगठित करके चलें. आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
समझौता करके आगे न बढ़ें, अपने दिल की आवाज सुनकर ही कोई फ़ैसला लें. आप कुछ नए लोगों से मिलेंगे, जिनके साथ चलना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होग. सोच-समझ कर ही आगे बढ़ें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
जीवन में घटने वाली कुछ घटनाएं आपका मन खराब कर देंगी, लेकिन आपकी योग्यता हर काम में निपुणता दिलाएगी. आप बहुत ही योजनाबद्ध तरीक़े से कार्य करेंगे और सफल होंगे. आप अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत छवि सुधारने के लिए मेहनत करेंगे. कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
आप व्यक्तिगत जीवन और कार्यक्षेत्र, दोनों जगहों पर सामंजस्य बनाकर चलें. हालांकि, आप कुछ असहज महसूस करेंगे. आपकी सामाजिक एवं पारिवारिक छवि जीवन में सफलता देगी.

सोशल मीडिया विंडो

लाइक इट

जब पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर को अलग रखने का सुझाव दे सकती है तो विधायिका में बढ़ती करोड़पतियों की संख्या को देखते हुए सांसदों, विधायकों के वेतन, भत्तों, और पेंशन के मामले में क्रीमी लेयर को इनसे मुक्त रखने पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता?

वीरेंद्र जैन

पंकज शुक्ल

आम आदमी पार्टी को पहली फुर्सत में एक सर्कुलर जारी कर ऐसे सारे होर्डिंग हटाने का आदेश देना चाहिए, जो दिल्ली में पार्टी की सरकार बनने की खुशी में देश भर में टांग दिए गए हैं. अरविंद केजरीवाल को जल्द ही पार्टी को होर्डिंगलेस, बैनरलेस पार्टी बनाने का ऐलान भी कर देना चाहिए. थैक्यू करने और शुभकामनाएं देने वाले मोहल्ले के होर्डिंगछाप नेताओं से राजनीति में भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है. मनीष सिसोदिया को भी इस पर ध्यान देना चाहिए.

कार्टून क्लास

कार्टूनिस्ट पंकज के ब्लॉग से साभार

स्वीट-ट्वीट

केजरीवाल को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर क्यों नक्सल, आतंकियों, अल-गाववादियों और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले आप पार्टी का समर्थन करते हैं?

प्रकाश जावडेकर

किरण मजूमदार शॉ

भारत को चुनावी नीतियों में बदलाव की जरूरत है, इसमें नागरिक पहल को भी जोड़े जाने की भारी आवश्यकता है. सिर्फ दयाभाव से काम नहीं चलेगा.

गॉसिप गैलरी

अगर राहुल गांधी ऐसे ही बयान देते रहे तो उनकी पार्टी को जल्दी ही उनसे ऊबकर एक समिति बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा राहुल गांधी बयान बचाओ समिति और इस समिति के अध्यक्ष होंगे अपने दिग्गीराजा.

ऋतु सक्सेना

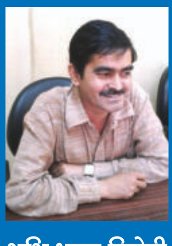
शशि भूषण द्विवेदी

आज सचमुच ज्ञानवर्धन हुआ. हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि ने फेसबुक पर टिप्पणी में बताया कि प्रेमचंद से ज्यादा महत्वपूर्ण लेखक गुरुदत्त और आचार्य चतुरसेन शास्त्री थे. संदर्भ इतिहास का है इसलिए कवि जी को कहना चाहिए था कि पी.एन ओक इरफान हबीब से बड़े इतिहासकार हैं.

पिछले महीने भारत के चेन्नई के तटीय किनारों वाले जल स्रोतों में भारत और जापान की सेनाओं ने नौसैन्य युद्धाभ्यास किया था. इसी तरह का युद्धाभ्यास दोनों देशों ने जून 2012 में जापानी जल स्रोतों में किया था. भारत–जापान का यह अभ्यास वार्षिक रूप ले चुका है. भारत और जापान के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने, भारत की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने समेत आठ समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए.

भारत-जापान संबंध

सहयोग के खुलते नए द्वार

भारत के 65वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे मुख्य अतिथि बनकर आए. जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से न सिर्फ़ भारत की रणनीतिक भागीदारी एक बार फिर से मजबूत हुई है, बल्कि दोनों देशों के प्रगाढ़ होते संबंधों पर चीन सहित अन्य विश्व शक्तियों की नज़रें भी टिक गई हैं. शिंजो अबे ने भारत के साथ आठ महत्वपूर्ण समझौते भी किए, जिसे भारत और जापान के बीच सहयोग के नए द्वार के तौर पर देखा जा रहा है. दोनों देशों के इस आपसी सहयोग से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी.

राजीव रंजन

भारत ने 26 जनवरी, 2014 को 65वां गणतंत्र दिवस मनाया. इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे. जापानी प्रधानमंत्री के साथ आए प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों के उद्यमी भी शामिल थे. भारत और जापान ने इस अवसर पर आपसी सहयोग के आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए. भारत–जापान के संबंध कभी भी बहुत अनबन वाले नहीं रहे. शिंजो अबे ने 2012 में जब दूसरी बार जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज संभाला, तब भारत और जापान के रिश्तों में और भी मिठास घुल गई. इन दोनों देशों के रिश्ते की गर्माहट का ही असर है कि दो महीने पहले जापान के उम्रदराज सम्राट अकिहितो और उनकी पत्नी ने भी भारत का दौरा किया था. यह इस मामले में खास है कि जापान के सम्राट अकिहितो बहुत कम ही कहीं जाते हैं.

ऐसा नहीं कि केवल भारत को ही जापान की ज़रूरत है, बल्कि जापान को भी भारत की आवश्यकता है. इस बात पर शिंजो अबे ने जोर दिया. शिंजो ने कहा कि जापान को मानव संसाधन की आवश्यकता है, जो भारत के पास है. उन्होंने कहा कि दवाओं के अलावा जापान के पास कृषि क्षेत्र से जुड़ी प्रौद्योगिकी भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच गठबंधन की संभावनाएं हैं. ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत जापान से फायदा उठा सकता है, क्योंकि जापान के पास सक्षम प्रौद्योगिकी है, जो कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकती है. दोनों देशों के बीच वर्ष 2011 में व्यापक मुक्त व्यापार समझौता लागू हो चुका है. जापान भारत को उसकी बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने में सहयोग दे रहा है. जापान भारत में दिल्ली–मुंबई औद्योगिकी गलियारे के विकास में भी मदद कर रहा है.

भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का झुकाव जापान के पक्ष में है. वर्ष 2012–13 में दोनों देशों के बीच 18.51 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जबकि एक साल पहले यह व्यापार 18.32 अरब डॉलर का था. भारत में जापान से अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2013 के बीच 15 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो देश में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सात प्रतिशत रहा है. जापान इस समय भारत में निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है. अप्रैल 2000 से मार्च 2013 तक भारत में जापान ने 14.5 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है. जापान भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है. वह हमारे आर्थिक विकास और शांतिपूर्ण, स्थिर एवं समृद्ध एशिया तथा दुनिया के लिए हमारे प्रयास में मुख्य भागीदार है. हमारे साझा मूल्यों और हितों में, मजबूत एवं आर्थिक रूप से सक्षम जापान और तेजी से बढ़ रहे भारत के बीच भागीदारी क्षेत्र की भलाई के लिए प्रभावी ताकत बन सकती है. बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जापान के साथ भारत के जिस तरह के राजनीतिक रिश्ते हैं, उनके आने वाले दिनों में और अधिक प्रगाढ़ होने की प्रबल संभावना है. परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग में सहयोग के लिए समझौते की दिशा में पिछले कुछ महीनों में तेजी से प्रगति हुई है.

यूएस–2 एम्फिबियन विमान पर हमारे संयुक्त कार्य समूह ने भारत में इसके उपयोग और सह–उत्पादन पर सहयोग के तौर–तरीकों की तलाश के लिए बात की है. अधिक व्यापक रूप से, हम उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं. जापान विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के लिए भारत की उन सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में विशिष्ट भागीदार है, जो हमारी सरकार ने हाल के वर्षों में शुरू की हैं. ये परियोजनाएं हैं–पश्चिमी समर्पित माल गलियारा, दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा, आईआईटी हैदराबाद और नियोजित चेन्नई–बंगलुरु औद्योगिक गलियारा. भारत ने इन फ्लैगशिप परियोजनाओं पर विचार किया है. इनके समेत भारत की कई अन्य परियोजनाओं में जापान की विदेशी निवेश सहायता ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जापान के इस सहयोग के प्रति दिल से आभार प्रकट किया है, जो यह बताता है कि जापान द्वारा की जा रही यह मदद भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इस मदद को भारत किस रूप में देखता है. जापान सरकार और वहां के औद्योगिक घरानों के लिए भारत का कितना महत्व है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि भारत में अभी भी 1000 जापानी कंपनियां काम कर रही हैं और हाल में इन कंपनियों में 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. भारत सरकार ने जापान से भारत में और अधिक निवेश करने को कहा है, क्योंकि सरकार का मानना है कि यहां निवेश की अभी काफी गुंजाइश है.

भारत और जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ–साथ ऊर्जा के क्षेत्र में एक्सपर्ट और ऊर्जा की बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों के निर्माण, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में ठोस सहयोग के लिए विचारों का आदान–प्रदान भी किया है, जिसका फायदा आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा. हाल के वर्षों में भारत और जापान के बीच पर्यटन एवं नागरिक विमानन क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है. मनमोहन सिंह ने जापान में सजायाफ्ता भारतीय कैदियों के तबादले और उनके आपराधिक मामलों पर आपसी क़ानूनी सहायता जैसे क्षेत्रों में लंबित कानूनी ढांचे को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए जापान के प्रधानमंत्री का समर्थन मांगा. भारत जापान के साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं की संभावनाएं तलाश रहा है. भारत और जापान के बीच आसियान एवं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों में काफी अच्छा समन्वय है. जापान भारत को नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना के लिए काफी सहयोग करता रहा है और जापान का यह सहयोग आगे भी जारी रहने की उम्मीद है. भारत और जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों और जी–20 जैसे सम्मेलनों के जरिये वैश्विक समृद्धि के लिए कार्य करने पर भी सहमत हुए हैं.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात के दौरान अबे ने दिल्ली मेट्रो के लिए दो अरब डॉलर का कर्ज देने की घोषणा भी की. दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों की रणनीतिक एवं वैश्विक साझीदारी को दुनिया के किसी अन्य द्विपक्षीय साझीदारी से सर्वाधिक संभावना वाला करार दिया. पिछले महीने भारत के चेन्नई के तटीय किनारों वाले जल स्रोतों में भारत और जापान की सेनाओं ने नौसैन्य युद्धाभ्यास किया था. इसी तरह का युद्धाभ्यास दोनों देशों ने जून 2012 में जापानी जल स्रोतों में किया था. भारत–जापान का यह अभ्यास वार्षिक रूप ले चुका है. भारत और जापान के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने, भारत की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने समेत आठ समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए. मनमोहन सिंह ने भारत के आर्थिक विकास में जापान को महत्वपूर्ण साझीदार बताया. बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच वीजा प्रणाली को सरल बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और इसके लिए आगे भी प्रयास जारी रखने पर सहमति जताई.

भारत और जापान के बीच बढ़ती नजदीकियां ऐसे वक्त में भी देखी जा रही हैं, जब पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीप समूहों को लेकर जापान और चीन के बीच तनाव की स्थिति है. जापान का चीन के कुछ बिंदुओं पर गहरा मतभेद है. दूसरी तरफ़ भारत का भी चीन से सीमा विवाद सहित कई अन्य बिंदुओं पर मतभेद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत और जापान के सहयोगी रिश्ते को चीन के ख़िलाफ़ देखा जाए. चीन के साथ मित्रवत संबंध भारत और चीन दोनों के हित में है और चीन से दुश्मनी की शर्तों पर भारत और जापान एक–दूसरे के क़रीब कभी नहीं आना चाहेंगे. विश्व राजनीति को आज की तारीख में दुश्मनी की नहीं, बल्कि दोस्ती की दरकार है. ज़रूरत तो इस बात की है कि भारत के चीन के साथ भी रिश्ते मधुर रहें और वह जापान के साथ भी सहयोगात्मक रवैया बनाए रखे. हालांकि जापान का चीन के साथ एक द्वीप को लेकर गंभीर विवाद है. वह द्वीप है सेनकाकू. सेनकाकू एक निर्जन द्वीप समूह है, जो पूर्वी चीन सागर में स्थित है. इस विवादित द्वीप पर जापानी झंडा फहराने को लेकर चीन एवं जापान के संबंधों में तल्खी आज भी बरकरार है. यह द्वीप समूह वर्षों से जापान के प्रशासनिक क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा जताता रहा है. चीन का कहना है कि द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले यह द्वीप समूह उसके कब्जे में था, इसलिए वह कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि यह जापान का क्षेत्र है. जापान इस द्वीप समूह को सेनकाकू कहकर पुकारता है, तो चीन इसे दियाओउ द्वीप समूह कहता है. दरअसल, इस द्वीप समूह को लेकर विवाद का मुख्य कारण इस क्षेत्र के समुद्र में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है, जिस पर दोनों देशों की नज़र है. इस मामले में भारत को कूटनीतिक रूप से जापान से क़रीबियां बढ़ानी होंगी.

ऐसा नहीं कि ये बातें यूं ही कही जा रही हैं, बल्कि जापान और उसके वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो अबे का भारत के प्रति नरम रुख का लंबा इतिहास रहा है. 2007 में लिखी अपनी पुस्तक *टुवाड्र्स अ ब्यूटीफुल कंट्री: माई विजन फॉर जापान* में शिंजो अबे ने भारत को काफी अहमियत दी है और कहा है कि आने वाले दशक में भारत और जापान का रिश्ता अगर जापान–अमेरिका का स्थान ले ले, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए.■

भारत-जापान सहयोग : क्या है खास

- जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे पहली बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने.
- भारत की वर्तमान खस्ताहाल आर्थिक स्थिति में यह काफी मददगार साबित होगा.
- भारत–जापान के सहयोगात्मक क़दम से वैश्विक पटल पर भारत की साख बढ़ेगी.
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा.
- जापान का चीन से कुछ मुद्दों पर गंभीर विवाद है. दूसरी तरफ़ हाल के दिनों में चीन ने भारतीय सीमाओं का लगातार अतिक्रमण किया है. दोनों देशों के प्रति चीन का यह रुख भारत और जापान को क़रीब आने में मददगार हो रहा है.
- जापान के सम्राट अकिहितो आम तौर पर कहीं कम ही जाते हैं, लेकिन हाल में उनका भारत दौरा उनकी नज़रों में भारत की महत्ता सिद्ध करता है.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

भारत और जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ ऊर्जा के क्षेत्र में एक्सपर्ट और ऊर्जा की बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों के निर्माण, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में ठोस सहयोग के लिए विचारों का आदान-प्रदान भी किया है, जिसका फायदा आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा. हाल के वर्षों में भारत और जापान के बीच पर्यटन एवं नागरिक विमानन क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है. मनमोहन सिंह ने जापान में सजायाफ्ता भारतीय कैदियों के तबादले और उनके आपराधिक मामलों पर आपसी क़ानूनी सहायता जैसे क्षेत्रों में लंबित कानूनी ढांचे को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए जापान के प्रधानमंत्री का समर्थन मांगा.

साई

साई बाबा ने अपने बचपन की कहानी के बारे में कुछ यूं कहा है, जब मैं छोटा था, तब जीविकोपार्जन के लिए मैं बीडगांव आया. वहां मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन एवं उम्मीद से अपना काम करने लगा. मेरा काम देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ. मेरे साथ तीन लड़के और भी काम करते थे. पहले का काम 50 रुपये का, दूसरे का 100 रुपये का और तीसरे का 150 रुपये का हुआ.

एक बार...

रहम नज़र करो अब मोरे साईं

चौथी दुनिया ब्यूरो

गीता के अनुसार, वटवृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं. इस वृक्ष के गुण पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ हैं. जड़ें जिनका कारणीभूत कर्म है, वे सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई हैं. इस वृक्ष की रचना बड़ी ही विचित्र है. न तो इसके आकार, उद्‌गम एवं अंत का ही भान होता है और न इसके आश्रय का. इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य के अमोघ शस्त्र द्वारा नष्ट करने के लिए किसी बाह्य मार्ग का अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस संसार में आवागमन से मुक्ति मिले. इस पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य दिग्दर्शक (गुरु) की नितांत आवश्यकता होती है. चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेद-वेदांत में पारंगत क्यों न हो, वह तब तक अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता, जब तक उसके सहायतार्थ कोई ऐसा योग्य पथ प्रदर्शक न मिल जाए, जिसके पदचिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गहरे गड्ढों एवं हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ जा सकता है. इसी विधि से संसार की यात्रा सुगम और कुशलतापूर्वक संपन्न हो सकती है. इस विषय में बाबा का अनुभव, जो उन्होंने स्वयं बताया, वास्तव में आश्चर्यजनक है. यदि हम उसका ध्यान पूर्वक अनुसरण करेंगे, तो हमें निश्चय ही श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी.

काशीबाई काननिटकर (साई बाबा की एक भक्त) से परिचय-पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आईं. वह यह दृढ़ निश्चय करके आई थीं कि बाबा के चरणों में बैठकर तीन दिन उपवास करूंगी. उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा, मैं होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूं. यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा, तो मेरे यहां होने का लाभ ही क्या है.

बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया और न दूसरों को करने दिया. उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, ऐसे में उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है. पहले तो आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है, भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती. यदि पेट में अन्न की शीतलता न हो, तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे. इसका मतलब यह कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ठ भोजन एवं शांति की प्राप्ति होती है, जब वे बलिष्ठ रहती हैं, तब ही हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं, इसलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए और न ही अधिक भोजन. भोजन में संयम रखना शरीर और मन, दोनों के लिए उत्तम है.

काशीबाई काननिटकर (साई बाबा की एक भक्त) से परिचय-पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आईं. वह यह दृढ़ निश्चय करके आई थीं कि बाबा के चरणों में बैठकर तीन दिन उपवास करूंगी. उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा, मैं होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूं. यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा, तो मेरे यहां होने का लाभ ही क्या है. दूसरे दिन जब श्रीमती गोखले दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण-कमलों के समीप बैठीं, तो बाबा ने तुरंत कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है? दादा भट के घर जाकर पूरनपोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ. वे होली के दिन थे और उस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थीं. दादा भट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी. श्रीमती गोखले ने दादा भट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया. कितनी सुंदर साई कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा.

बाबा के सरकार

साई बाबा ने अपने बचपन की कहानी के बारे में कुछ यूं कहा है, जब मैं छोटा था, तब जीविकोपार्जन के लिए मैं बीडगांव आया. वहां मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन एवं उम्मीद से अपना काम करने लगा. मेरा काम देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ. मेरे साथ तीन लड़के और भी काम करते थे. पहले का काम 50 रुपये का, दूसरे का 100 रुपये का और तीसरे का 150 रुपये का हुआ. मेरा काम उन तीनों से दो-गुना हो गया. मेरी चतुराई देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ. वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था. उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की. मेरे पास वह पोशाक वैसी ही रखी रही. मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित है, वह नाशवान एवं अपूर्ण है, लेकिन जो कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा, वही अंत तक रहेगा. किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है.

मेरे सरकार कहते हैं, ले जाओ, लेकिन लोग मेरे पास आकर कहते हैं, मुझे दो, मुझे दो. जो कुछ मैं कहता हूं, उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता. मेरे सरकार का खजाना (आध्यात्मिक भंडार) भरपूर है और वह ऊपर से बह रहा है. मैं तो कहता हूं कि खोदकर गाड़ी में भरकर ले जाओ. जो सच्ची मां का लाल होगा, उसे स्वयं ही भरना चाहिए. मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है. मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा और फिर यह अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा. मैं चाहे कहीं जाता हूं या कहीं बैठता हूं, लेकिन माया फिर भी मुझे कष्ट पहुंचाती है. इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूं. कोई जो कुछ भी करता है, एक दिन उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होगा और जो मेरे इन वचनों को स्मरण रखेगा, उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

सावधानी और जागरूकता की ज़रूरत

डॉ. अभय बंग

अस्वाद अर्थात स्वाद न लेना. स्वाद अर्थात रुचि. जिस तरह से दवा लेते वक्त, दवा स्वादिष्ट है या नहीं, इसका विचार न करते हुए, बल्कि शरीर को उसकी ज़रूरत है, ऐसा सोचकर निश्चित परिमाण में खाते हैं, ठीक वैसा ही अन्न के विषय में सोचना चाहिए. शरीर के पोषण के लिए आवश्यक न होते हुए भी मन को ठगने के लिए, यह आवश्यकता है, ऐसा कहकर कोई चीज (स्वाद के लिए) भोजन में डालना मिथ्याचरण ही तो हुआ.

इस तरह विचार करने में हमें दिखाई देगा कि हमारे खाने-पीने में ऐसी अनेक वस्तुए हैं, जो अनावश्यक होने की वजह से त्याज्य हैं और इस तरह अनेक वस्तुओं का त्याग जो अत्यंत स्वाभाविक रूप से करेगा, उसके विकार शांत होंगे. इस विषय की ओर इतना कम ध्यान दिया गया है कि व्रत की दृष्टि से अन्न का चुनाव करना क़रीब-क़रीब असंभव हो गया है. इसके अलावा बचपन से ही माता-पिता झूठे प्रेम के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के जिह्वा-विलास कराकर शरीर को बिगाड़ देते हैं और जुबान को अनियंत्रित कर देते हैं. इसका परिणाम यह होता है कि बढ़ती हुई पीढ़ी शरीर से रोगी एवं रुचि के मामले में अतिशय बिगड़ी हुई दिखाई देती है. इसके कटु परिणाम क़दम-क़दम पर दिखाई देते हैं. अनेक खर्चों को हम आमंत्रित करते हैं, वैद्य-डॉक्टरों के पीछे पड़ते हैं और शरीर एवं इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने के बजाय उलटे उनके ही गुलाम बनकर किसी पंगु के समान जीवन व्यतीत करते हैं.

अस्वाद व्रत का महत्व यदि आपको जंचा हो, तो उसका पालन करने के लिए आपको नए उत्साह से लग जाना चाहिए. उसके लिए चौबीसों घंटे खाने का विचार करते रहने की आवश्यकता नहीं. केवल सावधानी एवं जागरूकता की आवश्यकता होती है. ऐसा करते रहने से थोड़े ही समय में कब हम स्वाद के लिए और कब शरीर के पोषण के लिए खाते हैं, यह समझ में आने लगेगा. एक बार यह समझ में आने पर हमें दृढ़तापूर्वक स्वाद कम करते जाना चाहिए. सच पूछो, तो आदर्श स्थिति में, भोजन पकाने के लिए आग की आवश्यकता कम से कम अथवा शायद बिल्कुल ही नहीं है. सूर्य रूपी महान अग्नि जिन वस्तुओं को पकाता है, उसी में से हमें अपने भोजन का चुनाव करना चाहिए और इस दृष्टि से विचार करने पर, मनुष्य केवल फलाहारी है, ऐसा ही सिद्ध होता है, लेकिन इतनी गहराई में जाने की हमें आवश्यकता नहीं. यहां तो अस्वाद व्रत से क्या तात्पर्य है, उसमें कौन-कौन सी अड़चनें हैं अथवा नहीं भी हैं और

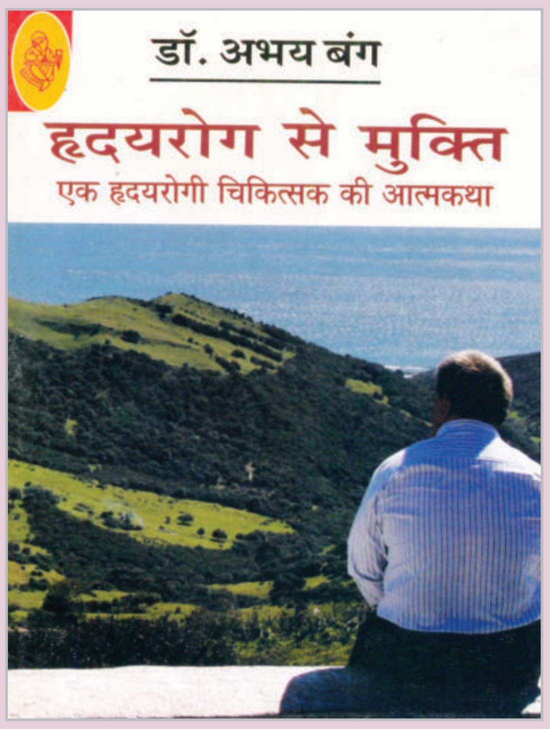

ब्रह्मचर्य पालन से उसका कितना निकट का संबंध है, इसी का विचार करना था. मन में यह जंच जाए, तब सभी को यथाशक्ति इस व्रत में पूर्णता प्राप्त करने का शुभ प्रयत्न करना चाहिए.

–महात्मा गांधी, मंगल प्रभात.

फाइबर

मैं वर्ष 1975 में चंडीगढ़ में पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तब विश्व प्रसिद्ध सर्जन डॉ. डेनिस बर्किट वहां आए. अफ्रीका में किए गए उनके रिसर्च कार्य एवं बर्किट लिम्फोमा नामक कैंसर की खोज के कारण उनकी कीर्ति फैली हुई थी. इंस्टीट्यूट में दिए गए भाषण के प्रारंभ उन्होंने पर्दे पर एक स्लाइड दिखाई, जिसे देखकर सारे डॉक्टर नाक सिकोड़ कर हंसने लगे. अफ्रीका के एक आदिवासी की विष्ठा और यूरोप-अमेरिका के गोरे आदमी की विष्ठा उस स्लाइड में दिखाई गई थी. अफ्रीकन आदमी की विष्ठा आकार में खूब बड़ी थी. नरम होने की वजह से गोबर की तरह वह ज़मीन पर फैली हुई थी, जबकि गोरे आदमी की विष्ठा निचुड़ी हुई, पत्थर की तरह थी.

ये दो प्रकार की विष्ठाएं कैसे दो प्रकार की सभ्यताओं की सूचक हैं, यह बात डॉ. बर्किट ने हमें समझाई. अफ्रीकन एवं भारतीय ग्रामीण लोग भोजन में मुख्यत: अनाज, दालें, कंदमूल एवं सब्जी इत्यादि खाते हैं (थे!), जिससे उनकी विष्ठा मात्रा में अधिक, नर्म एवं गीली होती है. उन्हें साधारणत: दिन में दो बार शौच जाना पड़ता है. इसके विपरीत गोरे (अथवा आधुनिक शहरी) मनुष्य के आहार में बदलाव के कारण विष्ठा कड़ी, थोड़ी एवं शुष्क हो जाती है. दो-तीन में एक बार शौच जाने से भी काम चल जाता है. विष्ठा सूखी होने की वजह से शौच के बाद मात्र कागज से पोंछने से भी काम चल जाता है. आधुनिक जीवनशैली की वजह से आहार में निम्न बदलाव हुए, जिनसे विष्ठा में उक्त परिवर्तन आए-मैदे की वस्तुएं, शक्कर, फैट्स, प्राणीज प्रोटीन्स एवं दूध.

इनका अनुपात बढ़ने से आधुनिक मनुष्य के आहार में से नैसर्गिक फाइबर (तंतु अथवा रेशे वाले पदार्थ) कम हो गए. ये फाइबर आहार के साथ जब आंत में जाते हैं, तो इनका अंतड़ियों द्वारा रक्त में शोषण नहीं होता. साथ ही वे अपने साथ पानी को पकड़े रहते हैं. अंत में पकड़े हुए पानी के साथ ये फाइबर्स शौच के रूप में बाहर निकल आते हैं. इसलिए विष्ठा गीली और नरम होती है. इसके अलावा ये फाइबर कॉलस्ट्रॉल को पकड़ कर रखते हैं, अतएव शौच के साथ वह भी बाहर निकल जाता है. आधुनिक मानव के आहार में फाइबर कम हो गए, विष्ठा कड़ी हो गई और इसी कारण शौचगृह में टॉयलेट पेपर आ गए. शौच का यह फर्क मात्र शौचालय में शरीर को पानी से धोना या कागज से पोंछना तक ही सीमित हो, तो चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बर्किट ने आहार में फाइबर के अभाव से शुरू होने वाले रोगों के एक समुच्चय (सिंड्रोम) का विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया. यह सिंड्रोम काफी हद तक सिंड्रोम एक्स जैसा था. आहार में फाइबर की कमी से और कड़ी विष्ठा विष्ठा वाली सभ्यताओं के लोगों को होने वाले रोगों की सूची इस प्रकार है, हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, पित्ताशय में पथरी, हॉर्निया, अपेंडिसाइटिस, पाइल्स, व्हेरीकोज व्हेंस एवं आंतों का कैंसर. अगर आधुनिक सभ्यता के इन रोगों से मुक्ति पानी हो, तो आहार में फाइबर बढ़ाइए, यह सलाह देकर डॉ. बर्किट चले गए.

भारत के पारंपरिक लोगों को कब्ज की बहुत चिंता रहती है. वे जब अपनी शौच का सूक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन करते हैं, तब हम डॉक्टरों को लगता है कि उन्हें न्यूरासिस है, वे शौच के संबंध में अतिशय चिंताग्रस्त हैं. वस्तुत: उनकी चिंता का बर्किट ने वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था. विनोबा जी ने एक जगह लिखा है, प्रभाते मल दर्शनम. सबेरे उठकर शौच जाओ और अपने मल का भलीभांति निरीक्षण करो. वह हमारे स्वास्थ्य की स्थिति का आईना है. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

मूर्ख ब्राह्मणी का पछतावा

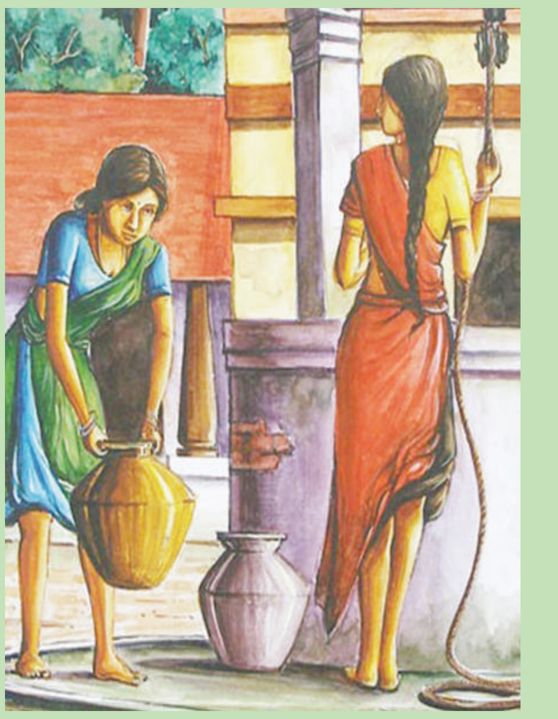

एक गांव में एक धार्मिक ब्राह्मण रहता था. उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी. उसने मन बहलाने के लिए एक नेवला पाल लिया था. नेवले को ब्राह्मण के घर में घूमने-फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी. ब्राह्मणी को नेवला बहुत अधिक प्यारा था. कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी के घर एक बेटे का जन्म हुआ. ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमारे संतान हो गई है, इसलिए नेवले को घर से निकाल दो. कहीं ऐसा न हो कि नेवला बच्चे का नुकसान कर दे. ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात नहीं मानी. एक दिन ब्राह्मणी कुएं पर पानी भरने गई. बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला पालने के पास आराम कर रहा था. इतने में किसी तरफ़ से घर में एक सांप आ गया. वह बच्चे की ओर काटने को बढ़ा. नेवले ने यह सब देख लिया. नेवला सांप का शत्रु होता है. नेवले ने सांप के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. घर में खून ही खून हो गया. नेवले ने बच्चे की जान बचा ली, यह दिखाने के लिए वह घर के दरवाजे पर आ बैठा. ब्राह्मणी जब कुएं से पानी भरकर लौटी, तब उसने खून से लथपथ नेवले को दरवाजे पर देखा. वह नेवले को देखकर घबरा गई और यह समझी कि उसने बच्चे को मार डाला है. इसलिए गुस्से में ब्राह्मणी ने नेवले पर पानी भरा घड़ा दे मारा. इसके बाद वह रोती हुई घर के अंदर गई. वहां उसने देखा कि बच्चा पालने में सो रहा है और पास में सांप मरा हुआ पड़ा है. यह देखकर वह अपनी भूल पर बहुत पछताने लगी. शिक्षा: कोई भी काम सोच-समझ कर अंजाम देना चाहिए. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

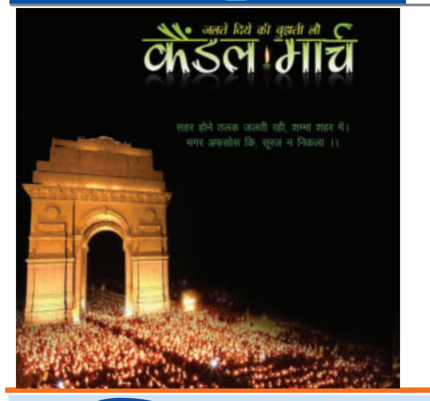

कैंडल मार्च, कितने दीप जलाऊं, पीड़ित कौन, अभियुक्त बनाम दोषी, आंदोलनकारी हाज़िर हों, ख़तरे में लोकतंत्र: नेतृत्वहीनता, लाइन हाज़िर, टीआरपी के खेल में पत्रकारिता फेल, दशहरे का मेला, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, बदल रहा है देश, ढाक के तीन पात जैसे शीर्षकों तले लेखक ने उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की, जिन पर उनकी नज़र गई. देश की न्याय व्यवस्था के ढीलेपन एवं उसकी खामियों पर रोशनी डालते हुए लेखक कहते हैं, किसी पीड़ित को न्याय मिले, यह एक सभ्य समाज के भविष्य की अनिवार्य शर्त एवं शासन का दायित्व है, जिसमें संभवत: हम विफल रहे हैं.

नियमित हो तो बात बने

अनंत विजय

मैं ने चौथी दुनिया के अपने इस स्तंभ में कई बार हिंदी में निकल रही साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा है. पाठकों ने पिछले अंक में पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य में साहित्यिक पत्रिकाओं को निकालने के पीछे किस तरह से बाज़ार को भुनाने की चाहत बढ़ती जा रही है. मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि बाज़ार का अपने पक्ष में उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन बाज़ार को कोसना और फिर उसका ही इस्तेमाल करना मुझे साइकोफैंसी लगता है. बाज़ार के विरोध की आड़ में जिस तरह से यह खेल खेला जा रहा है, उसे पाठकों के सामने बेनकाब करने की ज़रूरत है. ऐसी पत्रिकाओं की संख्या थोड़ी ही है, लेकिन वे बिगाड़ने और पाठकों को भ्रमित करने के लिए काफी हैं. ज़रूरत इस बात की है कि हिंदी जगत खड़ा होकर यह कहने की हिम्मत जुटाए कि अमुक पत्रिका अमुक मकसद से निकल रही है. मेरे कहने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हिंदी में निकलने वाली सभी साहित्यिक पत्रिकाएं इस खेल में शामिल हैं. हिंदी में अब भी कई पत्रिकाएं बेहद गंभीरता से निकल रही हैं, कुछ व्यक्तिगत प्रयासों से, तो कुछ सांस्थानिक पूंजी के सहारे.

ऐसी ही दो पत्रिकाएं हैं, तद्भव और आलोचना. तद्भव को कथाकार–उपन्यासकार अखिलेश बेहद श्रमपूर्वक सालों से बगैर किसी संस्थागत पूंजी की मदद के निकाल रहे हैं और आलोचना तो राजकमल प्रकाशन से अरुण कमल के संपादकत्व एवं नामवर सिंह जी की रहनुमाई में निकल रहा है. अभी हाल में तद्भव और आलोचना, दोनों ही पत्रिकाओं का नया अंक आया है. आलोचना का समीक्ष्य जुलाई–सितंबर 2013 अंक सहस्त्राब्दी अंक (50) है. आलोचना लंबे समय से निकल रही है और इस पत्रिका की हिंदी के पाठकों के बीच साहित्यिक रुचि एवं संस्कृति विकसित करने में अहम भूमिका है. शिवदान सिंह चौहान से लेकर नामवर सिंह तक इसके संपादक रहे हैं. इन दिनों नामवर जी इसके प्रधान संपादक हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एवं वरिष्ठ कवि अरुण कमल इसके संपादन का दायित्व संभाल रहे हैं. पत्रिका की आवर्तिता लगभग ठीक होने के बावजूद समय से थोड़ा पीछे चल रही है, जैसे समीक्ष्य सहस्त्राब्दी अंक जुलाई–सितंबर 2013 का अंक है. सहस्त्राब्दी अंक के संपादकीय में अरुण कमल ने बेहद विनम्रतापूर्वक कहा है, आलोचना का मुख्य काम श्रेष्ठ की पहचान कर, उसके मूल्य को स्वीकार्य बनाना है. साथ ही ऐसे वातावरण, ऐसे समाज की रचना में अपना योग देना है, जो श्रेष्ठ को पोषण प्रदान करे. ऐसे समाज का निर्माण, जहां रोटी और कविता में सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो.

अब कवि हैं, तो आत्मा तो थोड़ी कविता की ओर झुकी ही होगी, लेकिन बेहतर होता कि संपादक यह कहता कि रोटी और साहित्य में सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो. इसके अलावा साहित्य को रोटी से जिस तरह अरुण कमल ने जोड़ा है, उसे वह थोड़ा और विस्तार देते, तो आलोचना के आम पाठकों के लिए समझना आसान होता. अरुण कमल का गद्य भी पद्य की ही तरह मोहक होता है. इसके अलावा अपने संपादकीय में अरुण कमल ने बड़े बोल नहीं बोले हैं. वह कहते हैं, हम यह नहीं कहते कि यहां जो भी प्रकाशित हुआ, वह सब मूल्यवान ही है या श्रेष्ठ ही है, लेकिन पचास ऐसी प्रस्तुतियां भी मिलें,

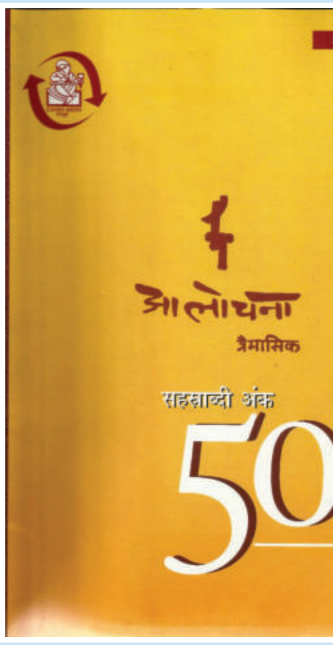

अब कवि हैं, तो आत्मा तो थोड़ी कविता की ओर झुकी ही होगी, लेकिन बेहतर होता कि संपादक यह कहता कि रोटी और साहित्य में सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो. इसके अलावा साहित्य को रोटी से जिस तरह अरुण कमल ने जोड़ा है, उसे वह थोड़ा और विस्तार देते, तो आलोचना के आम पाठकों के लिए समझना आसान होता.

तो हम धन्य होंगे. अब इस वाक्य में ही शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है. सिर्फ़ ही लगाकर संपादक ने विनम्रता के साथ अपने दावे को पेश कर दिया है. इस बात का हक भी उन्हें है, क्योंकि आलोचना में सैकड़ों ऐसे लेख एवं कविताएं प्रकाशित हुए हैं, जिनकी गूंज लंबे समय तक हिंदी साहित्य में सुनाई देती रही है. समीक्ष्य अंक में लेख स्तरीय हैं, लेकिन इस बार ज़्यादातर कविताएं औसत हैं. संपादक और सह–संपादक, दोनों अच्छे कवि हैं, लिहाजा यह कमी खटकती है.

तद्भव के इस अंक में अखिलेश ने साहित्य और राजनीति को मिलाकर अपने संपादकीय में पेश किया है. अपने सारगर्भित संपादकीय में अखिलेश ने हिंसा और घृणा को अपने तरीके से परिभाषित किया है. उनका मानना है कि घृणा की बिसात पर होने वाली हिंसा ज़्यादा भयानक और गहन होती है. वह इसके लिए नरेंद्र मोदी के मशहूर कुत्ते के पिल्ले वाले बयान का उदाहरण देते हैं. अखिलेश का मानना है कि मुगलों ने राज्य–सत्ता का विस्तार करने के लिए हिंसा का सहारा अवश्य लिया था, लेकिन बाद में अपना शासन स्थापित कर वे वैमनस्यता भूल गए थे. अखिलेश इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि हिंसा और घृणा के ख़िलाफ साहित्य की कला कोई प्रतिरोध नहीं कर रही है. अखिलेश की विचारधारा ज्ञात है और इस वजह से उनके संपादकीय में अमेरिका की घृणा और युद्धोन्माद तो दिखाई देता है, लेकिन वह रूस या फिर पश्चिम बंगाल में वामदलों के शासनकाल में सरकारी हिंसा पर टिप्पणी करने से बच निकलते हैं. संभवत: वह यह सोचते हों कि रूस या बंगाल में जो हिंसा हो रही है, वह मुगलों की तरह है, जो अपना आधिपत्य स्थापित कर वैमनस्यता भूल जाती है. लेकिन, इतना अवश्य है कि राजेंद्र यादव के निधन के बाद हिंदी में इस तरह के तीखे संपादकीय लिखने वाले अखिलेश अकेले लेखक बचे हैं.

अब तद्भव चूंकि अनियतकालीन है, लिहाजा संपादकीय पढ़ने का अवसर भी तय वक्त पर नहीं मिल पाता है. वीरेंद्र यादव तद्भव में संपादकीय की तरह ही स्थायी हैं. इस बार भी उन्होंने अतिया हुसैन पर लिखा है. वीरेंद्र यादव को पढ़ना हमेशा से रुचिकर होता है. बीच–बीच में जब वह अपने पूर्वाग्रहों पर जाते हैं, तो अतार्किक हो जाते हैं, लेकिन इस लेख में वह इस फैलेसी के शिकार नहीं हैं. तद्भव के इस अंक में गरिमा श्रीवास्तव का मलयालम स्त्री आत्मकथा पर लिखा लेख बेहतरीन है. अपने इस शोधपूर्ण लेख में गरिमा ने हिंदी के पाठकों का मलयालम में लिखी गई आत्मकथाओं से परिचय कराया है. मैं जब इस अंक को पढ़ रहा था, तो मन के किसी कोने–अंतरे में यह बात थी कि शायद गरिमा ने सिस्टर जेसमी की आत्मकथा पर न लिखा हो, लेकिन लेख ने मेरी आशंका गलत साबित की. उन्होंने सिस्टर जेसमी की आत्मकथा–आमीन को उभारा है. इसके अलावा इस अंक में उपासना और शिवेंद्र की लंबी कहानियां हैं. कुंवर नारायण, ऋतुराज, चेतन क्रांति और सुंदर चंद ठाकुर की कविताएं हैं. तुलसीराम की आत्मकथा तो लंबे वक्त से चल ही रही है, जो इस अंक में भी जारी है. कुल मिलाकर अखिलेश के संपादन में निकलने वाली पत्रिका तद्भव हिंदी साहित्य में एक अलग और ऊंचे स्थान पर स्थापित है. मैं पहले भी कई बार यह बात कह चुका हूं कि अखिलेश को यह पत्रिका नियमित करनी चाहिए. अगर मासिक निकालना संभव नहीं है, तो कम से कम द्वैमासिक तो निकालना ही चाहिए. मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पूरा हिंदी साहित्य अखिलेश को रचनात्मक सहयोग करेगा. ■

(लेखक आईबीएन–7 में डिप्टी एडिटर हैं)

anant.ibn@gmail.com

कविताएं

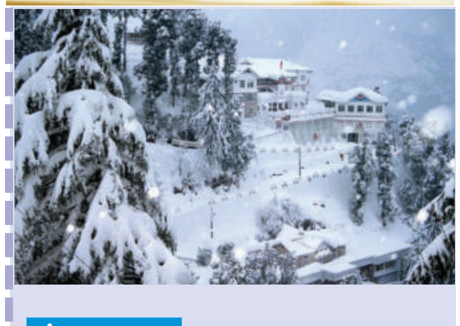

कंचन पाठक

किसने दी ऋतु में बर्फ घोल

ठिठुरी धरणी ठिठुरा–सा गगन
तरुवल्लरी भी स्तब्ध गहन
सहमे से विहग नभचर अक्रांत
टुक ताक परिभ्रमित धुंध सघन
भूले से निज कूजन किल्लोल
किसने दी ऋतु में बर्फ घोल!
कली क्लांत सुकोमल खिल न सकी
निद्रित उषा रवि से मिल न सकी
कोहरे से ढंका उज्जवल अंबर
शशिधर की छटा भी खिल न सकी
चले मलयानिल भी सिहर–सिहर
अदृश्य कहीं रवि रश्मि लोल
किसने दी ऋतु में बर्फ घोल!

प्रभु अग्निदेव तुम धन्य–धन्य
लगे तुम–सा न प्रियकर कोई अन्य
बरखा–सी टपकती ओस बूंद
दशों दिशा प्रकंपित शीत जन्य
हिमशैल–सी यामिनी दीर्घ हो चली
दिनमान धरे पग नाप–तोल
किसने दी ऋतु में बर्फ घोल!

****

मैं जाग रही ...

कृष्ण पक्ष की
भयप्रद विभावरी
चहुंओर नि:स्तब्ध
घनघोर ध्वान्त!
सभी विटप, तरु
सो रहे गहन
निद्रा में लीन
बेसुध विश्रांत!
मैं जाग रही सखि
यादों के संग
कुछ संस्मरण
करें चित्त विभ्रांत!!

****

तुम सुनते तो होगे

कौन से नाम से
बुलाऊं तुम्हें?
अंतरात्मा के
सहस्त्र–कंठ–नि:सृत
प्रत्यावाहन
तुम तक पहुंचते तो होंगे...
इन सजल नेत्रों में लहराते
प्रेमाश्रुओं से प्रस्पुरित
उदधि की लहरें
तुम्हारे पद–पद्मों को
पखारती तो होंगी...
ओ मेरे आत्मस्वरूप!
तन से, अंतर्मन से
श्वांस–प्रश्वांस से
उर–प्राण से
तुम्हें पुकारती
इन स्वर–लहरियों को
तुम सुनते तो होगे ना?

pathakkanchan239@gmail.com

किताब मिली

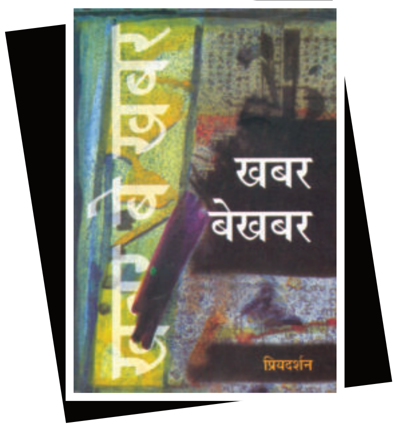

पुस्तक	लेखक
ख़बर बेख़बर	प्रियदर्शन
प्रकाशक	**मूल्य**
सामयिक बुक्स, नई दिल्ली	360 रुपये

वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन की यह किताब उनके लेखों का संग्रह है. पुस्तक की चिंता में अपने समय की पत्रकारिता और तेज विकास का समय तो है ही, पत्रकारिता और इससे जुड़े संस्थानों की मूलभूत ज़रूरत भी है. यही कारण है कि लेखक न सिर्फ़ अपने समय के बदलावों को महसूस कर रहा है, बल्कि उन्हें पाठकों तक पहुंचा भी रहा है. इस पुस्तक की खास बात यह है कि लेखक के भीतर का पत्रकार–स्तंभकार निष्कर्षों तक पहुंचने की जल्दी में नहीं है. वह सहज तर्कों के जरिये पत्रकारिता के कुछ ज़रूरी आयामों की तलाश करता है. इस प्रक्रिया में वह पाठकों को भी अपनी चिंता में शामिल कर लेता है. पत्रकारिता के छात्रों के लिए यह पुस्तक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक समीक्षा

...और तभी सार्थक होगा मोमबत्तियों का जलना

महेंद्र अवधेश

भ्रष्टाचार तो हम भारतीयों के रक्त में सम्मिलित हो गया है. इसे हमारे समाज ने सहजता से स्वीकार कर लिया है. हम ले–देकर काम कराने के आदी हो गए हैं. शॉर्टकट ढूंढने में मसरूफ हो गए हैं, हम जुगाड़ू हो गए हैं और सच कहें कि हम जुगाड़ुओं को अहमियत भी देने लगे हैं. आज के बाज़ार में ईमानदारों की तुलना में जुगाड़ुओं को अधिक क़ीमत मिलती है...

आपको लग रहा होगा कि उक्त बातें किसी बड़े राजनीतिक–सामाजिक नेता के भाषण का हिस्सा हैं, लेकिन नहीं, ये बातें किसी व्यक्ति विशेष के भाषण का अंश कतई नहीं हैं, बल्कि हाल में प्रकाशित पुस्तक–जलते दिये की बुझती लौ: कैंडल मार्च के चौथे अध्याय–अभियुक्त बनाम दोषी से उद्धृत हैं, जिसमें इस पुस्तक के लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल कुमार ने बताया है कि हम और आप भी, अपने सामने होने वाले अन्याय, अराजकता, अमानवीयता, बेईमानी, चोरी और अन्य दूसरे तरह के अनुचित कामों एवं गतिविधियों को बड़ी लापरवाही के साथ न केवल नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि कभी–कभी खुद उसके हिस्से भी बन जाते हैं. पिछले दिनों हुए जनांदोलनों और कई अन्य राजनीतिक–सामाजिक मुद्दों को लेकर लिखी गई यह पुस्तक हमें बताती है कि भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के लिए सिर्फ़ ऐसा करने वाला ही दोषी नहीं होता है, बल्कि हम भी उसमें बराबर के कुसूरवार होते हैं, चाहे ऐसा जानते हुए हो अथवा अनजाने में. प्रफुल्ल कुमार की यह पुस्तक अपने 12 अध्यायों के अंतर्गत कई गंभीर बिंदुओं पर न केवल चर्चा करती है, बल्कि हमें उन पर चिंतन–मनन के लिए भी प्रेरित करती है.

दरअसल, किसी भी पुस्तक का ध्येय तब पूरा होता है, जब वह अपने संदेश को पाठकों तक उनकी भाषा में, उन्हीं की सरलता के अनुरूप पहुंचा दे. पाठकों को लगे कि यह तो वही बात है, जो वे भी सोचते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पाते. इस प्रकार उन्हें संतुष्टि मिलती है कि उनकी सोच की दिशा सही है और उन्हें

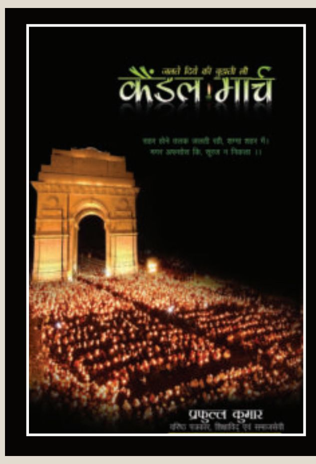

समीक्ष्य कृति
जलते दिये की बुझती लौ: कैंडल मार्च
लेखक
प्रफुल्ल कुमार
प्रकाशक
डायमंड बुक्स, दिल्ली
मूल्य
125 रुपये

यह भी मालूम हो जाता है कि अपनी बात अपने ही शब्दों में दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है और किस तरह. कैंडल मार्च को लिखते समय प्रफुल्ल कुमार ने पाठकों तक अपना संदेश पहुंचाने का ध्येय सर्वोपरि रखा और शायद यही कारण है कि उन्होंने ज़मीन से जुड़े मसलों पर आमजन की भाषा में बात की और वह भी ज़मीन पर खड़े होकर. आमुख में वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश असीम ने अक्षरश: सही कहा है कि वास्तव में प्रफुल्ल जो हैं, वहीं दिखते हैं और उनके मन में जो बातें आती हैं, उन्हें वह बिना कोई परवाह किए कह जाते हैं. उन्हें अपने विचार के संग अकेले पड़ जाने का मलाल नहीं है.

कैंडल मार्च, कितने दीप जलाऊं, पीड़ित कौन, अभियुक्त बनाम दोषी, आंदोलनकारी हाज़िर हों, ख़तरे में लोकतंत्र: नेतृत्वहीनता, लाइन हाज़िर, टीआरपी के खेल में पत्रकारिता फेल, दशहरे का मेला, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, बदल रहा है देश, ढाक के तीन पात जैसे शीर्षकों तले लेखक ने उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की, जिन पर उनकी नज़र गई. देश की न्याय व्यवस्था के ढीलेपन एवं उसकी खामियों पर रोशनी डालते हुए लेखक कहते हैं, किसी पीड़ित को न्याय मिले, यह एक सभ्य समाज के भविष्य की अनिवार्य शर्त एवं शासन का दायित्व है, जिसमें संभवत: हम विफल रहे हैं. कोई अपराधी किसी व्यक्ति विशेष का शत्रु नहीं, बल्कि समाज का शत्रु होता है, किंतु हमारे देश में यह प्रथा अब तक चलन में नहीं है. इसलिए आम तौर किसी अपराध का दोषी उस अपराध के पीड़ित का शत्रु मात्र समझा जाता है, जिसे सजा दिलाने के लिए पीड़ित संघर्ष करता है और जब यह संघर्ष दीर्घकालीन होने लगता है, तो पीड़ित टूटने लगता है और ऐसे में वह उस सीमा रेखा को भी कई बार लांघ जाता है, जो अभियुक्त और पीड़ित के बीच होती है और तब पीड़ित स्वयं अन्य मामले में अभियुक्त होता दिखता है.

पुस्तक में ऐसे कई विचार–बिंदु हैं, जो हमारे क़रीब होकर भी आज तक अनछुए रहे, जिन्हें लेखक ने बखूबी पकड़ा. समाज में महिलाओं की हालत को लेकर उन्होंने कहा कि जो अपने गर्भ में हमें नौ–दस माह तक रख सकती है, वह अबला कैसे हो सकती है? लेखक कहता है कि जब समाज में वर (दूल्हे) खरीदे जाते हैं, तो ऐसे में बेटी के कन्यादान की रस्म का क्या औचित्य है? एक जगह लेखक ने पुलिसकर्मियों की मनोदशा का वर्णन किया है, वह भी काव्यात्मक, शीर्षक है लाइन हाज़िर. इसे पढ़कर आप कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार पुलिसकर्मियों के मन में चलने वाली उथल–पुथल को बखूबी समझ सकते हैं. बहुत आशावादी दृष्टि रखते हुए लेखक का मानना है कि हमारी व्यवस्था में जो खामियां हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है, बशर्ते हम इसके लिए खुद को तैयार कर सकें. प्रफुल्ल सच कहते हैं, क्योंकि यह हमारी फितरत है कि जब कोई अन्य शख्स कहीं कुछ अनुचित कार्य करता है, अपने कर्तव्य से दूर भागता है, भ्रष्ट आचरण करता है, तो वह हमारी नज़र में सहज ही दोषी हो जाता है, लेकिन जब हम वैसा आचरण करते हैं, तो खुद को पाक–साफ़ बताने और साबित करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ते. बहरहाल, भाषा–व्याकरण संबंधी कुछ त्रुटियों के बावजूद यह पुस्तक सुधी पाठकों को एक नया संदेश, एक नया रास्ता देगी, ऐसा मुझे विश्वास है. ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

केवल 4.99 लाख में फोर्ड की लक्जरी कार

दिल्ली में इसकी क़ीमत 4.99 लाख से लेकर 7.59 लाख रुपये तक है

कार खरीदने वालों के लिए एक अच्छी ख़बर है. मशहूर कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने अपने लोकप्रिय सेगमेंट सेडान क्लासिक को अब सस्ते दामों में बाज़ार में लॉन्च किया है. दिल्ली में इसकी क़ीमत 4.99 लाख से लेकर 7.59 लाख रुपये तक है. फोर्ड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग) विनय पिपरसानिया ने बताया कि फोर्ड क्लासिक 1600 सीसी के ड्यूराटेक पेट्रोल और 1400 सीसी के टीडीसीआई ड्यूराटेक डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है. दोनों ही मॉडल्स 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन केसाथ मिलेंगे. इसके साथ इसमें की-लैस एंट्री, स्पीड सेंसिटिव लॉक्स, एयरबैग्स, फ्रंट फॉग लैम्स एवं रेयर डेफोगर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं. ■

सोनी के वॉयो सीरीज लैपटॉप कम टैबलेट

सोनी के ये लैपटॉप डेल और आसुस जैसी कंपनियों केहाईब्रिड टैबलेट को टक्कर देंगे.

सोनी ने वायो सीरीज के एफ-13एन, एफ-14एन, एफ-15एन लैपटॉप भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी क़ीमत लगभग एक लाख रुपये तक है, लेकिन ये लैपटॉप काफी स्टाइलिश हैं. इनकी ऊंची क़ीमत इसलिए है, क्योंकि ये कर्वटिबल फीचर्स वाले हैं. कुछ दिनों से बाज़ार में सस्ते गैजेट्स के साथ-साथ अच्छे लुक और फीचर्स के कारण महंगे गैजेट्स भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. टच स्क्रीन फीचर वाले ये लैपटॉप स्क्रीन मोड़कर टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इनकी सबसे खास बात है बेंडेबल स्क्रीन (पीछे की ओर मुड़ने वाली स्क्रीन). यह स्क्रीन मोड़ने के बाद की-बोर्ड पर फ्लिप हो जाएगी और इसे टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तीनों नए लैपटॉप 13, 14 एवं 15 इंच की स्क्रीन साइज के हैं. 13 इंच के वायो फ्लिप एफ-13एन के लिए 99,990 रुपये, 14 इंच के फ्लिप एफ-14एन के लिए 94,990 रुपये और 15 इंच के फ्लिप एफ-15एन के लिए 1,04,990 रुपये यूजर्स को खर्च करने होंगे.

सोनी के ये लैपटॉप डेल और आसुस जैसी कंपनियों के हाईब्रिड टैबलेट को टक्कर देंगे. वायो फ्लिप सीरीज के ये तीनों मॉडल एफ-13एन, एफ-14एन और एफ-15एन में इंटेल कोर आई-5 या आई-7 प्रोसेसर होंगे. इसी के साथ फ्लिप 15 में एनवीडिया का ग्राफिक्स प्रोसेसर भी होगा. यह तीनों फुल एचडी स्क्रीन के साथ हैं. फ्लिप एफ-13एन ब्लैक एवं सिल्वर और बाकी दोनों सिर्फ़ सिल्वर कलर में हैं. सोनी ने इन सभी लैपटॉप्स को अच्छे फीचर्स के साथ उतारा है. इनमें बैकलिट (रात में चमकने वाले) की-बोर्ड हैं, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है. सोनी के अनुसार, ये लैपटॉप किसी भी प्रोडक्टिव काम के लिए उपयुक्त हैं. इनकी वारंटी एक साल की है, लेकिन आप 999 रुपये देकर वारंटी 2 साल तक बढ़ा भी सकते हैं. इन लैपटॉप्स के साथ एमडीआर-एक्सबी910 हैडफोन भी मुफ्त दिया जाएगा, लेकिन यह लिमिटेड ऑफर है, जो तीन महीनों तक ही लागू रहेगा. ■

स्मार्ट फोन की मदद से एक्स-रे

स्मार्ट फोन के लिए कई तरह के ऐप्स बनाए गए हैं. किसी को मनोरंजन से जुड़े ऐप्स पसंद हैं, तो किसी को काम से जुड़े. गूगल प्ले पर कई ऐसे ऐप्स हैं, जिन्हें हम सिर्फ़ मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं. उन्हीं में से एक है द-रे स्कैन. इस ऐप की सहायता से आप किसी के भी हाथ, पैर, सिर, उंगलियों का एक्स-रे निकाल सकते हैं. गूगल प्ले पर मुफ्त में मौजूद यह ऐप हाल में अपडेट किया गया है. इसे डाउनलोड करने केलिए आपके फोन में एंड्रॉयड 2.2 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है. इसका साइज 255 केबी है. अपडेट हुए एक्स-रे स्कैन में एचडी क्वालिटी की फोटो दिखाई जाती है.

यह ऐप सिर्फ़ मनोरंजन के लिए बनाया गया है. न यह कैमरे का इस्तेमाल करता है और न कोई असली एक्स-रे दिखाता है. यह ऐसा ऐप है, जो खास तौर पर उनके लिए बनाया गया है, जो अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिक खेलना चाहते हैं. ग़ौरतलब है कि यह असली एक्स-रे नहीं निकालेगा, बल्कि सिर्फ़ शरीर के अलग-अलग अंगों के एक्स-रे की फोटो दिखाएगा. इस ऐप के डाटाबेस में हाथ की पांचों उंगलियों के अलावा 6 उंगलियों वाले हाथ का भी एक्स-रे है और इसी के साथ पैर का भी. अगर आप थोड़ी मस्ती के मूड में हैं, तो यह ऐप किसी भी पार्टी की जान बन सकता है. स्मार्ट फोन यूजर्स के लिए यह एक अच्छा ऐप साबित हो सकता है.■

लोकप्रिय म्यूजिक गैजेट्स

आजकल संगीत की ओर लोगों की रुचि बढ़ रही है. इसलिए म्यूजिक गैजेट्स में इनोवेशन एवं स्टाइल भी देखा जा सकता है. नई तकनीक के कारण इन गैजेट्स का बोलबाला है. 2000 से लेकर 20,000 रुपये तक के म्यूजिक गैजेट्स नए डिजाइन एवं आकर्षक फीचर्स के साथ बाज़ार में उपलब्ध हैं. म्यूजिक गैजेट्स के क्षेत्र में कई कंपनियां अपने हाथ आजमा रही हैं. जानिए, पांच खास म्यूजिक गैजेट्स के बारे में:-

राकेट डिवाइस में स्टूडियो

मॉन्स्टर गो-डीजे अल्ट्रा पोर्टेबल स्टैंड-अलोन डीजे कंसोल सिस्टम है. इस पॉकेट साइज डिवाइस में पूरा साउंड स्टूडियो है. मॉन्स्टर गो-डीजे सिस्टम मिक्सर और टर्नटेबल्स की ज़रूरत एक साथ पूरी करता है. इसमें ड्यूएल एलसीडी टच स्क्रीन और एनालॉग कंट्रोल पैनल है. इसमें एक ही टच से दो म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स को मिक्स किया जा सकता है. इसमें एसी एडॉप्टर के साथ यूएसबी पावर केबल है

यूएफओ इंस्पायर्ड डिजाइन

आईबॉल यूएफओ ने ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ पोर्टेबल स्पीकर लॉन्च किया है. फोन और टेबलेट से हैंड्स-फ्री बात करने के लिए माइक्रोफोन भी है. म्यूजिक सुनने के लिए ब्लूटूथ ऑडियो स्ट्रीमिंग के अलावा यूएसबी पेनड्राइव या माइक्रो एसडी कार्ड को भी कनेक्ट किया जा सकता है. इसमें रिचार्जेबल बैटरी है, जो चार घंटे तक वायरलेस ऑडियो देती है. इसमें एयूएक्स इनपुट है, जिसके जरिए मोबाइल फोन, टेबलेट, आईपॉड, एमपी-3 प्लेयर्स आदि से म्यूजिक का आनंद लिया जा सकता है.

पोर्टेबल स्टीरियो बूमबॉक्स

अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाले ब्लूटूथ स्पीकर्स भारत में भी लॉन्च हो चुके हैं. ये एचएमडीएक्स जैम पार्टी ब्लूटूथ से काम करने वाले पोर्टेबल स्टीरियो बूमबॉक्स हैं. ये एक ही चार्ज में 12 घंटे तक लगातार चल सकते हैं. अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो एलईडी लाइट इसका संकेत देती है. इन्हें पार्टियों में म्यूजिक का आनंद लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी 30 फीट तक है.

डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर

पोर्ट्रेनिक्स का सुपरबॉक्स हथेली के आकार का डिवाइस है, जो स्पीकर, एमपी-3 प्लेयर, ऑडियो रिकॉर्डर और पावर बैंक है. इसमें 8 जीबी का कार्ड लगा है, जिसे बढ़ाकर 32 जीबी तक कर सकते हैं. यूएसबी केबल के जरिए गानों को डाउनलोड किया जा सकता है और इसमें मौजूद स्पीकर से ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है. डिजिटल वाइस रिकॉर्डर में स्टीरियो माइक्रोफोन भी है. इससे मोबाइल एवं अन्य डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं.

टैबलेट के लिए स्पेशल स्पीकर

डेफिनिटिव टेक्नोलॉजी साउंड सिलेंडर कॉम्पैक्ट वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है. यह सिंगल भी उपयोग किया जा सकता है और इसे टैबलेट से जोड़ा जा सकता है. साउंड सिलेंडर में 2.1 एक्टिव साउंड एरे है. टैबलेट पर टीवी शो और मूवी देखे जा सकते हैं. इसकी साउंड क्वालिटी भी जबर्दस्त है. ■

एक सेकेंड में 44 एचडी मूवी

भारत में अभी ब्रॉडबैंड की एवरेज स्पीड 10.6 एमबीपीएस है यानी नया ब्रॉडबैंड इससे 18,350 गुना अधिक तेज है. यह टेक्नोलॉजी ब्रिटिश टेलिकॉम और फ्रांस की नेटवर्किंग कंपनी अल्काटेल ल्यूसेंट के वैज्ञानिकों ने विकसित की है.

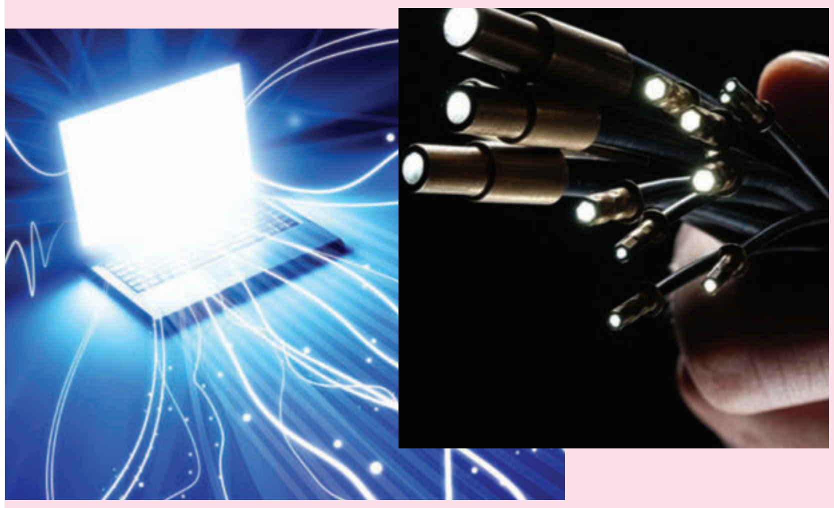

मूवी डाउनलोड करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर है. ब्रिटेन और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने ऐसी ब्रॉडबैंड सर्विस विकसित कर ली है, जिससे अब एक सेकेंड में 44 हाई डेफिनेशन (एचडी) फिल्में आप डाउनलोड कर सकते हैं. इस ब्रॉडबैंड की स्पीड 1.4 टेराबाइट्स प्रति सेकेंड है. भारत में अभी ब्रॉडबैंड की एवरेज स्पीड 10.6 एमबीपीएस है यानी नया ब्रॉडबैंड इससे 18,350 गुना अधिक तेज है. यह टेक्नोलॉजी ब्रिटिश टेलिकॉम और फ्रांस की नेटवर्किंग कंपनी अल्काटेल ल्यूसेंट के वैज्ञानिकों ने विकसित की है. ब्रिटिश टेलिकॉम ने एक फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर इसका टेस्ट 255 मील की दूरी पर पिछले अक्टूबर-नवंबर में किया. इस टेक्नोलॉजी के जरिए फाइबर केबल नेटवर्किंग से किए गए टेस्ट के बाद एक सेकेंड में 44 हाई डेफिनेशन (एचडी) क्वालिटी की फिल्में डाउनलोड करने का दावा किया गया है.■

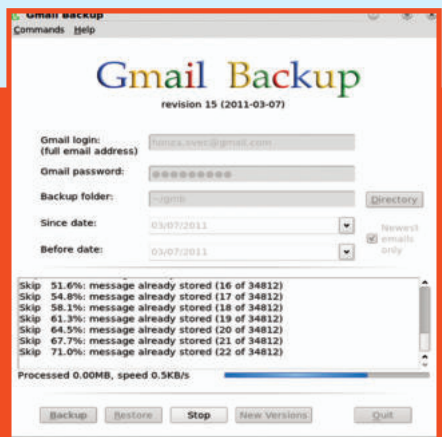

ज़रूरी मैसेज का बैकअप

आज के दौर में जीमेल का प्रयोग अधिकांश लोग करते हैं. आप जीमेल में अपने ई-मेल अकाउंट का बैकअप बड़ी आसानी से रख सकते हैं. कभी-कभी ज़रूरी मेल गलती से डिलीट हो जाने के कारण यूजर्स को बहुत परेशानी होती है. बैंक अकाउंट डीटेल्स से लेकर किसी यात्रा की ई-टिकट तक, यानी बहुत कुछ अपने ई-मेल अकाउंट में सेव रहता है. अगर आप अपने ई-मेल अकाउंट का बैकअप रखना चाहते हैं, तो यह सबसे आसान काम है. इसके लिए सेटिंग-फार्वर्डिंग और पीओपी/आईएमपी में जाकर फॉर्वड अ कॉपी ऑफ इन्कमिंग मेल टू (Forward a copy of incoming mail to) पर क्लिक करें और संबंधित ई-मेल आईडी डालें. आपके सभी मेल बैकअप उक्त ई-मेल आईडी में चले जाएंगे. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> देश हो या विदेश, गेंदबाज लगातार रन लुटाते रहे हैं और टीम की लुटिया डूबती रही है. घरेलू विकेटों पर बल्लेबाजों का बल्ला गेंदबाजों के घटिया प्रदर्शन पर पर्दा डाल देता है. विदेशी पिचों पर सभी की कलई खुल जाती है. तेज गेंदबाजों के लिए माकूल पिचों पर हमारे बल्लेबाज असहज और अप्रभावी हो जाते हैं. जिन पिचों पर विपक्षी गेंदबाज आग उगल रहे होते हैं, वहां हमारे गेंदबाज औसत दर्जे की गेंदबाजी करते हैं.

क्या ऐसे वर्ल्डकप जीतेगी टीम इंडिया!

नवीन चौहान

क्रिकेट विश्वकप के आयोजन में तक़रीबन एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय टीम विश्व विजेता का खिताब बचाने के लिहाज से कतई काम करती नहीं दिख रही है. विदेशी धरती पर भारत का शर्मनाक प्रदर्शन जारी है. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड, हर जगह भारतीय बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के आगे घुटने टेकते नज़र आए. बल्लेबाजों का ढेर होना समझ में आता है, लेकिन तेज और स्विंग गेंदबाजों के लिए माकूल पिचों पर तेज गेंदबाजों का असफल होना टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है. वर्तमान में टीम इंडिया जैसा प्रदर्शन कर रही है, उसके बूते क्या वह अपना खिताब बचा पाएगी? दुनिया भर में अपनी बल्लेबाजी के दम पर डंका बजाने वाले भारतीय बल्लेबाजों का बैंड बज रहा है. ढेरों रन लुटाते गेंदबाज असहाय और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बगलें झांकते नज़र आ रहे हैं. कामयाबी के शिखर बैठे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने जब न्यूजीलैंड में क़दम रखा, तो ऐसा लगा कि इस बार इतिहास बदलेगा. धोनी ने कहा कि वह विदेशी दौरों पर अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहते हैं, लेकिन एक पखवाड़ा गुजरा नहीं कि टीम की कलई खुल गई. भारतीय टीम एक बार फिर ढेर हो गई. विदेशी जमीं पर एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा है. लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों को खुद से ज़्यादा खुदा पर भरोसा हो गया है. विराट कोहली एवं मोहम्मद शमी को छोड़कर और किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है. कैप्टन कूल भी भारतीय टीम की नैया पार नहीं लगा पा रहे हैं. विदेशी पिचों पर बतौर कप्तान असफल रहने का दाग दौरा दर दौरा गहराता जा रहा है. भारतीय बल्लेबाजों की हालत पस्त है. शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे एवं सुरेश रैना का बल्ला लगातार विदेशी पिचों पर नाकाम हो रहा है.

शिखर धवन ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, लेकिन उसके बाद विदेशी धरती पर उनका बल्ला शांत ही रहा है. शिखर धवन ने अब तक भारत के लिए कुल 33 वनडे मैच खेले हैं. धवन ने 32 पारियों में 92.52 के धांसू स्ट्राइक रेट से कुल 1275 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका उच्च स्कोर 119 रन रहा है, जिसमें उनके 5 शतक और 5 अर्द्धशतक शामिल हैं. वैसे तो शिखर धवन एक आला दर्जे के बल्लेबाज हैं, उन्होंने कई धमाकेदार पारियां भी खेली हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उनका जैसा प्रदर्शन रहा है, उससे सवाल उठना लाजिमी है. दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान धोनी ने गंभीर का नाम लिया था कि वह अभी भी उनकी योजनाओं में हैं. यदि धवन का बल्ला लगातार शांत रहता है, तो चयनकर्ता गंभीर को एक आख़िरी मौक़ा दे सकते हैं. यदि गंभीर को मौक़ा मिलता है, तो वह हाथ आए इस मौक़े को कतई खाली नहीं जाने देंगे. रणजी ट्रॉफी में गंभीर के खराब प्रदर्शन की वजह से शिखर कुछ दिन और शिखर पर बने रह सकते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान के रूप में गंभीर के पास वापसी करने का एक सुनहरा मौक़ा है. उससे पहले शिखर को सचेत हो जाना चाहिए.

कप्तान धोनी के क़रीबी होने की वजह से सुरेश रैना लगातार टीम में बने हुए हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ियों को एक सीरीज में असफल रहने पर या नए खिलाड़ियों को मौक़ा दिए बिना ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. ऐसे खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है, जो घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर लगातार टीम इंडिया के दरवाजे खटखटाते रहे हैं, लेकिन रैना न तो टीम से बाहर गए, न ही उन्हें कोई चेतावनी दी गई. रैना ने अपना पिछला शतक जनवरी 2010 में ढाका में श्रीलंका के ख़िलाफ़ लगाया था. वहीं, रैना ने अपना पिछला अर्द्धशतक अगस्त 2013 में जिम्बॉब्वे के ख़िलाफ़ लगाया था. चेतेश्वर पुजारा देशी–विदेशी धरती पर अपनी तकनीक और बल्ले का लोहा मनवा चुके हैं. उन पर टेस्ट खिलाड़ी का टैग लगाकर लगातार एकदिवसीय टीम से बाहर रखा जा रहा है. तेज पिचों पर खेलने के लिए तकनीकी सुदृढ़ता चाहिए. बल्लेबाजी तकनीक के मामले में पुजारा कहीं से कमतर नहीं हैं. जिस तरह चयनकर्ताओं ने 2003 के विश्वकप से पहले हेमांग बदानी पर लक्ष्मण से ज़्यादा विश्वास जताया और उन्हें विश्वकप में खेलने का मौक़ा दिया था, भले ही टीम इंडिया तब फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही थी, लेकिन बदानी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. ठीक वैसी ही गलती इस बार पुजारा को नज़रअंदाज करके दोहराई जा रही है. चयनकर्ताओं को यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि अगला विश्वकप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है और भारतीय टीम को हमेशा यहां की पिचों पर मुंह की खानी पड़ी है. बावजूद इसके खिलाड़ियों को निजी संबंध और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर जगह मिल रही है, तो यह बेहद चिंताजनक है.

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया, तो लगा कि वह अपनी लय में आ गए हैं, उन्हें अपार प्रतिभा का धनी मानने वाले लोगों को लगा कि सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम को एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है, जो अकेले ही विपक्षी गेंदबाजों को लोहे के चने चबवा सकता है, लेकिन रोहित भी घरेलू विकेटों के रणबांकुरे बने रहे. लगभग सभी विदेशी दौरों पर उनका बल्ला खामोश ही रहा. अनियमित तौर पर यदा–कदा उनका बल्ला चला, लेकिन उन पर विश्वास जता पाना बेहद मुश्किल लगता है. उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहद सुस्त दिखाई पड़ती है. इसी वजह से वह विदेशी विकेटों पर तालमेल बैठा पाने में असफल रहे हैं. एक आल राउंडर की तरह टीम में जगह पाने वाले रविंद्र जड़ेजा का बल्ला बीच–बीच में थोड़ी–बहुत चमक दिखा जाता है, लेकिन उनकी ये पारियां भारतीय टीम को जीत के मुहाने पर नहीं पहुंचा पाती हैं. वह एक स्पिन गेंदबाज हैं, जो बल्लेबाजी कर सकता है, यही उनकी पहचान है. उनका बल्ला उनकी फिरकी के सामने खामोश ही दिखाई पड़ता है. गेंदबाजी के दम पर जड़ेजा आईसीसी रैंकिंग में पहले पायदान पर भी पहुंच गए थे, लेकिन बतौर बल्लेबाज वह पूरी तरह असफल रहे हैं. लंबे समय बाद रविंद्र जड़ेजा ने न्यूजीलैंड में लगातार दो अर्द्धशतक लगाए, लेकिन भारत की डूबती नैया को वह नहीं बचा पाए. भले ही वह विश्वकप की टीम में जगह पा लें, लेकिन विषम परिस्थितियों में वह बतौर बल्लेबाज असफल ही साबित हुए हैं.

कप्तान धोनी के क़रीबी होने की वजह से सुरेश रैना लगातार टीम में बने हुए हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ियों को एक सीरीज में असफल रहने पर या नए खिलाड़ियों को मौक़ा दिए बिना ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. ऐसे खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है, जो घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर लगातार टीम इंडिया के दरवाजे खटखटाते रहे हैं, लेकिन रैना न तो टीम से बाहर गए, न ही उन्हें कोई चेतावनी दी गई. रैना ने अपना पिछला शतक जनवरी 2010 में ढाका में श्रीलंका के ख़िलाफ़ लगाया था.

गेंदबाजों का तो बहुत बुरा हाल है. देश हो या विदेश, गेंदबाज लगातार रन लुटाते रहे हैं और टीम की लुटिया डूबती रही है. घरेलू विकेटों पर बल्लेबाजों का बल्ला गेंदबाजों के घटिया प्रदर्शन पर पर्दा डाल देता है. विदेशी पिचों पर सभी की कलई खुल जाती है. तेज गेंदबाजों के लिए माकूल पिचों पर हमारे बल्लेबाज असहज और अप्रभावी हो जाते हैं. जिन पिचों पर विपक्षी गेंदबाज आग उगल रहे होते हैं, वहां हमारे गेंदबाज औसत दर्जे की गेंदबाजी करते हैं. उनकी गेंदबाजी अनियंत्रित और दिशाहीन हो जाती है, जिसका फायदा विपक्षी टीम के बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से उठाते हैं और भारतीय टीम को मुंह की खानी पड़ती है. टीम में नए गेंदबाजों की जो खेप आई, जिसमें मोहम्मद शमी, उमेश यादव, वरुण ऐरोन, भुवनेश्वर कुमार, विनय कुमार एवं जयदेव उनदकर आदि शामिल हैं, में मोहम्मद शमी को छोड़कर कोई भी गेंदबाज स्थाई तौर पर टीम में जगह नहीं बना सका. इनमें से कोई एक सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो दूसरी में बदतर. युवा गेंदबाजों की मदद करने के लिए टीम में कोई अनुभवी गेंदबाज मौजूद नहीं है. जहीर बीसीसीआई के एकदिवसीय मैचों के प्लान में नहीं हैं. कप्तान धोनी जहीर खान को हालिया दक्षिण अफ्रीकी दौरे में एक बॉलिंग मेंटोर के रूप में ले गए थे. इससे ज़हीर खान की अहमियत का अंदाजा लग जाता है. गेंदबाज लगातार संघर्ष कर रहे हैं. 2015 में विश्वकप का खिताब बचाए रखने के लिए गेंदबाजी की समस्या का समाधान करना बेहद ज़रूरी है. गेंदबाजी भारतीय टीम की कमजोर कड़ी हमेशा से रही है. फिलहाल इसे मजबूती देने के लिए जहीर खान को टीम में बनाए रखना बेहद ज़रूरी हो गया है. यदि जहीर फिट हैं और टेस्ट मैचों में बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें बीसीसीआई किस आधार पर एकदिवसीय टीम में नहीं बनाए रखना चाहती है, यह समझ से परे है. ज़हीर खान की गैर मौजूदगी में टीम में सबसे सीनियर गेंदबाज ईशांत शर्मा हैं. ईशांत ने वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जो गेंदबाजी की थी, उसे देखकर लगा था कि भारतीय टीम को ज़हीर का उत्तराधिकारी मिल गया है, लेकिन ईशांत इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका, सभी विदेशी दौरों पर असफल रहे हैं. न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हालिया सीरीज में दो मैचों में ईशांत ने 59 के औसत से महज 2 विकेट लिए. ईशांत एकादश में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि वह टीम में ज़्यादा दिनों तक अपना स्थान सुरक्षित नहीं रख पाएंगे. उनकी इकॉनोमी और स्ट्राइक रेट सवालों के घेरे में है. फील्डिंग और बल्लेबाजी भी उनकी मदद करती नहीं दिख रही है. शायद उनके विकल्प के रूप में ही घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले ईश्वर पांडे को न्यूजीलैंड दौरे पर भेजा गया है, ताकि वह विश्वकप के लिहाज से तैयारी कर सकें और वहां की परिस्थितियों के बारे में समझ विकसित कर सकें.

पिछले एक साल में मोहम्मद शमी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. थोड़े से समय में वह टीम इंडिया की गेंदबाजी की धुरी बनकर उभरे हैं. अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय करियर में शमी ने 24 एकदिवसीय मैचों में लगभग 29 के औसत से 40 विकेट लिए हैं. जबकि उनका साथ दे रहे युवा भुवनेश्वर कुमार ने 30 मैचों में 33 विकेट लिए हैं. टीम में बतौर स्पिन गेंदबाज खेलने वाले अश्विन भी तेज पिचों पर बेअसर नज़र आ रहे हैं. बल्लेबाजी के दम पर वह ज़्यादा दिनों तक टीम में नहीं बने रह पाएंगे. बतौर गेंदबाज उनका प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड, दोनों में बेहद खराब रहा. दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ वह तीन एकदिवसीय मैचों में 169 रन खर्च करके केवल एक विकेट और न्यूजीलैंड सीरीज के पहले चार मैचों में 190 रन देकर केवल एक विकेट हासिल कर सके. अमित मिश्रा को जब–जब मौक़ा मिला है, उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की, लेकिन धोनी का क़रीबी होने का फायदा अश्विन को मिला और उन्हें अमित मिश्रा पर वरीयता मिली. तेज पिचों में किया गया प्रदर्शन उन्हें विश्वकप की टीम में जगह दिला पाने के लिए नाकाफी है. अब तक खेले गए 74 एकदिवसीय मैचों में अश्विन 33.86 के औसत से केवल 97 विकेट हासिल कर सके हैं. इन आंकड़ों को विश्वस्तरीय स्पिन गेंदबाजी के लिहाज से बेहतरीन नहीं कहा जा सकता. जबकि अमित मिश्रा ने अब तक खेले गए 21 मैचों में 23 के औसत से 37 विकेट हासिल किए. वह विदेशी धरती पर भी सफल रहे हैं.

महेंद्र सिंह धोनी एक करिश्माई कप्तान हैं. उनकी कप्तानी का हर कोई कायल है. उनका आईसीसी प्रतियोगिताएं जीतने का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है. इस वजह से उनसे पूरे देश को आशाएं हैं कि वह भारत को एक बार फिर से विश्व विजेता बनाएंगे. लेकिन, एक सेनापति तभी युद्ध जीत सकता है, जब उसके पास बेहतर युद्ध कौशल वाले सैनिक हों. यहां बतौर कप्तान धोनी को यह समझना होगा कि मेन इन यलो (चेन्नई सुपरकिंग्स) मेन इन ब्लू (टीम इंडिया) नहीं हो सकते हैं. उनकी जवाबदेही देश के प्रति है, न कि बीसीसीआई प्रमुख और चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन के प्रति. धोनी को देश के लिए निजी संबंधों को तिलांजलि देनी होगी और अपने तरकश में वे अचूक तीर लाने होंगे, जो उन्हें एक बार फिर विश्वकप दिला सकें. अभी तक तो भारतीय चयनकर्ता भी ट्रायल एंड इरर मैथड एप्लाई करते दिख रहे हैं. उनके पास गेंदबाजों को लेकर कोई योजना नहीं है. जो खिलाड़ी विश्वकप बीसीसीआई और धोनी की योजनाओं में हैं, उन्हें समय रहते मौक़ा दिया जाना चाहिए, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेल सकें और खुद को क्रिकेट के महाकुंभ के लिए तैयार कर सकें. यदि बीसीसीआई ने समय रहते आवश्यक क़दम नहीं उठाए, तो रेत के महल को ढहने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

Show your Advertisement For your Brand Presence

A D V E R T I S I N G S O L U T I O N S I N S I D E B . E . S . T . B U S E S

Please Contact :
Atul Bothra : +91 98921 30077 | +91 22 4922 0000
Email : sales@bestyms.com | sales@besttv.in
Website : www.bestyms.com | www.besttv.in

RingsaBell
Seatback Advertising Solutions

BEST TV
Bus Screen Advertising Solutions

हिंदी फिल्मों में आम आदमी की पॉवर पॉलिटिक्स

हिंदी फिल्मों का किरदार अब मेरा जूता है जापानी और पतलून इंग्लिस्तानी की इलीट छवि से बाहर निकल कर आम आदमी की ओर बढ़ रहा है, जहां वह अपने प्यार के लिए नहीं, समाज के लिए लड़ता है. राजनीतिक हक़ के लिए लड़ता है. भ्रष्ट व्यवस्था के ख़िलाफ़ लड़ता है. हालांकि पहले भी ऐसी फिल्में बनती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आंदोलनों के माध्यम से समाज में आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, तो फिल्मी जगत भी ऐसे विषयों को तरजीह देने लगा है.

प्रियंका प्रियम तिवारी

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी दुनिया के भ्रष्टाचारी देशों की सूची में भारत 94वें नंबर पर है. भारत में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है. राजनीतिक पार्टियां आएदिन एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाती और एक–दूसरे को बड़ा भ्रष्टाचारी होने का तमगा देती रहती हैं. अगर भ्रष्टाचार का सफाया हो जाए, तो देश दिन दूनी–रात चौगुनी तरक्की कर सकता है, लेकिन यह कम होने के बजाय दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. देश की तरक्की में बाधक इस समस्या को बॉलीवुड में भी खूब फिल्माया गया. जब–जब देश की राजनीति ने करवट ली, तब–तब उससे प्रेरणा लेकर सिल्वर स्क्रीन ने उसे अपना विषय बनाया. समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन पर प्रकाश झा ने फिल्म सत्याग्रह बना डाली, तो सन्नी भी कहां पीछे रहते, उन्होंने भी भ्रष्टाचार से त्रस्त आम आदमी पर आधारित फिल्म सिंह साहब दी ग्रेट बना डाली. यह आइडिया सोहेल खान को इतना भाया कि उन्होंने आम आदमी लहर से प्रभावित होकर सलमान खान को लेकर फिल्म जय हो बना डाली.

आम आदमी की कहानी बयां करती सलमान स्टारर इस फिल्म का डायलॉग–आम आदमी सोता हुआ शेर है, को काफी पसंद किया गया. आइए जानते हैं, क्या है फिल्म की कहानी. जय (सलमान खान) एक आम आदमी है, जिसने भ्रष्टाचार और अन्याय के ख़िलाफ युद्ध छेड़ रखा है. जय का एक ही मिशन है, लोगों की सहायता करना. वह इस सिद्धांत पर काम करता है कि लोगों की मदद करो और फिर उनसे कहो कि वे धन्यवाद बोलने की जगह दूसरों की सहायता करें. इस तरह से मददगार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी. इस मिशन में जय का सामना एक बड़े राजनेता (डैनी) और उसके परिवार से होता है. जय भूतपूर्व आर्मी ऑफिसर है और वह किसी भी चुनौती से नहीं घबराता. जय का विश्वास है कि देश की सेवा करने के लिए यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी बहन गीता (तब्बू) डरती है कि इस लड़ाई का परिणाम उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़

सकता है. गीता अपने भाई जय पर दबाव डालती है कि वह राजनेता से समझौता कर ले. जय परिवार की भलाई के लिए ऐसा कर भी लेता है, लेकिन इस कारण उसे काफी जलालत सहनी पड़ती है और वह अपना आपा खो बैठता है. इसके बाद वह राजनेता के ख़िलाफ आर–पार की लड़ाई छेड़ देता है. हालांकि जय नहीं जानता कि जिन लोगों की उसने अब तक मदद की है, वे उसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं, ताकि जय हो की गूंज दूर तक सुनाई दे.

फिल्में समाज का आईना होती हैं, फिल्मों में वही दिखाया जाता है, जो समाज में होता है. हर तरफ़ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जनता भी अब इस मुद्दे को लेकर काफी जागरूक हो गई है. ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में केवल हाल में ही राजनीति पर आधारित फिल्में बनने लगी हैं. इस विषय पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं. इस बार हम आपको बता रहे हैं, ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में...

सत्याग्रह

समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन पर प्रकाश झा ने फिल्म सत्याग्रह बनाई. इस फिल्म ने समीक्षकों की खूब वाहवाही लूटी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. हालांकि प्रकाश झा इसे अपनी अब तक की बेहतरीन फिल्म मानते हैं. यह फिल्म भारतीय लोकतंत्र और राजनीति की पृष्ठभूमि में ही रची गई है. झा कहते हैं, यह दिमागी राजनीति को दिखाती है. इसमें सत्ता को हासिल करने के दांव दिखाए गए हैं. कुल मिलाकर यह सत्ता पर अंदर और बाहर से पकड़ रखने वालों की कहानी है. प्रकाश झा ने इससे पहले भी राजनीति पर आधारित कई फिल्में बनाई हैं, जिन्हें काफी सराहा गया, जैसे गंगाजल, अपहरण, राजनीति एवं आरक्षण. फिल्म राजनीति की सफलता से प्रभावित होकर वह राजनीति–2 भी बना रहे हैं. झा खुद बिहार में राजनीति में दो बार किस्मत आजमा चुके हैं और दोनों ही बार उन्हें नाकामी हाथ लगी.

औरंगजेब

इस फिल्म को अतुल सबरवाल ने डायरेक्ट किया और आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस. फिल्म की कहानी गुड़गांव के रियल स्टेट माफियाओं एवं राजनेताओं की साठगांठ से ज़मीन की दलाली और एक पुलिस ऑफिसर के राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर आधारित है. यह कहानी बताती है कि सरकार ने किसानों से कौड़ियों के दाम ज़मीन खरीद कर किस तरह उसे करोड़ों–अरबों रुपये में भू–माफियाओं को बेच दी.

हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी

निर्देशक सुधीर मिश्रा ने भारतीय राजनीति को बहुत क़रीब से देखा और जाना है. उनके दादा डीपी मिश्रा इंदिरा गांधी के बेहद क़रीबी थे और उनके चाचा बृजेश मिश्रा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे. शायद यहीं से प्रेरणा मिली उन्हें राजनीति पर आधारित फिल्म बनाने की. उनकी फिल्म हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी वर्ष 2005 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहे तीन युवाओं पर आधारित थी. इस फिल्म में आपातकाल से पहले और उसके बाद का घटनाक्रम दिखाया गया था. देश के एक गंभीर मुद्दे नक्सलवाद को भी उन्होंने अपनी फिल्म में दर्शाया.

रंग दे बसंती

राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म रंग दे बसंती कॉलेज गोइंग युवाओं की कहानी है. कॉलेज में युवाओं की यह आम धारणा होती है कि देश के राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं. युवाओं में इस कदर गुस्सा है कि वे मानते हैं कि राजनेताओं को उड़ा दिया जाए. यह फिल्म इस विचार पर आधारित है कि क्रांति की ज़रूरत आज भी है. आज भी राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो इस सड़ चुके तंत्र को साफ़ करें.

आंधी

फिल्म आंधी को प्रोड्यूस किया था गुलजार ने. फिल्म के मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार एवं सुचित्रा सेन. फिल्म एक ऐसे कपल पर बनी थी, जो शादी के कुछ समय बाद ही अलग हो जाता है और पत्नी एक बड़ी राजनेता बन जाती है. कैंपेन के दौरान वह एक होटल में रुकती है, जहां उसकी मुलाकात उसके पति से होती है. तब माना गया कि यह फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है. वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह फिल्म राजनीतिज्ञ तारकेश्वरी सिन्हा के जीवन पर आधारित है. हकीकत जो भी हो, पर इंदिरा गांधी जब तक सत्ता में थीं, तब तक आंधी पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाई. जब 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार की विदाई हुई, तभी जाकर आंधी पूरी तरह से थियेटरों में रिलीज हो पाई.

गरम हवा

फिल्म गरम हवा इस्मत चुगतई की एक शॉर्ट स्टोरी पर बनी थी. यह हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है. विभाजन की त्रासदी पर आधारित यह फिल्म जूता व्यापारी सलीम मिर्ज़ा (बलराज साहनी) के इर्द–गिर्द घूमती है, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते. सलीम मिर्ज़ा के रिश्तेदार एक–एक करके पाकिस्तान जा रहे हैं. उनके भतीजे कासिम से उनकी बेटी अमीना निकाह करना चाहती है, पर कासिम भी अपने पिता के साथ पाकिस्तान चला जाता है, इस वायदे के साथ कि वह हिंदुस्तान आएगा और उससे निकाह करेगा. सलीम को उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा. सलीम का व्यवसाय प्रभावित होता है, इसकी वजह काफी हद तक उसका मुसलमान होना है. अपने वायदे के अनुसार कासिम निकाह करने भारत आता है, पर उसे राजनीतिक कारणों से निकाह के पहले ही गिरफ्तार कर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है. अमीना और कासिम की यह आख़िरी मुलाकात है. अब उसका निकाह शमशाद (जलाल आगा) से होने वाला है, पर व्यवसाय में हो रही मुश्किलों के कारण शमशाद भी पाकिस्तान चला जाता है. सलीम मिर्जा का बड़ा बेटा भी व्यवसाय में हो रहे घाटे को देखते हुए पाकिस्तान जाना चाहता है. सलीम मिर्जा अपनी बेटी, पत्नी (शौकत आज़मी) एवं छोटे बेटे सिकंदर (फारुख शेख) के साथ भारत में रह जाता है. अमीना अपनी शादी न हो पाने से फिर मायूस है. बंटवारे के बाद मुसलमानों को पाकिस्तान में अच्छे मौक़े मिल सकने की उम्मीद, भारत में उनके साथ हो रहा भेदभाव, घर से बेघर हो जाने और बेटी का गम जैसी परिस्थितियां सलीम मिर्ज़ा की हिम्मत तोड़ देती हैं. फिल्म में दो देशों के बीच मजहब की राजनीति को दिखाया जाता है, वहीं दोनों मजहबों में आपसी विश्वास को भी दिखाया जाता है. मुस्लिम तांगे वाला कहता है कि यहां के हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, वे चमड़े के धंधे को हाथ भी नहीं लगाएंगे.

मेरे अपने

यह फिल्म बेरोज़गारी की समस्या पर आधारित है. इसकी कहानी कुछ ऐसे बेरोज़गार युवकों के इर्द–गिर्द घूमती है, जिनका कोई विजन नहीं है. वे गली–मुहल्लों में हुड़दंगई करते हैं और बात–बात में मरने–मारने के लिए उतारू हो जाते हैं. विनोद मेहरा और शत्रुघ्न सिन्हा के नेतृत्व में युवकों की टोलियां आपस में लड़ती हैं और इस लड़ाई में मीना कुमारी, जिन्हें सभी प्यार से नानी कहते हैं, उनकी गोली की शिकार हो जाती हैं.

गुलाल

अनुराग कश्यप लिखित फिल्म गुलाल कई किरदारों के जरिए आगे बढ़ती है. छात्र राजनीति, राजपूतों द्वारा अलग राज्य की मांग, नाजायज औलाद का गुस्सा, प्रेम कहानी, युवा आक्रोश का गलत इस्तेमाल जैसे विषय लेकर बनी इस फिल्म में गालियों का जमकर इस्तेमाल किया गया. इस बारे में अनुराग का कहना था कि यथार्थ दिखाने के लिए ऐसा किया गया. आज के दौर पर कटाक्ष करते हुए इस फिल्म में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की ग़ज़ल सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है...पर एक पैरोडी भी है, जो कुछ इस तरह है...

ओ रे बिस्मिल, काश! आते आज तुम हिंदोस्तां
देखते कि मुल्क़ सारा यह टशन में, थ्रिल में है.
आज के जलसों में बिस्मिल, एक गूंगा गा रहा
और बहरों का वो रेला नाचता महफ़िल में है.

इसके अलावा श्याम बेनेगल की मंथन, आज का एमएलए, गांधी माई फादर, सरदार एवं किस्सा कुर्सी का आदि भी राजनीति पर बनी बेहतरीन फिल्में हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

10 फरवरी –16 फरवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार – झारखंड

अतिपिछड़ों के सहारे पार होगी नैया

शशि सागर

पिछले दिनों बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर की जयंती को सभी दलों ने प्रमुखता से मनाया. कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद, लोजपा सहित सभी दलों ने बड़ी ही शिद्दत से कर्पूरी को याद किया और अतिपिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की. इसी क्रम में भाजपा ने बड़ा आयोजन राजधानी के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में किया. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे. इससे पहले भी भाजपा कर्पूरी ठाकुर को बड़े फलक पर याद कर चुकी है. यह भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले भाजपा ने ही पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग भी की. यह अकारण नहीं है. बिहार की तमाम पार्टियों को इस बात का एहसास हो चला है कि आने वाले लोकसभा और विधान सभा के चुनाव में अतिपिछड़ी जातियों को साधकर ही पार उतरा जा सकता है.

बताते चलें कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के अतिपिछड़ी जाति के पहले मुख्यमंत्री बने. उन्होंने ही पहली बार पिछड़ी जातियों को वर्गीकृत करते हुए अतिपिछड़ी जाति की अवधारणा को राजनीतिक स्वीकृति दी थी. भानुमति का कुनबा सरीखा यह वह समूह था जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित था और इससे मुक्ति के लिए पूरी शक्ति के साथ पिछड़ों का साथ देता था. लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि इस समूह को जमीनी स्तर पर पहली लड़ाई दबंग पिछड़ों से ही लड़नी थी. कर्पूरी ठाकुर के मन में यह वेदना थी कि अतिपिछड़ों को सवर्ण और पिछड़ी जाति के सामंतों के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है. मुख्यमंत्री होते हुए भी वे खुद को लाचार पाते थे. कर्पूरी ठाकुर पर नरेंद्र पाठक द्वारा लिखी किताब कर्पूरी ठाकुर और समाजवाद में इस बात का जिक्र भी है. किताब में यह जिक्र है कि कर्पूरी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उदयभान त्रिपाठी से कहा था कि मूझे खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ता है जब गरीबों पर अत्याचार होता है और वह अत्याचार अगड़ी जातियों के सामंतों से पहले पिछड़ी जाति के सामंतों द्वारा होता है. उन्होंने कहा था कि मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब ये कमजोर जातियां संगठित होकर सामंतों से जुल्म के एक-एक पल का हिसाब मांगेंगी. बहरहाल अब यह मानिए कि ये अतिपिछड़ी जातियां कम से कम पॉलिटिकली चार्ज तो जरूर हो गई हैं. उन्हें स्वर तो मिला लेकिन अब ये स्वर्ग पर धावा बोलने की तैयारी में हैं. बिहार के इतिहास को देखें तो आजादी से पहले और बहुत बाद तक भी सवर्णों ही का राज रहा. भोला पासवान और कर्पूरी ठाकुर को छोड़ दें तो 1980 से 90 के बीच में बिहार में पांच मुख्यमंत्री हुए और पांचों सवर्ण. 62 से 90 तक का दौर संक्रमण काल का दौर भी कहा जाता है. 90 में सवर्णों के वर्चस्व की यह राजनीति टूटी और पिछड़ों का उभार हुआ. मंडल कमीशन की लहर और भूरा बाल साफ करो के नारे ने लालू को नायक बनाया. मंडल कमीशन की लहर को लालू ने सड़क पर उतरकर कैश किया. लालू दलितों और पिछड़ों के नायक बनकर उभरे और लंबे समय तक राज किया. धीरे-धीरे सवर्ण हाशिये पर चले गए. लालू ने इन वंचितों को स्वर तो दिया लेकिन उन्हें व्यवस्थित रूप नहीं दे पाए. धीरे-धीरे इस मुहिम का यादवीकरण होता चला गया. 97 में जब वे जेल जाने लगे तब भी उन्होंने रावड़ी को सीएम बना दिया और इस प्रकार पिछड़ों का एक नेता कमजोर होता गया. आगे चलकर लालू की ही बिछायी बिसात को नीतीश ने व्यवस्थित किया और कैश किया. नीतीश ने इसे स्वर देना शुरू किया. जान लें कि बिहार में अतिपिछड़ों की 118 जातियां हैं. बिहार के कुल वोट का लगभग चालीस प्रतिशत. आबादी के लिहाज से यह एक बड़ा ब्लॉक है जो नीतीश के शासनकाल में सबसे बड़ा वर्ग बनकर उभरा. 2005 के विधानसभा चुनाव पर नजर रखने वाले बताते हैं कि उस समय यह माना जाने लगा था कि सत्ता में वहीं आएगा जिसे अतिपिछड़ों का समर्थन मिलेगा. इसी समीकरण के तहत एनडीए वन और टू को अगड़ी जातियों और अतिपिछड़ी जातियों का समर्थन मिला और वे सत्ता में आए. जानकारों का मानना है कि बिहार में आने वाले दिनों में राजनीति अतिपिछड़ी जातियों के इर्दगिर्द ही घूमेगी और कर्पूरी इनके सबसे बड़े आइकॉन हैं यही वजह है कि कर्पूरी के बहाने सभी पार्टियां इस बड़े ब्लॉक को साधने की कोशिश में लगी हुई हैं लेकिन इसमें एक दिक्कत यह भी है कि 118 जातियों का यह भानुमति का कुनबा संगठित नहीं है. धानुक, मल्लाह, कहार, कुम्हार, माली, लोहार, सोनार, नोनिया, बेलदार जैसी कुछ प्रमुख जातियां हैं जो सबसे अधिक ताकतवर हैं. नीतीश इस समूह की शक्ति को बहुत पहले ही समझ चुके थे. यही वजह है कि वे 1995 के चुनाव से ही दलित और पिछड़े को अपने साथ करने की कोशिश में लग गए. यादवों के वर्चस्व को तोड़ने में कोइरी-कुर्मी नीतीश के साथ आगे बढ़कर आए और धीरे-धीरे दलित और अतिपिछडे भी नीतीश के साथ होते गए. इसका फायदा नीतीश को 2005 और 2010 के विधानसभा में जबरदस्त रूप से मिला. जहां लालू के मजबूत पक्ष के रूप में मुस्लिम और यादव हैं वहीं नीतीश के मजबूत आधार के रूप में अतिपिछड़े हैं. भाजपा के साथ रहते हुए सवर्ण भी उनके साथ थे. नीतीश इस बड़े ब्लॉक की महत्ता को समझते हैं यही वजह है कि उन्होंने इस बार कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा से टिकट दिया है लेकिन अतिपिछड़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, उनमें अब कसमसाहट दिख रही है. उन्हें अब अपनी बिरादरी से नेता चाहिए. वर्तमान का नेता भी और पौराणिक नेता भी. इस कसमसाहट को ऐसे भी समझा जा सकता है. बिहार में मल्लाहों की 23 जातियां हैं, 19 प्रतिशत उनका वोट है. चूंकि अब ये पॉलिटिकली चार्ज हो गई जातियां हैं तो उन्होंने अपना ऐतिहासिक नेता ढूंढ लिया. 1942 में शहीद हुए जुब्बा सहनी को, मुजफ्फरपुर में मल्लाहों के नायक जुब्बा सहनी के नाम का पार्क भी है. उधर भाजपा भी इस बड़े ब्लॉक को अपने पक्ष में करने की कोशिश लगातार कर रही है. कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग के अलावा और भी कई स्तरों पर भाजपा की तैयारी चल रही है. भाजपा के द्वारा गठित बूथ कमेटियों को ही देखें तो आप पाएंगे कि इन कमेटियों का हेड अधिकांश तौर पर उसने अतिपिछड़ी जाति से ही किसी को बनाया है. इसके अलावा बिहार में भाजपा लगातार यह बताने की कोशिश करती है कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ी जाति से आते हैं. साथ ही यह भी प्रचारित करती है कि अतिपिछड़ा के सहारे एक पिछड़ा (नीतीश) राज कर रहा है. थोड़े दिन पहले भाजपा अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा भी था कि नीतीश अतिपिछड़े के सहारे ही मुख्यमंत्री बने और आज जब कोई अतिपिछड़ा प्रधानमंत्री बनने की राह पर है तो नीतीश इसका विरोध कर रहे हैं.

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

कर्पूरी ठाकुर बिहार के अतिपिछड़ी जाति के पहले मुख्यमंत्री बने. उन्होंने ही पहली बार पिछड़ी जातियों को वर्गीकृत करते हुए अतिपिछड़ी जाति की अवधारणा को राजनीतिक स्वीकृति दी थी. भानुमति का कुनबा सरीखा यह वह समूह था जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित था और इससे मुक्ति के लिए पूरी शक्ति के साथ पिछड़ों का साथ देता था. लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि इस समूह को जमीनी स्तर पर पहली लड़ाई दबंग पिछड़ों से ही लड़नी थी. कर्पूरी ठाकुर के मन में यह वेदना थी कि अतिपिछड़ों को सवर्ण और पिछड़ी जाति के सामंतों के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है. मुख्यमंत्री होते हुए भी वे खुद को लाचार पाते थे. कर्पूरी ठाकुर पर नरेंद्र पाठक द्वारा लिखी किताब कर्पूरी ठाकुर और समाजवाद में इस बात का जिक्र भी है.

एक नज़र

कर्पूरी ही आदर्श - अमरेंद्र

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के इस कथन का कि कार्यकर्ता सभी चालिसों सीट पर लोकसभा चुनाव की तैयारी करें, स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ ही किसी के साथ समझौता होगा. साथ ही अमरेंद्र ने यह भी कहा कि बिहार सहित पूरे देश में आरक्षण का कर्पूरी फार्मूला ही लागू होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ही रालोसपा के आदर्श हैं. नीतीश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार सामाजिक न्याय के रास्ते से भटक गई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि संगठन का पंचायत और बूथ स्तर पर विस्तार करें. उन्होंने कहा कि रालोसपा बिहार में पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा और डॉ.अरुण कुमार के नेतृत्व में नया विकल्प देगी.

मुफ्त स्वास्थ्य कैंप लगा

लायंस कल्ब पाटलीपुत्र और महावीर कैंसर संस्थान ने राजधानी पटना के यारपुर स्थित अक्षत सेवा सदन में मुफ्त चिकित्सीय जांच और दवाओं के वितरण के लिए कैंप लगाया. इस कैंप का उद्घाटन अभिनेता व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने किया. अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि अक्षत सेवा सदन के डॉक्टर और स्टाफ पिछले दस साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं. ऑर्थोपेडिक की समस्याओं के निदान के लिए यह बिहार का प्रमुख केंद्र बन गया है. कार्यक्रम में बिहार झारखंड के एनसीसी के उप महानिदेशक रतन कुमार ने भी शिरकत की. उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है. यह हमें एक-दूसरे के करीब लाता है और एनसीसी हमेशा इन कार्यों में आगे रही है. वहीं महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. जेके सिंह ने कहा कि हमारा संस्थान समाज के स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखता रहा है. साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक बनाने के लिए संस्थान के द्वारा समय समय पर कैंप लगाए जाते रहे हैं. पीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. हरिराम सिंह ने अतीथियों का स्वागत किया. कैंप के दौरान डॉ. सरसीज नयानम, डॉ. अमीता सिंह, डॉ. मनीषा, डॉ. अमलेश, डॉ. जे. चौधरी, डॉ. संजय, डॉ. नीता, डॉ. अनुपमा, डॉ. रवीश, डॉ. अजीत, डॉ. आनंद, डॉ. शिवम, डॉ. शितांशु आदि ने आठ सौ से अधिक मरीजों की जांच की और साठ से अधिक फार्मा कंपनियों की सहायता से इन मरीजों को मुफ्त में दवाएं दी गईं. इस मौके पर अक्षत सेवा सदन के निदेशक डॉ. अमूल्य ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाज की सेवा करना है. साथ ही उन्होंने यह जानकारी दी कि अगले माह से उनका हॉस्पीटल अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही 75 बेड का हो जाएगा. *– अमृता कुमारी*

क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फॉरबिसगंज में टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच ट्रैक्टर मैकेनिक/मशीनिस्ट-प्रथम वर्ष बनाम वायरमैन प्रथम वर्ष के बीच खेला गया. इसमें ट्रैक्टर मैकेनिक की टीम विजेता रही. मैन ऑफ द मैच विकास कुमार मंडल रहे जबकि मैन ऑफ द सिरीज का खिताब तबरेज आलम ने अपने नाम किया. इसी प्रकार बेस्ट बैट्समैन ऑफ सिरीज एवं बेस्ट बॉलर ऑफ सिरीज क्रमश: रौशन कुमार एवं विकास कुमार रहे. विजेता टीम के कप्तान रवि कुमार एवं उपविजेता टीम के कप्तान विकास कुमार को संस्थान के चेयरमैन अरविंद गोयल, प्राचार्य सुजाइद्दीन एवं क्रीड़ा अध्यक्ष रामप्रवेश दास के द्वारा संयुक्त रूप से ट्राफी प्रदान की गयी. टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने व्यवसायवार भाग लिया. संस्थान के चेयरमैन श्री गोयल ने इस अवसर पर अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि खेल से आपसी भाईचारा बढ़ता है और यह भावना हमेशा छात्रों में बनी रहनी चाहिए. इसके लिए हर संभव सहयोग देने का उन्होंने भरोसा भी उन्होंने दिलाया. ■ *– अजातशत्रु अग्रवाल*

फ़र्ज़ी शिक्षकों की नौकरी गई

तरुण कुमार

नियोजित शिक्षकों को लेकर पूरे सूबे में कई तरह के मामले हैं. जगह-जगह ये शिक्षक वेतनमान के लिए विरोध करते नजर आते हैं तो कहीं उनकी गुणवत्ता पर ही सवाल किए जाते हैं लेकिन एक मामला समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड का है. यहां के 61 नियोजित शिक्षकों की नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि इन लोगों ने प्रमाण पत्र व मेधा सूची में गड़बड़ी करके नौकरी हासिल की थी. इस संबंध में जिलाधिकारी नवीन चंद्र झा को शिकायत मिली थी. इसी के आधार पर जांच की गई और मामले को सही पाया गया. बीडीओ ने उक्त सभी शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने का निर्देश जारी कर दिया है. इन सभी शिक्षकों ने 2012 में आवेदन दिया था. डीएम नवीन चंद्र झा के जनता दरबार में इन शिक्षकों के खिलाफ शिकायत आई थी. आपत्ति के आलोक में प्रखंड नियोजन समिति ने सभी नियोजित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, मेधा सूची, मूल प्रमाण पत्र एवं नियोजन प्रक्रिया की जांच की. इसके बाद प्रथम चरण के वर्ग एक से पांच तक के चार, द्वितीय चरण के वर्ग एक से पांच तक के आठ, वर्ग छह से आठ तक के दो व तृतीय चरण के तहत वर्ग एक से पांच तक के 34, वर्ग छह से आठ तक के 13 शिक्षकों का नियोजन रद्द किया गया. विभूतिपुर बीडीओ सुरेन्द्र नाथ राय ने बताया कि 61 नियोजित शिक्षकों का नियोजन रद्द करते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को डाक के माध्यम से पत्र भेज त्वरित कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है.

इन शिक्षकों की गई नौकरी

बीडीओ ने रद्द किए गए नियोजित शिक्षकों की सूची जारी कर दी है. इनमें मोहन कुमार राय, प्रमोद कुमार, सत्य नारायण सिंह, विजय कुमार, सुमित कुमार, हरिओम कुमार, रौशन कुमार, सुरेश कुमार, देवेश कुमार प्रभाकर, राजीव कुमार, प्रवीण कुमार महतो, आलोक कुमार, अनिल कुमार, धर्मप्रकाश यादव, जय नारायण महतो, शशि कुमार सुमन, मणिभूषण मिश्र, निरंजन कुमार चौधरी, राम जलिस कुमार, महेश्वर प्रसाद सिंह, चंदेश्वर यादव का नियोजन रद्द कर दिया गया है. ये सभी तृतीय चरण में यूआर कोटि में नियोजित हुए थे. मेधा अंक के विरुद्ध उनका नियोजन किया गया था. वहीं तृतीय चरण में दिनेश प्रसाद सिंह, मुकेश कुमार सिंह, देवेन्द्र कुमार महतो, कमलाकांत राय, विकास कुमार का भी नियोजन रद्द किया गया है. तृतीय चरण के ओबीसी कोटे के तेज नारायण कुमार, प्रमोद ठाकुर, सुरेश कुमार ठाकुर, चंदन कुमार शर्मा, नरेन्द्र पंडित, धीरेन्द्र रजक, नमूना चौधरी, प्रभात कुमार ठाकुर, राजेश कुमार, शुभम कुमार, विजय कुमार विनय, लक्ष्मण कुमार, त्रिभुवन कुमार, राम कुमार सिंह, राजीव कुमार राय, सहदेव शर्मा, अनुरोध कुमार, फूल कुमार पंडित, दुखन साह, मोति कुमारी, पूजा कुमारी, कमल कुमार, राम गुलाम शर्मा, मो. समस आलम, रवि प्रकाश, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सीमा सिंह, भावना कुमारी, सुमित कुमार, वीरेन्द्र कुमार, गणेश कुमार, प्रियंका कुमारी, दीपक कुमार राय, राम विवेक कुमार व हरिशंकर सदा का नाम शामिल है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नेताओं की वजह से उपेक्षित हैं बेगूसराय

सुरेश चौहान/रघुवीर झा

लोकसभा चुनाव नजदीक है. तैयारियां जोरों पर है. ऐसे में बेगूसराय की जनता के बीच बतकही हो रही है कि क्या इस बार भी हम ठगे जाएंगे? लोगों के बीच हो रहे गपशप का लब्बोलुआब यही होता है कि अबतक यहां से कई कद्दावर जीतकर संसद गए, जिसमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनका बेगूसराय से कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है. और यही वजह है कि बेगूसराय लगातार उपेक्षा का दंश झेल रहा है. यही वजह है कि इस बार बेगूसराय की जनता का मिजाज बदला-बदला दिख रहा है. अबतक तो यही देखा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान ये नेता बड़े-बड़े वादे तो करते हैं लेकिन जीतने के साथ ही बेगूसराय को भूल जाते हैं. जानकार एक कारण यह भी बताते हैं कि अबतक जीतते रहे नेता बेगूसराय की जरूरतों, यहां की समृद्ध संपदा को महसूस ही नहीं कर पाते हैं, वे ओछी राजनीति में उलझकर रह जाते हैं.

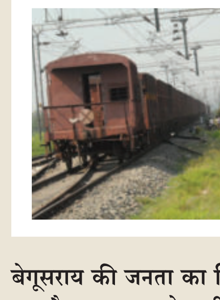

बताते चलें कि कार्यानन्द शर्मा, श्यामनन्दन मिश्र, चन्द्रभानु देवी, सूर्य नारायण सिंह, राजो सिंह, रमेन्द्र कुमार, ललिज विजय सिंह, राजवंशी महतो, रामजीवन सिंह, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह, डॉ. मोनाजिर हसन जैसे कद्दावर नेताओं ने बेगूसराय एवं बलिया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो किया लेकिन जिले के विकास में एक भी ईंट नहीं जोड़ पाए. इन नेताओं के कार्यकाल में बेगूसराय जिला सर्वथा उपेक्षित ही नहीं रहा बल्कि वैभवशाली अतीत का लगातार क्षरण होते चला गया. यह कहा जाता है कि आज बेगूसराय-बरौनी विश्व के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित है तो इसमें बेगूसराय एवं बलिया के सांसदों का तनिक भी योगदान नहीं है. जो कुछ भी है वह पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की देन है. बेगूसराय कभी बौद्धधर्म का केन्द्र हुआ करता था, पालवंश के शासन एवं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य का समृद्ध मुख्यालय हुआ करता था. एशिया प्रसिद्ध ताजा जलश्रोत का काबर झील, पक्षी विशेषज्ञ डॉ. सलीम के सपनों का अन्तर्राष्ट्रीय पक्षी विहार, ऐतिहासिक तांत्रिक स्थल जयमंगलागढ़ जिले के वैभवशाली विरासत में शुमार था. पौराणिक महत्व का सिमरिया एवं चमथा का कल्पावास मास मेला, हरिगिरि धाम, नैयपुर एवं नूरपुर की ऐतिहासिक मस्जिद, बरौनी तेलशोधक कारखाना, बरौनी खाद कारखाना, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी डेयरी, गढ़हारा रेलवे यार्ड आदि बेगूसराय की समृद्धि में चार चांद लगाते थे. लेकिन सांसदों में दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव एवं विकास के प्रति उदासीन रवैये के कारण बरौनी खाद कारखाना बन्द हो गया, बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता का अपेक्षित विस्तार नहीं हो पाया एवं इसपर आधारित पेट्रो-रसायन कारखाना नहीं लग पाया, गढ़हारा यार्ड की 2200 एकड़ परती जमीन अपराधियों का सुरक्षित अभ्यारण्य बन गया, सिमरिया एवं चमथा घाट का निर्माण नहीं हो पाया, काबर झील पक्षी विहार नहीं बन पाया, जयमंगलागढ़ एवं हरसाई स्तूप का विकास कर इसे बौद्ध सर्किट से जोड़कर पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सका, देवना औद्योगिक केन्द्र वीरान हो गया, औद्योगिक विकास केन्द्र में एक भी उद्योग नहीं स्थापित हो पाया, बरौनी डेयरी में पशुपालकों का शोषण जारी है. इस सबके पीछे एकमात्र कारण है सांसदों में कार्य संस्कृति का अभाव. इसके पीछे एक वजह यह भी है कि अधिकांश सांसद बेगूसराय पर थोप दिए जाते हैं. जिन्हें बेगूसराय के विकास से कुछ लेना देना नहीं है. वर्तमान सांसद का कार्यकाल सिर्फ बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर द्रुतगामी ट्रेनों के ठहराव की मांग में ही बीत गया और वह भी नहीं हो पाया. एक ओर सांसदों की पहल पर हाजीपुर, मधेपुरा एवं सीवान आदि स्थानों पर जमीन खरीदकर रेलवे का बड़ा कारखाना आदि स्थापित हो रहा है जबकि गरहारा में रेलवे की 2200 एकड़ जमीन खाली पड़ी है जहां कारखाना लगाने से भारत सरकार को अरबों रुपये की बचत होती और जिले के हजारों परिवार को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजी-रोटी मिलती.

बेगूसराय जिला स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए नगर निगम के मेयर संजय कुमार ने मंचासीन जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से मांग की थी कि आप सब बेगूसराय का विकास नहीं कर सकते तो जिलेवासियों को अतीत का समृद्धशाली, गौरवशाली, वैभवशाली एवं खुशहाल विरासत लौटा दीजिये. जिलाधिकारी मनोज कुमार ने भी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि इतने संसाधनो से संपन्न बेगूसराय पिछड़ा कैसे है? यदि गरहारा यार्ड की जमीन पर रेलवे का कोई बड़ा कारखाना, पेट्रोकेमिलकल कारखाना, बरौनी औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के साथ बरौनी खाद कारखाना को पुन: चालू किया जाय, काबर झील को पक्षी विहार घोषित किया जाय, जयमंगलागढ़, हरसाई स्तूप, नमक सत्याग्रह स्थल एवं सिमरिया तथा चमथा घाट का विकास पर्यटक स्थल के रूप में कर दिया जाय तो बेगूसराय देश के समृद्ध एवं खुशहाल जिलों में से एक होगा और यहां के युवाओं का न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि यह दूसरे प्रदेश के युवाओं को रोजी-रोटी प्रदान करने वालों की स्थिति में आ जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

संकल्प रैली की निकली हवा

सुनील सौरभ

महीनों से बहुप्रचारित बिहार के सत्ताधारी दल जदयू की मगध प्रमण्डल स्तर की संकल्प रैली जदयू नेताओं के आशा के विपरीत रही. रही-सही कसर मौसम ने पूरी कर दी. जदयू के नेता रैली से पूर्व बड़े-बड़े दावे कर रहे थे. रैली के बाद वही नेता कुछ नरम होकर भीड़ के दावे करते हुए मौसम को कोसते नजर आए. लेकि खराब मौसम के बाद भी गया गांधी मैदान में जुटी भीड़ पर तो कोई असर नहीं पड़ा था. नीतीश कुमार की संकल्प रैली में आई भीड़ का अंदाजा भी सभी कोई अपने-अपने तरीके से कर रहा है. सच यही है कि इस रैली में दस हजार के नीचे ही लोगों की भीड़ रही.

गया जिले समेत मगध प्रमण्डल के तमाम जदयू नेताओं के प्रयास के बावजूद नीतीश कुमार की संकल्प रैली में भीड़ नहीं जुटने का अर्थ लगा लिया जाना चाहिए. ऐसे गया शहर समेत जिले के तमाम प्रमुख कस्बाई शहरों को बैनर, पोस्टर, होर्डिंग से जदयू के नेताओं ने पाट दिया था. हर नेता ने अपनी-अपनी तस्वीर का बड़ा-बड़ा होर्डिंग लगा रखा था. रैली में स्थानीय नेताओं से लेकर नीतीश कुमार तक के भाषण में भाजपा से अलग होने की सफाई तथा आत्मप्रशंसा ही प्रमुख रहे. शेष वही बातें जंगलराज, साइकिल बांटने की कथा दोहराई गई. अंत में सांप्रदायिकता के विरोध में एकजुट होकर जदयू को मजबूत करने का आह्वान किया गया.

संकल्प रैली में औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह के नहीं आने पर भी कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक में कानाफूसी होती रही. रफीगंज के जदयू विधायक अशोक सिंह ने बिना नाम लिए ही सुशील सिंह की चर्चा करते हुए कहा कि जिसे नीतीश कुमार ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया अब वे दूसरे दल की ओर ताक-झांक कर रहे हैं. अन्य मंत्री-विधायक भी भाजपा को कोसने और नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाते रहे. नीतीश कुमार ने ले-देकर विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले को ही लोक सभा चुनाव में मुद्दा बनाने की बात कही. बिजली को लेकर तो पुन: ये कहा कि 2015 तक बिजली नहीं सुधरी तो वोट नहीं मांगने आऊंगा. सर्वाधिक लोकप्रिय और सुशासन की बात करने वाले बिहार के मुखिया को आम जन से दूरी बनाए रखने के लिए रैली में सुरक्षा की जबरदस्त घेराबन्दी की गई थी. हर किसी को कड़ी जांच के बाद ही मैदान में घुसने दिया गया. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का अन्दाजा इसी से लगा सकते हैं कि मंच से ठीक सामने करीब 100 फिट का डी एरिया बनाया गया था, जिसे खाली रखा गया था ताकि कोई भी व्यक्ति मंच तक न फटक सके. काला छाता, काला मफ्लर, गमछी पर भी पुलिस की कड़ी नजर थी. संकल्प रैली के लिए दिन-रात एक करने वाले नेताओं को बहुत तवज्जो नहीं दी जाने की चर्चा भी रैली के बाद होती रही. इस रैली के लिए सबसे अधिक समय और तन-मन-धन लगाने वाले गया महानगर जदयू अध्यक्ष राजू वर्णवाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के पूर्व ही स्वागत भाषण करा दिया गया. जबकि स्वागत भाषण नीतीश कुमार के मंच पर आने के बाद करना था. इस मामले पर जदयू के प्रदेश संगठन प्रभारी अशोक कुमार सिन्हा तथा राजू वर्णवाल से कुछ नोक-झोंक भी हुई. इस रैली में जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा ने ये साबित करने का प्रयास किया कि सबकुछ उनके प्रयास से ही हुआ है. जबकि सच्चाई यह है कि गया महानगर जदयू अध्यक्ष राजू वर्णवाल ने सभी छोटे-बड़े नेताओं को जोड़कर संकल्प रैली के लिए तन-मन-धन लगाया.

जदयू के इस संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मगध प्रमण्डल में अपनी तथा अपनी पार्टी जदयू की शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास बेकार गया क्योंकि प्रदेश के विकास के लिए भविष्य की कोई ठोस योजना, नए कल-कारखाने लगाने, रोजगार बढ़ाने, मगध प्रमण्डल के विकास किसी भी तरह की मुकम्मल योजना, नक्सली समस्या, सिंचाई योजनाओं आदि के लिए किसी तरह की बातें, नीतीश कुमार ने नहीं की. सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए संघर्ष करने की बात कह कर चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा. संकल्प रैली से आम जन को राज्य के मुखिया से कुछ नहीं मिल पाया. सिवाय इसके कि जदयू कार्यकर्ताओं को महीने दो महीने तक कार्यक्रम के बहाने व्यस्त रखा गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

बालिकाएं सम्मानित

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विकास भारती बिशुनपुर में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डा. एल.एन. भगत ने कहा कि शिक्षा आज के दौर में बुनियादी जरूरत बन गई है. शिक्षा हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. डॉ. भगत विकास भारती द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे. मानव शास्त्र विभाग के शिक्षक डॉ. करमा उरांव ने कहा कि आदिम जनजाति समाज के अभिन्न अंग हैं. आजादी के बाद भी उनकी आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति नहीं सुधरी है. समारोह में विनय कुमार ने आदिवासी जनजाति समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया. मंच का संचालन सुजीत गोस्वामी ने किया. विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने कहा कि आदिम जनजाति शिक्षित होकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. शोधार्थियों को उनके विकास के बारे में लोगों को बताना चाहिए. आदिवासी कल्याण आयुक्त राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार अकेले दम पर विकास नहीं कर सकती है. इसके लिए सभी को साथ मिल कर चलना होगा. बताते चलें कि विकास भारती ने झारखंड की सात आदिम जनजातीय बालिकाओं को सम्मानित किया. *– मंगलानंद*

ट्रेन चलाने की मांग

इंडो-नेपाल ऑरगेनाईजेशन ऑफ रेल यूजर्स के सदस्य विनोद सरावगी ने केन्द्रीय रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जोगबनी से बनारस के बीच त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन बरौनी-मुजफ्फरपुर-छपरा-बलिया के रास्ते चलाने की मांग की है. अपने पत्र में इन्होंने दर्शाया है कि बनारस एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं शैक्षणिक स्थल है तथा भारतीय मूल के लोगों का नेपाली मूल के लोगों के साथ बेटी-रोटी का संबंध है इसलिए इस ट्रेन की उपयोगिता काफी मायने रखती है. उन्होंने बताया है कि जब दशकों पूर्व इस क्षेत्र में मीटर गेज की रेल लाईन थी तो भी उस वक्त जोगबनी से धार्मिक स्थल इलाहाबाद के लिए प्रयाग एक्सप्रेस के रूप में सीधी ट्रेन चला करती थी. उन्होंने बनारस तक चलनेवाली इस ट्रेन का नाम पशुपतिनाथ-विश्वनाथ एक्सप्रेस रखने की मांग करते हुए अनुरोध किया है कि आगामी 12 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले रेल बजट में इसकी घोषणा कर इस सीमावर्ती क्षेत्र के लाखों लोगों की जनभावना का आदर किया जाए. *– अजातशत्रु अग्रवाल*

शिक्षित बनें लड़कियां

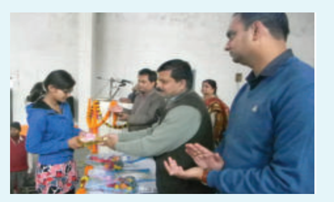

जबतक बालिकाएं शिक्षित नहीं होंगी समाज व राष्ट्र की खुशहाली संभव नहीं है. इसके लिए एक बेहतर कार्ययोजना बनाकर काम करने की जरूरत है. उक्त बातें जिलाधिकारी श्रीधर सी ने स्थानीय एमजेके महिला इन्टर कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही. समारोह महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी. छात्राओं के बीच वाद-विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और सफल प्रतिभागियों को जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया गया. उक्त कार्यक्रम में छात्राओं ने जिलाधिकारी श्रीधर सी के समक्ष अठारह वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं करने की शपथ ली. मौके पर पहुंची पूर्व प्राचार्या सह विद्यालय उप निरीक्षिका शशिकला, वरीय उपसमाहर्ता, विद्यालय प्राचार्या देवयानी, शिक्षक जीतेन्द्र पाण्डेय, विनय पाण्डेय, राम कुमार बैठा, महिला हेल्प लाइन के परियोजना प्रबंधक सुश्री अमृता कुमारी, श्रीमति संगीता चित्रांश, महिला विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक अरविन्द कुमार, डा. विजय शर्मा आदि उपस्थित थे. *– इंतेजारुल हक*

कोसी क्षेत्र हो अलग

आजादी के बाद से खगड़िया सहित पूरे कोसी क्षेत्र की जनता ने हर चुनाव में सरकार को एकमुश्त वोट देकर सत्ता दिलाने का काम किया लेकिन सत्ता में आने के बाद कोसी क्षेत्र के लोगों को आज तक सिर्फ ठगने के सिवा कोई काम नही किया गया. उक्त बातें परिसदन में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि शिक्षा को शराब का गिरवी बना दिया गया. इलाके के लोग कभी बाढ़ तो कभी सूखे का दंश झेलने को भी मजबूर हैं. साथ ही यह भी कहा कि आज बिहार में जितनी नदियां है, वह अभिशाप बन चुकी हैं. लेकिन नदियों के पानी का समुचित प्रबंधन हो तो बिहार के हर घर में मुफ्त बिजली एवं हर खेत में मुफ्त पानी पहुंचाया जा सकता है. श्री यादव ने कोसी क्षेत्र को अलग स्टेट बनाने को लेकर कहा कि कर्पूरी जी की पुण्यतिथि पर सभी जिला मुख्यालय में उपवास कार्यक्रम से शुरुआत करते हुए प्रदर्शन, जेल भरो अभियान, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं मानी तो करो या मरो की नारा के साथ जन आंदोलन जारी रखेगें. इस अवसर पर युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेन्द्र सिह त्यागी, नगर सभापति मनोहर कुमार यादव, जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार, चन्द्रशेखर कुमार ,दीपक चन्द्रवंशी, चंदन सिह, रणवीर कुमार, मनोज कुमार, शिवराज यादव, सुनील चौरसिया सहित दर्जनों युवा शक्ति के कार्यकर्ता उपस्थित थे. *– नन्द किशोर शर्मा*

सेमिनार आयोजित

राजनीति में बाहुबल व धनबल एक बड़ी समस्या है और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा भी. जब तक चुनाव में बाहुबल व धनबल का प्रयोग होता रहेगा तब तक समाज व राष्ट्र की तरक्की संभव नहीं है. मोतिहारी के गांधी संग्रहालय के सभागार में बशीरूल होदा इस्लाहुल मुसलेमिन वेलफेयर सोसाइटी एवं नेशनल इलेक्शन वाच द्वारा आयोजित 'राजनीति में बाहुबल और धनबल समस्या एवं समाधान' विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए बुद्धिजीवियों ने उक्त बातें कही. गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राजनीति में हो रहे अपराधीकरण, जातिवाद व राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही मनमानी का मामला विस्तार से रखा और एक बेहतर कार्य योजना बनाकर काम करने पर बल दिया. राइट टू रिकॉल पर भी गहन चर्चा हुई और कहा गया कि जनता जैसे वोट देकर चुनाव जिताने का अधिकार रखती है उसी तरह से जनता को मनमानी करने वाले जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए. मौके पर राजीव कुमार, प्रो. शोभाकान्त चौधरी, अशोक वर्मा, प्रसाद रत्नेश्वर, उमाशंकर प्रसाद, संदीप कुमार कौशल, विनय कुमार, प्रभु राम, अमर आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए. ■

अतिपिछड़ों के सहारे पार होगी नैया

पृष्ठ 17 का शेष

खैर अब यह बात इस समुदाय में भी होने लगी है कि नीतीश अतिपिछड़े के स्वाभाविक नेता नहीं हैं. और यह बात अब उठने लगी है कि आखिर नीतीश पिछड़ा होकर कबतक अतिपिछड़ों के नेता बने रहेंगे. नीतीश शुरूआत से ही इस वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने अतिपिछड़ों के लिए विधायिका में आरक्षण की मांग की ही थी. पंचायतों में अतिपिछड़ों को आरक्षण देकर इसके सशक्तिकरण का भी काम किया ही था. लेकिन अब यह वाजिब मांग है कि उच्च स्तर पर भी इनके सशक्तिकरण के लिए आवाज दें. अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करेंगे तो यह देखेंगे कि सवर्ण और अतिपिछड़ों को ही सबसे अधिक फायदा हुआ है. सवर्णों को जहां 56 की जगह 76 सीट हाथ लगीं वहीं अतिपिछड़ी जाति के सात की जगह 17 विधायक जीत कर आए. इसके बाद यह माना जाने लगा कि यही दोनों ग्रुप नीतीश के कोर समूह का निर्माण करते हैं लेकिन नीतीश के साथ परेशानी यह है कि इनके दोनों कोर ग्रुप सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बेमेल हैं, इनके बीच कोई मजबूत राजनीतिक सूत्र नहीं है और न ही नीतीश दोनों के स्वभाविक नेता हैं. और यह असहज स्थिति उनके साथ बनी रहेगी. राजनीतक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं कि नीतीश इस ब्लॉक को टेकेन फॉर ग्रांटेड मानकर नहीं चलें. यह वर्ग फिलहाल सशक्तिकरण के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में यह पॉलिटिकली कमिटेड नहीं होगा. कोई भी दल इसमें सेंध लगा सकता है और यह किसी के तरफ जा सकता है. रामनाथ को टिकट देने से बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है देखना यह होगा कि ये लोकसभा में अतिपिछड़ी जाति से कितने को टिकट देते हैं. सुमन की बातें सही भी हैं. 2009-10 में नियोजित शिक्षक नीतीश के उत्साही समर्थक माने जाते थे. नीतीश उनकी महत्वाकांक्षा को पर नहीं लगा सके और आज ये नीतीश के प्रबल विरोधी हैं. ठीक इसी प्रकार से अतिपिछड़े वर्ग को भी देखा जा सकता है. यह सच है कि अतिपिछड़े का ऐतिहासिक जुड़ाव नीतीश के प्रति है. लेकिन नीतीश ने इस वर्ग को पॉलिटिकली चार्ज किया है, इसे स्वर दिया है. अब यह वर्ग सत्ता में अपनी भागीदारी चाहता है और उसे अब अपना नायक चाहिए. फिलहाल इस वर्ग की महत्वाकांक्षा को पूरा करना किसी भी दल के वश की बात नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
1 YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

जिगर शरीर का ठोस अंग
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
डॉ. राजेश कुमार
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo - XT
AREX
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo - XT
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA MARITIMA REPL डालना उचित होगा। रिचा स्वामी, राजस्थान
... भी समर्थ नहीं हो पाता हूं। स्थायी उपचार बतायें। सुधीर सिंह, जयपुर
उत्तर : सुधीर जी! बाबासीर की रोकथाम के लिये आप पाइलेलैक्स लिफलेट के निर्देशानुसार इस्तेमाल करें और विगोरा 5x ...
Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आएंगी।
प्रश्न : बालों के निरन्तर झड़ते रहने के कारण ...
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला, फेक्ट्रल, पटना - 801505
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051
किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

आपका शानदार घर बर्बाद ना हो!
घर बनाने से पहले आइये कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें
* क्या आप जानतें हैं बिल्डिंग मेटेरियल्स पर करीब 28 से 30 परसेन्ट टैक्स लगा रहता है। सभी अच्छी कम्पनी का सामान का वैट बिल लेने पर आपको कोई टैक्स देना नही पड़ता है। सभी अच्छी कम्पनियां सभी टैक्स पेड माल अपने डीलर या रिटेलर को सप्लाई करती है।
* आप अपना घर बनाने में अगर 25 लाख खर्च करते हैं तो उस पर करीब 7 लाख टैक्स भारत सरकार एवं राज्य सरकार को मिलता है। जो वापस आपके लिए ही सरकार खर्च करती है।
* आप बिल्डिंग मेटेरियल्स खरीदते समय वैट बिल नही लेते हैं तो आपका रुपया तो जाता ही है, आपको नकली सामान भी मिलता है, जैसे आप 20 किलो का वॉल पुटटी जिस पर कीमत रु0. 800 लिखा है उस पर कम्पनी रु0.69 एक्साईज डयूटी एवं वैट 96 रुपया टोटल 165 रु0 टैक्स कम्पनी लिए हुए रहती है। परन्तु आपके छोटी सी भूल से आप बिना वैट बिल का नकली सामान खरीद लेते हैं। जिससे जिस सामान की लाईफ 10 साल होनी चाहिए वह सामान साल भर में ही खराब होने लगता है। अपने शानदार घर को बर्बादी से बचाने के लिए सभी सामान का वैट बिल अवश्य ले लें। आपकी सावधानी से आपके घर की लाईफ कई गुणा बढ़ जायेगी।
राजस्थान के चुनिन्दा जिप्सम से बना बेहतरीन क्वालिटी का
विश्वस्तरीय क्वालिटी एवं पैकिंग में
ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस
Made from Imported Chemicals
ITALIAN Beauty Wall Putty
ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार क्वालिटी एवं पैकिंग में भारत का नं0 1 वॉल पुटटी
सबसे किफायती 40 किलो पैक
ईटालियन ईन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण पेरिस की अपेक्षा आपके दीवारों एवं मकानों को ज्यादा सुन्दर बनाता है ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा मजबूत होने के कारण यह ज्यादा फैलता है, कड़े क्वालिटी कन्ट्रोल में बना हुआ सुपर स्ट्रांग, सुपर स्मूथ एवं सुपर कवरेज वाला भारत का सबसे बेहतरीन ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस।
लक्की ड्रॉ में 1 किलो 24 कैरेट सोना
24 कैरेट 10 ग्राम सोने का 100 सिक्का 100 लोगों को
डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप
अपने फर्म का नाम पूरा पता एवं वैट नं० के साथ एस.एम.एस या मेल करें
Mob-09549663640 E-mail- shalimarpop@gmail.com *शर्तें लागू
प्लास्टर ऑफ पेरिस
* प्लास्टर ऑफ पेरिस खरीदते समय बोरी का वजन जरुर चेक करें, क्योंकि साधरण प्लास्टर ऑफ पेरिस 20 किलो के बोरी में 16 किलो ही आता है, बिना वैट बिल का प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिटटी मिला हो सकता है। जिससे आपके फाल्स सिलींग या पी0 ओ0 पी0 का काम साधारण क्वालिटी का होगा।।।।।
* प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके पूरे घर की सुन्दर पेन्टिंग का बेस होता है, अगर वही साधारण क्वालिटी का होगा तो आपके कीमती पेन्टिंग का भविश्य क्या होगा आप खुद सोचिये ।।।।
* ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो साधारण प्लास्टर ऑफ पेरिस की तुलना में दुगुणा फैलता है, शानदार क्वालिटी शानदार पैकिंग साथ ही 1 किलो 24 कैरेट सोना* के साथ।
वॉल पुटटी के बारे में जानिए
वॉल पुटटी के बोरी में अधिकतर कम्पनियां रुपये का कूपन डालती है जांच करें बिना वैट बिल का वॉल पुटटी नकली हो सकता है, जिसमें केमिकल की सही मात्रा नही होती है, जबकि असली वॉलपुटटी में केमिकल 200 से 450 रुपये किलो का लगता है, एक बोरी ऑरिजीनल वाल पुटटी पर करीबन 200 रुपये टैक्स लगा रहता है जो सभी कम्पनी को देना होता है लेकिन नकली माल बनाने बाले टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन आपसे पूरा कीमत वसूल लेते हैं। आपकी जरा सी सावधानी से वैट बिल के साथ खरीदारी पर आप हमेशा असली सामान ही खरीदेगें।
प्रिय ग्राहक कृपया ध्यान दें
हमारी कम्पनी सभी माल टैक्स पेड देती है, आपको अलग से कोई टैक्स नही देना है, ऑरिजीनल सामान के लिए वैट बिल अवश्य ले लें तभी आप 1 किलो सोना के लक्की ड्रा स्कीम में शामिल हो सकते हैं।
अपने देश हित में, अपने राज्य हित में वैट बिल अवश्य लें
वैट बिल लेना आपका अधिकार है, ओरिजीनल सामान की पहचान है।
Required: Sales Manager & Asst. Sales Manager for Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, M.P., Chhatisgarh, Haryana. Punjab, Bihar, Jharkhand, J&K, U.P, Mumbai, Delhi & Himachal Experienced person with P.O.P. marketing knowledge. Send Resume by mail only. e-mail. shalimarpop@gmail.com

जब 18 अगस्त 2006 को जब बिहार सरकार के तत्कालीन लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने इस टंकी का उद्घाटन किया था तो यहां की जनता को लगा था कि अब उन्हें शुद्ध पानी नसीब होगा लेकिन ऐसा हो नहीं सका. उद्घाटन के ठीक एक वर्ष बाद उसमें लगा मोटर चोरी हो गया. इसकी प्राथमिकी भी संग्रामपुर थाने में दर्ज है.

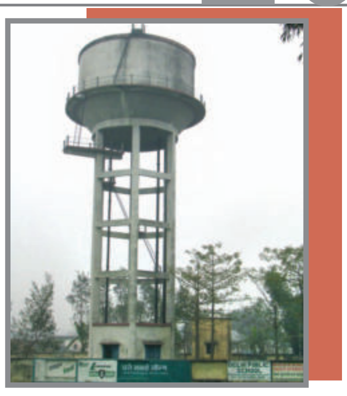

भाजपा में दावेदारों की फ़ौज

कपिल कुमार

आसन्न संसदीय चुनाव को लेकर मधुबनी की राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं. खासकर भाजपा-जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की. हालांकि खरमास बीतने के बाद भी किसी गठबंधन या उम्मीदवार का नाम अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, बावजूद इसके जनसभा, रैली, धरना, प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है. टिकट को लेकर दलों में आपसी खींचातानी कोई नई बात नहीं है. लेकिन इस बार उम्मीदवारी देने से पूर्व सभी दलों द्वारा सावधानी बरतते हुए संभावनाओं की पड़ताल कर लेना जरूरी माना जा रहा है. साथ ही दूसरे दल के द्वारा पेश किए जाने वाले उम्मीदवार के नाम का इंतजार किया जा रहा है. टिकट अभिलाषी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, खासकर भाजपा में

कभी खुद में भी पीएम मेटेरियल्स बता कर मोदी समर्थकों की आखों की किरकिरी बन चुके यादव के साथ उम्र की भी एक समस्या है, जो मोदी के युवा भारत के अनुरूप नहीं रह गई है. दूसरी ओर राजद पिछले चुनाव में इस सीट पर कम अन्तर से मिली हार को इस बार के चुनाव में पूरा कर लेने का हर संभव उपाय तलाश जरूर करेगी.

इसका असर साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है. हालांकि पार्टी के नेता-कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर किसी मनमुटाव या खींचतान, गुटबाजी होने की बात को खारिज तो जरूर करते हैं, लेकिन सतह तक जो बात उभर कर आ रही है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्दर खाने में कुछ जरूर पक रहा है. इसका मुख्य कारण छह-सात माह पूर्व राजग में टूट और दिल्ली में आप पार्टी के उदय को माना जा रहा है. आप ने स्थापित दलों को अपनी राजनीतिक रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है. यद्यपि मधुबनी के भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव को ही फिर से उम्मीदवारी मिलने की संभावना है. साथ ही अनुमान यह भी है कि इस बार उनका निर्वाचन क्षेत्र बदल भी सकता है, जैसा कि पार्टी सूत्र बताते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या यादव इसके लिए तैयार होंगे? वजह यह कि वे दो बार भाजपा से और पूर्व में एक बार सोशलिस्ट के टिकट पर यहीं से लोक सभा का सफर कर चुके हैं और उनकी यह कर्मभूमि समझी जाती है. पार्टी के अन्दर भी उनकी उम्मीदवारी को लेकर विरोधी स्वर प्रखर हैं, जिसकी मुख्य वजह उनके बड़बोलेपन को बताया जा रहा है.

कभी खुद को भी पीएम मेटेरियल बता कर मोदी समर्थकों की आंखों की निगाहों में बुरे बन चुके यादव के साथ उम्र की भी एक समस्या है, जो मोदी के युवा भारत के अनुरूप नहीं रह गई है. दूसरी ओर राजद पिछले चुनाव में इस सीट पर कम अन्तर से मिली हार को इस बार के चुनाव में पूरा कर लेने का हर संभव उपाय तलाश जरूर करेगी. हालांकि कांग्रेस से उसका गठबंधन अभी तक स्वरूप नहीं ले सका है, फिर भी इसे लेकर उम्मीद अभी बरकरार है. अगर दोस्ती होती है, तो यह सीट कांग्रेस के लिए राजद को छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जिले के दूसरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर की सीट से जदयू से निष्कासन झेल रहे वर्तमान सांसद मंगनीलाल मंडल इस बार राजद के लालटेन के सहारे पुनः चुनावी मैदान में उतरने की संभावना तलाश रहे हैं, जो लगभग तय माना जा रहा है. अगर ऐसा कुछ हुआ तो मधुबनी क्षेत्र से पिछले चुनाव में राजद के दूसरे स्थान पर रहे अब्दुल बारी सिद्दिकी के लिए निर्णय करने का समय होगा, क्योंकि जदयू इस सीट पर किसी अल्पसंख्यक चेहरे को तलाश रही है. संभव है वह किसी बाहरी को ही यहां से चुनाव में उतारे, क्योंकि मधुबनी में पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पार्टी की नैया पार लगा सके. झंझारपुर सीट से किसी अति पिछड़ा को उतारने का जदयू की रणनीति लगभग तय मानी जा रही है. वैसे किसी भी अंतिम निर्णय के लिए जदयू की संकल्प रैली का इंतजार करना होगा. ऐसे में भाजपा के लिए यह निर्णय करना थोड़ा मुश्किल का काम नजर आ रहा है कि वह अपना उम्मीदवार किसे बनाए. हुकुमदेव नारायण यादव के बाद भाजपा के लिए इस क्षेत्र से जो एक चेहरा है, वह है प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता एवं बेनीपट्टी क्षेत्र के विधायक विनोद नारायण झा लेकिन पार्टी में इस बात पर भी एक मत नहीं है कि किसी विधायक को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए. दूसरी ओर इन सारी संभावना-आशंकाओं के बीच टिकट अभिलाषी नेता दिल्ली में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक के बहाने डेरा जमाकर बैठे हुए हैं. इनमें मधुबनी से प्रफुल्ल चंद्र झा जिन्हें मोदी के निकटतम सहयोगी का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही संघ के सदस्य होने से प्रबल दावेदार माना जा रहा है, साथ ही मृत्युन्जय झा का भी नाम चल रहा है, वहीं झंझारपुर से सुमन महासेठ को प्रवल दावेदार के रूप में माना जा रहा है, इसके अलावा बालेश्वर सिंह भारती और आनन्द कुमार झा भी इस दौड़ में शामिल हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे चयन करती है और किसका भाग्य साथ देता है. वैसे भी टिकट मिलना एक बात है, चुनाव जीतना दूसरी बात. क्योंकि लोकतंत्र में तो मतदाता ही यह तय करता है कि उसका रहनुमा कौन होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

जनता को शुद्ध पानी भी नसीब नहीं

मुकुल पाण्डेय

विभागीय उदासीनता की वजह से संग्रामपुर की जनता परेशान है. सरकार की तमाम वादों कोशिशों के बाद भी वहां की जनता को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है. मामला यह है कि अरेराज अनुमण्डल के संग्रामपुर में करोड़ों की लागत से आठ वर्ष पूर्व बनकर तैयार पानी टंकी सरकारी उपेक्षा का शिकार है. इसे चालू करने व आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई सरकारी व विभागीय कार्रवाई दिखावा साबित हो रही है.

जब 18 अगस्त 2006 को जब बिहार सरकार के तत्कालीन लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने इस टंकी का उद्घाटन किया था तो यहां की जनता को लगा था कि अब उन्हें शुद्ध पानी नसीब होगा लेकिन ऐसा हो नहीं सका. उद्घाटन के ठीक एक वर्ष बाद उसमें लगा मोटर चोरी हो गया. इसकी प्राथमिकी भी संग्रामपुर थाने में दर्ज है. जिला पार्षद राजन मिश्रा द्वारा जिला पार्षद की समान्य बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया और पीएचइडी विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब भी किया गया लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई. स्थानीय विधायक सचिन्द्र सिंह व गोविन्दगंज विधायक मीना द्विवेदी इस बाबत बिजली नहीं मिलने को कारण बताते हैं जबकि बिजली विभाग जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने का दावा करता है. दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता यतीन्द्र कश्यप, दिग्विजय सिंह, राजद नेता डॉ. राजेश कुमार, सोरेन सहनी, वासुदेव राय, अमरेश लाल, कम्युनिस्ट नेता रामाशरण यादव व बुनीलाल सहनी आदि इसे सरकार की विफलता का परिणाम बताते हैं. इन लोगों का कहना है कि धोषणाओं पर टीकी यह सरकार केवल शिलान्यास व उद्घाटन के नाम पर जनता को गुमराह करती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नगर निगम बेगूसराय के बढ़ते कदम

26 जनवरी 2014 गणतंत्र दिवस के शुभअवसर पर जिलावासियों को हार्दिक बधाई

- शहर में जलजमाव न हो इसलिए नालो की उड़ाही लगातार की जा रही है।
- संक्रामक रोग पर नियंत्रण के लिए कीटनाशन/फॉगिंग का छिड़काव किया गया है और पुनः कराया जा रहा है।
- नगर क्षेत्र के सफाई की समुचित व्यवस्था की जा रही है। जिसके अंतर्गत नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 100 पीस लोहे का डस्टबीन पर 500 पीस रोडसाईड ट्वीन्स बिन्स लगाया जा रहा है।
- जनता से अपील है कि वे कूड़ा-कर्कट, पलास्टिक की पन्नी, थर्मोकोल वगैरह को नालों में न डालकर निर्धारित स्थान प्रातः 09.00 बजे के पूर्व डालें और शहर को साफ-सुथरा रखें।
- होल्डिंग कर दाताओं से अपील है कि वे अपना बकाया कर का भुगतान शीघ्र करें और दण्ड शुल्क के भागी न बनें।
- नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों के आवागमन के मद्देनजर प्रत्येक वार्ड में 50-50 पीस स्ट्रीट लाईट लगवाया गया है।
- नगर निगम क्षेत्र के गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों के बीच वर्ष 2014 में कुल 13500 पीस ऊनी कंबल का वितरण किया गया है।
- नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लगभग सात करोड़ रूपये राशि के तहत विभिन्न चयनित योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।
- स्पर कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम कार्यालय का रेनोवेशन का कार्य कराया गया है।
- होर्डिंग एवं बोर्ड लगाने वालों से अपील है कि वे निर्धारित शुल्क नगर निगम में जमा कर ही होर्डिंग लगाये अन्यथा उनके होर्डिंग जब्त कर लिये जायेगें।
- मोबाईल टावर कंपनी वालों तथा भवन के उपर मोबाईल टावर लगाने वालों से अपील है कि वे नगर निगम में रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं सालाना कर जमा कर ही मोबाईल टावरन लगाये अन्यथा जबसे टावर अधिष्ठापित हुए हैं तब से सभी शुल्क, दण्ड शुल्क के साथ वसूली की जायेगी।
- भवन/दूकान मालिकों से अपील है कि वे अपने भवनों के सामने स्थित नालों पर स्थायी रूप से ढक्कन न लगाये अन्यथा नाली उड़ाही के दौरान ढकक्न को हटा दिया जाएगा एवं क्षतिग्रस्त होनेवाले ढक्कनों की मरम्मति पर व्यय होनेवाली राशि आपसे वसूल की जायेगी।
- निजी बस पड़ाव एवं हरहर महादेव चौक के निकट नगर निगम द्वारा गरीबों के लिए संचालित रेन बसेरा (आश्रय स्थल) का लाभ निःसहाय व्यक्ति निःशुल्क उठायें।

संजय कुमार
महापौर

नगर निगम बेगूसराय

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

10 फरवरी –16 फरवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

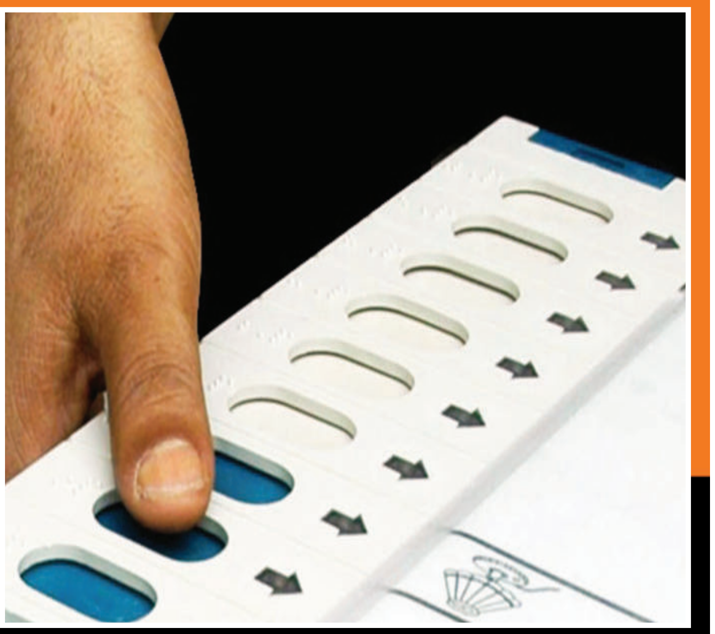

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

अजय कुमार

यूपी : योगी-जोशी पर भारी मोदी

भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि देश की राजनीति में यूपी की स्थिति 'एक साधे सब सधे' जैसी है. यूपी के बिना भाजपा का '272 प्लस' मिशन पूरा करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है. जहां एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता और वाराणसी के सांसद मुरली मनोहर जोशी के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर सस्पेंस है, वहीं सांसद योगी आदित्यनाथ का दायरा सीमित है. ये ऐसे कारण हैं, जिसे देखते हुए नरेंद्र मोदी मिशन यूपी को पूरा करने के लिए यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं.

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी की उत्तर प्रदेश में छह रैलियां, जिसमें से तीन पूर्वांचल (बहराइच, वाराणसी और गोरखपुर) में होना. उनके (मोदी) सबसे वफादार साथी अमित शाह का यूपी का चुनाव प्रभारी बनना. शाह का पूरे प्रदेश के मुकाबले पूर्वांलच पर ज्यादा ध्यान देना. भाजपा के दिग्गज नेता और वाराणसी के सांसद मुरली मनोहर जोशी के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर सस्पेंस. ऐसे तमाम कारण हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नरेन्द्र मोदी पूर्वांचल में किसी 'तीन-तेरह' में लगे हैं. वह मिशन यूपी को पूरा करने के लिए यहां की किसी सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं. पूर्वांचल में भाजपा सिर्फ सांसद योगी आदित्यनाथ जैसे चंद नामों के भरोसे नहीं बैठना चाहती है, जिनका दायर सीमित है. गोरखपुर की रैली में मोदी के रंग में योगी का रंगा जाना. योगी का हिन्दुत्व का एजेंडा मोदी के सामने ठंडे बस्ते में चला जाना. हाल में ही लोकमंच के संयोजक और वर्षों तक मुलायम के वफादार रहे अमर सिंह का बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी की तारीफ करना और मुलायम को आड़े हाथों लेना बदलाव की राजनीति के संकेत हैं. मोदी यूपी में कहीं से भी चुनाव लड़ें, इसका प्रभाव पूरे प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा.

विभिन्न सर्वे रिपोर्ट भाजपा को यूपी में 35 के करीब सीटें दे रही हैं, लेकिन इससे आलाकमान को संतोष नहीं हो रहा है. आरएसएस और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यहां पार्टी को उस सुनहरे दौर में ले जाना चाहता है, जब पार्टी यहां 50 का आंकड़ा पार कर लेती थी. इस दौर में भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी का राज्य में दबदबा था. पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता कल्याण सिंह जैसे नेताओं की राज्य की सियासत में मजबूत पकड़ थी. उत्तर प्रदेश भाजपा के अन्य बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, केशरी नाथ त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, सूर्य प्रताप शाही, लाल जी टंडन, योगी आदित्य नाथ, डॉ नेपाल सिंह, साक्षी महाराज आदि तमाम नेता अपने-अपने इलाके में पकड़ बनाए हुए थे. पूरे प्रदेश में हिन्दुत्व का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा था. सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था.

उक्त नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के आभा मंडल में सूबे की सियासत परवान चढ़ रही थी, जिसके चलते निचले स्तर पर फैला पार्टी का कलह-कलेश और गुटबाजी हासिये पर चली गई थी. अगर कहीं थोड़ा-बहुत मनमुटाव दिख रहा था तो वह चंद बड़े नेताओं के बीच का मसला बनकर रह गया था. इस समय कल्याण सिंह, राजनाथ और कलराज मिश्र विपरीत ध्रुव बने हुए थे, जिसके चलते कल्याण सिंह को दो बार पार्टी से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ गया. आज फिर कल्याण भाजपा का झंडा लहरा रहे हैं. राजनाथ और कलराज मिश्र भी टांग खिंचाई की राजनीति से दूर हो गए हैं. फिर भी भारतीय जनता पार्टी के रसातल में जाने का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है. भाजपा की तकदीर 'जब दांत थे तो चने नहीं, जैसी होकर रह गई है. अटल बिहारी वाजपेयी की कमी, कल्याण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की धार कुंद हो जाना और स्थानीय नेताओं में संघर्ष का माद्दा खत्म हो जाने की वजह से पार्टी पनप नहीं पा रही है. अटल जी गुजरे जमाने की बात होकर रह गए हैं. अटल ने 2004 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की हार और केन्द्र में यूपीए की सरकार बनने के बाद अटल जी धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति से दूर होते गए. 2009 के लोकसभा चुनाव तक वह नहीं लड़े. इसका प्रभाव यह पड़ा की यूपी में कभी सांसदों का अर्धशतक लगाने वाली भाजपा के सांसदों की संख्या दहाई का आंकड़ा (दस सीटें) भी मुश्किल से छू पाई. विधानसभा चुनाव में भी यही इतिहास दोहराया जा रहा था. पार्टी कमजोर पड़ी तो गुटबाजी चरम पर पहुंच गई. कुछ नेता पार्टी को मझधार में छोड़कर अन्य दलों की शरण में चले गए तो कई ने अपने आप को सीमित कर लिया.

एक तरफ सबसे अधिक सीटों वाले हिन्दी शासित प्रदेशों उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भाजपा कमजोर पड़ रही थी तो दूसरी तरफ अप्रत्याशित रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी था. गुजरात में नरेन्द्र मोदी का सिक्का चल रहा था. कनार्टक में आश्चर्यजनक रूप से येदुरप्पा ने भाजपा को सत्ता दिला थी. बिहार में लालू राज से परेशान जनता ने उनका सूपड़ा साफ किया तो नीतीश कुमार की सरकार का गठन हुआ. जनता दल युनाइटेड से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पंख फैला लिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत पतली होती गई. देश के किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का गौरव उत्तर प्रदेश को पहली बार मिला जरूर था, लेकिन यह दौर लम्बे समय तक नहीं चल पाया.

लम्बे समय के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी के कारण हर्ष का माहौल है. जो यूपी में पूरी ताकत झोंके हुए हैं. मोदी की वजह से ही विभिन्न सर्वे यूपी में भाजपा को जबरदस्त फायदा होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं. मोदी के कारण यूपी में भाजपा की जीत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है. इसका एहसास उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी अमित शाह को भी है. बीते दिनों मोदी का नाम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर उछाला भी जा चुका है. इस समय अमित शाह का सारा फोकस वाराणसी संसदीय सीट पर टिक गया है. जरूरी नहीं कि मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेगें, मगर संभावनाओं को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है.

पूर्वांचल में 'जोशी की जगह मोदी' का नारा गलियों में गूंज रहा है. नरेन्द्र मोदी की वाराणसी और गोरखपुर की विजय शंखनाद रैली के बाद अमित शाह का बलिया, गाजीपुर व वाराणसी का दौरा अहम माना जा रहा है. वह बंद कमरों में इन नेताओं से सलाह-मशविरा कर रहे हैं, जिन्हें मोदी का करीबी माना जाता है. खबर यह भी आ रही है कि अमित शाह पूर्वांचल की तमाम सीटों के लिए प्रत्याशी छांटने का काम कर रहे हैं. हालांकि वह इस मसले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं और ज्यादा कुरेदने पर इतना ही कहते हैं कि इस बात का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा. जब उनसे पूछा जाता है कि वाराणसी से मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी ही चुनाव लड़ेंगे तो वह इतना भर कहते हैं कि अभी किसी भी सीट पर उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ है. वह यह भी दावा करते हैं कि पूर्वांचल में मोदी की लहर चल रही है, जिसे जीत में बदला जा सकता है.

बहरहाल, थोड़ी बात भाजपा से अलग कांग्रेस कि की जाए तो कांग्रेस यूपी में मोदी की सक्रियता से बुरी तरह बेचैन है. जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने नाराज चल रहे सुल्तानपुर के लोकसभा सांसद संजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की बजाए राज्यसभा में भेजने का फैसला किया, उससे कांग्रेस के बड़े नेताओं की बेचैनी भी साफ हो गई. सुल्तानपुर संसदीय सीट पर इस बार से भाजपा की तरफ से वरुण गांधी के चुनाव मैदान में उतरने की बात कही जा रही है. इसी के चलते संजय सिंह परेशान थे. वह अपने लिए राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे. ऐसा न होने पर वह पाला बदल कर भाजपा के पक्ष में जाने तक की हद पर पहुंच गए थे. संजय सिंह के जाने से पूरे क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है. अमेठी संसदीय सीट भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती. संजय की अमेठी में अच्छी-खासी पैठ है. संजय को रोक कर कांग्रेस ने कम से कम एक मोर्चे पर तो फतह हासिल ही कर ली. अब राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार कुमार विश्वास की ही चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो लगातार राहुल के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस्तीफा दे दिया है. राज्य में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तो चौथी दुनिया ने इस रहस्य का उद्घाटन किया था कि साढ़े चार सौ करोड़ की मोटी धनराशि खर्च कर के एक उद्यमी परिवार ने उन्हें अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनवाया था. इस समाचार से इस सच से पर्दा उठा था कि किस तरह से एक जमीनी कार्यकर्ता का वास्तविक हक कांग्रेस हाईकमान ने मारते हुए धनबल के आधार पर सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी को बेच दिया था. जज से राजनीति में आए विजय ने कुर्सी मिलते ही न्याय करना छोड़ दिया. पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने मुख्य सचिव के वास्तविक दावेदार अजय कुमार जोशी के साथ अन्याय किया. जोशी जी आईएएस बैच के टॉपर होने के साथ उत्तराखंड मूल के निवासी भी थे. उन्हें वरिष्ठता क्रम में मुख्य सचिव की कुर्सी सौंपी जानी थी. ऐसा न होने के पीछे भी उनके कार्यप्रणाली पर उंगुली उठी. बस यहीं से विजय के राज में उत्तराखंड में धन उगाही और भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो गया. हर बड़ी कुर्सी को पाने, बड़ा ठेका पाने के लिए नियमों को ताक पर रख कर दलालों के माध्यम से काम और पद का विभाजन शुरू हो गया. मुख्यमंत्री की कुर्सी अनीतिपूर्वक हथियाने के बाद उन्हें यह समझ में आ गया कि उन्हें हर अनैतिक कार्य करने का लाइसेंस कांग्रेस हाईकमान ने दे दिया है. सूबे में ईमानदार अधिकारी को साइडलाइन कर दिया गया और दागियों को खोज-खोज कर कुर्सी सौंपी गई. मुख्यमंत्री के बदले रुख से राज्य की अफसरशाही बेलगाम हो उठी.

जून 2013 में हिमालय के केदारखंड सहित उत्तरकाशी में जिस तरह दैवी कोप आया, उससे पूरा उत्तराखंड हिल उठा. एक पखवाड़े तक चले प्रकृति के इस तांडव ने देवभूमि के जर्रा-जर्रा को हिला कर रख दिया था. इस आपदा से भी तीन दिनों तक बहुगुणा सरकार बेखबर रही. जब चारों ओर मौत की चीखें सुनाई देने लगी, तब सीएम साहब को समझ में आया कि पानी अब नाक के ऊपर बह चला है. इसके बाद उन्होंने आनन-फानन में भारत सरकार से सेना भेजन के लिए आग्रह किया. सेना को बुलाकर सूबे की सरकार ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली. सेना ने जिस साहस से आपदा में फंसी जनता का हाथ थामा, वह बेमिशाल था. सच पूछा जाए तो अगर सेना नहीं होती तो देवनगरी का नजारा और भी विभत्स होता. इस आपदा ने कांग्रेस हाईकमान को भी हिला कर रख दिया. राहुल-सोनिया ने भी अपने तरीके से जनता का आंसू पोंछा. बहुगुणा को जनता के भारी आक्रोश का सामना पूरे प्रदेश में करना पड़ा. आपदा से तंग जनता को मदद की दरकार थी. सरकार जनता में विज्ञापनों में ही दिख रही थी. इस आपदा के बाद ही कांग्रेस हाईकमान को बहुगुणा सरकार के नकारापन की भनक लग गई थी. इसके बाद भी हाईकमान की एक गलती के कारण बहुगुणा पर लगाम नहीं लगाया जा सका. चार राज्यों में मिली करारी हार ने कांग्रेस हाईकमान को झकझोर कर रख दिया. उत्तराखण्ड के मिशन 2014 से जुड़ी गोपनीय रिपोर्ट में जिस तरह से बहुगुणा सरकार के प्रति जनता में बढ़ रहे आक्रोश की बात पता चली, उससे पूरी कांग्रेस हिल उठी. इसी के बाद बहुगुणा की विदाई तय मानी जाने लगी. कांग्रेस को अब स्पष्ट रूप से एक अदद जमीनी कार्यकर्ता की आवश्यकता थी, जो राहुल के मिशन 2014 की पतवार थाम सके.

बहुगुणा को दो वर्ष के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा. नवगठित हिमालयी राज्य की यह विडम्बना ही कही जा सकती है कि उसके अपने 14 वर्ष के अल्पकाल में सात मुख्यमंत्री हुए. बहुगुणा ने अपने कार्यकाल में केदारघाटी में आई दैवी आपदा में अकर्मण्यता का परिचय दिया और पहाड़ के चंदन के रूप में जाने जाने वाले अपने पिता हेमवती नन्दन का नाम भी खराब किया. विजय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस फितरत के साथ सितारगंज सीट से विजय प्राप्त की, उससे लोगों में उनकी सेवा के प्रति एक विश्वास जगा था. टिहरी संसदीय सीट पर उनके पुत्र साकेत की हार कांग्रेस हाईकमान के लिए राज्य की जनता द्वारा खुली चेतावनी थी. अगर बहुगुणा को कांग्रेस हाईकमान इसी समय विदा कर देता तो कांग्रेस सम्भावित क्षति से बच सकती थी. मिशन 2014 को सुखी बनाने के लिए कांग्रेस ने देर से ही सही, लेकिन जो दुरुस्त कदम उठाया है, उसका लाभ कांग्रेस को अवश्य मिलेगा. सूबे में बहुगुणा ने भ्रष्ट अफसरशाही का एक गिरोह बना लिया था. अपनी झूठी शोहरत दिखाने के लिए तीन नामी चैनलों के विज्ञापनों पर कई करोड़ रुपये पानी की तरह बहाए. जज से राजनीति में आए नेता ने अपने साथ अपने युवा पुत्र पर भी दलाली का जो लेबल लगाया, उससे कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैरत में हैं. उनके विदाई के साथ साकेत की कहानी भी लगभग खत्म हो गई है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की विदाई की चर्चा एक पखवारे से होती रही थी. हर दिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने दागी अफसरों की फौज के साथ बहुगुणा दस जनपथ के दरबानों तक चक्कर काटते रहे. अन्तत: उन्हें बड़ी बेरुखी से पद छोड़ने की फरमान सुना दी गई.

कांग्रेस हाईकमान ने संसदीय चुनाव के तीन माह पूर्व हरीश रावत जैसे ईमानदार कार्यकर्ता एवं नेता पर दांव खेला है. रावत कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षित कार्यकर्ता के साथ-साथ जमीन से जुड़े नेता की छवि वाले नेता हैं. सांसद, भारत सरकार में मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवक की तरह कार्यशैली के कारण रावत को कांग्रेस ने अपनी पहली पसंद बनाया. रावत के मुख्यमंत्री बनते ही भाजपा के एक विधायक द्वारा कुर्सी खाली करने की पेशकश की खबर आने लगी है. देवभूमि की लोकपरम्परा के संवाहक हरीश की ताजपोशी ने हिमालयी जनता में खुशी की लहर बिखेर दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

पीलीभीत में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का गठन

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

पीलीभीत श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की एक बैठक में समस्त सदस्यों की पूर्ण सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न पदों पर निम्न लोगों की नियुक्ति की गई है.

जिलाध्यक्ष–बुद्धसेन शर्मा

उपाध्यक्ष–प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विनय सक्सेना, नवीन अग्रवाल, सत्यवान अवस्थी

जिला महामंत्री–नीरजराज सक्सेना

मंत्री–मंजीत सिंह भसीन, राकेश कुमार पाठक, साकेत सक्सेना

उप मंत्री–महिपाल अग्निहोत्री, मुनेन्द्र कुमार सक्सेना

प्रचार मंत्री–प्रेमसागर शर्मा

संगठन मंत्री–एम. रफीक अनवर वारसी

कोषाध्यक्ष–डॉ. ओमप्रकाश सक्सेना 'निडर',

कार्यकारिणी सदस्य–मोहित कुमार, देवव्रत शर्मा, शिवा सक्सेना, प्रियंक अग्रवाल, ब्रजेन्द्र सिंह यादव, अनु सक्सेना, सुहेल अहमद, सुरेन्द्र सिंह सुमन, के. के. वाजपेयी. ■

feedback@chauthiduniya.com

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कृषि विभाग जनपद के कृषकों का हार्दिक स्वागत करता है

जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिए (गेहूं एवं दलहन) योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे कृषकों को निम्न सुविधाएं देय है.

1-गेहूं की 10 वर्ष से कम के अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीज पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपया 500.00/कु देय है.

2-मसूर/मटर के 10 वर्ष से कम के अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीज पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपया 2200.00/कु देय है.

3-मसूर/मटर के 10 वर्ष से अधिक के अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीज पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपया 1200.00/कु देय है.

4-गेहूं के तहत क्षेत्र प्रदर्शन पर रुपया 5000.00/हे. (कुल 500 हे.) मसूर के तहत क्षेत्र प्रदर्शन पर रुपया 5000.00/हे. (कुल 100 हे.).

जनपद में एस.आर.ई.पी. योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कृषकों को निम्न सुविधाएं देय हैं:-

1.इस योजना के अंतर्गत कृषकों को अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण, राज्य के अंदर प्रशिक्षण तथा जनपद के अंदर प्रशिक्षण की सुविधा है.

2.इस योजना के अंतर्गत कृषि से जुड़े विभाग उद्यान, पशुपालन, गन्ना, रेशम, मत्स्यपालन व दुग्ध पालन को सम्मिलित कर कृषकों को प्रदर्शन, प्रशिक्षण गोष्ठी के माध्यम से तकनीकी जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराकर आर्थिक विकास सुदृढ़ करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है.

आर. सैम्फिल
आई.ए.एस
जिलाधिकारी
कुशीनगर

जनार्दन बरनवाल
मुख्य विकास अधिकारी
कुशीनगर

गंगादीन
उप कृषि निदेशक
कुशीनगर

कार्यालय-उप कृषि निदेशक, कुशीनगर

पत्रांक 877 /विज्ञापन/2013-14 दिनांक 25/1/14

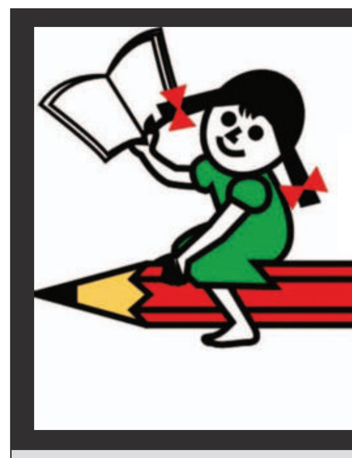

सर्व शिक्षा अभियान
कुशीनगर

सब पढ़ें सब बढ़ें

बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त अध्यापकों, कर्मचारियों, अभिवावकों व छात्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई

- बेसिक शिक्षा के उत्थान के लिए समस्त जन पारदर्शिता, ईमानदारी एवं समयान्तर्गत कार्य संपादित करें.
- जनपद में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों को मानक के अनुसार शीघ्रता से पूर्ण करा लें.
- समस्त विद्यालयों की रंगाई-पुताई, पेंटिंग 30 जनवरी, 2014 तक मानक के अनुसार पूरा करा लें.
- शिक्षक विद्यालय में रुचिपूर्ण भयरहित शिक्षण कार्य करें.
- छात्रवृत्ति का वितरण यथाशीघ्र पूर्ण कराएं.
- प्रत्येक विद्यालय में मीनू एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन का वितरण सुनिश्चित करें.
- यह ध्यान रहे कि सत्र समाप्त होने में 04 माह से भी कम समय बचा है.

(प्रदीप कुमार पांडेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कुशीनगर

(जनार्दन बरनवाल)
मुख्य विकास अधिकारी
कुशीनगर

(रिग्जियान सैम्पिल)
जिलाधिकारी
कुशीनगर

पत्रांक : एस.एस.ए/लेखा/मेमो /2013-14 दिनांक : जनवरी 2014

यूपी में मुस्लिम सियासत की बदलती तस्वीर

उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों की नजरें इस बात पर लगी हैं कि राज्य का मुस्लिम वोटर किधर जाएगा. क्या वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा या फिर कांग्रेस-बहुजन समाज पार्टी में से किसी एक को अपना नया 'सारथी' बनाएगा. कहीं आम आदमी पार्टी तो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध नहीं लगा देगी. राज्य की राजनीति में इस तरह के तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि मुस्लिम वोटर आने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को अपना वोट देते हैं.

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर माथापच्ची जारी है. कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सहित आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम वोटरों का मिजाज पढ़ने में लगी है. भाजपा को इस बात की उम्मीद तो नहीं है कि इसे अल्पसंख्यक वोट मिलेगा, लेकिन वह यह भलीभांति जानती है कि मुस्लिमों के वोट किसी भी पार्टी के खाते में जाए, इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर जरूर पड़ता है. भाजपा की हमेशा यही मंशा रहती है कि अल्पसंख्यक वोट किसी एक पार्टी के पक्ष में पड़ने के बजाय तमाम दलों में बंट जाए. इसके लिए वह समय-समय पर अपनी रणनीति में बदलाव भी करती रहती है. इस बार भी ऐसा कर रही है. इसके एजेंडे में न तो राम मंदिर है, न मथुरा-काशी. समान नागरिक संहिता और धारा 370 के खिलाफ इसके तेवर नर्म पड़ गए हैं. विश्व हिन्दू परिषद के कट्टर छवि वाले नेताओं प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल से भाजपा ने दूरी बना रखी है. मंच से जय श्री राम के नारे अब सुनाई नहीं देते. इसकी जगह 'भारत माता की जय' और 'वंदेमातरम' ने ले ली है. भाजपा की सोच यही है कि ऐसा कुछ न बोला और कहा जाए, जिससे मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण जैसे हालात पैदा हो जाएं.

भाजपा को मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से डर लगता है तो अन्य दल किसी भी तरह मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने को उतवाले रहते हैं. इसके लिए तमाम नुस्खे अपनाए जाते हैं. कभी मुसलमान कांग्रेस का मजबूत वोटर हुआ करते थे, लेकिन राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद बढ़ने के बाद मुस्लिम राजनीति ने तेजी से करवट ली. कांग्रेस से यह वोट बैंक धीरे-धीरे खिसकने लगा. इंदिरा गांधी के समय में मुस्लिमों की नाराजगी कांग्रेस से बढ़ना शुरू हुई तो मुस्लिम मतदाता कभी किसी तो कभी किसी दल के पीछे लामबंद होते रहे. इस दौरान मुसलमानों के नाम पर कुछ दल भी बने, लेकिन वह अपनी छाप नहीं छोड़ पाए. इसके बाद भी मुसलमानों के नाम पर दल खड़े करने का रिवाज बंद नहीं हुआ. 1968 में कांग्रेस से नाराजगी के बाद डॉक्टर फरीदी ने मुस्लिम मजलिस की स्थापना जरूर की, लेकिन वह मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत पाए. इसके बाद इसी तरह के प्रयास समय-समय पर होते रहे. इंडियन नेशनल लीग, पीपुल्स डेमोक्रेटिव फ्रंट, यूपीयूडीएफ, यूडीएफ, मोमिन कॉन्फ्रेंस, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, कौमी एकता दल, पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल जैसे तमाम दल बने, पर मुसलमानों की उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरा. बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुसलमानों के बीच अलग पार्टी बनाने की चर्चा काफी तेजी से उभरी, लेकिन इसका फायदा समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव उठा ले गए.

एक बार मुलायम ने अल्पसंख्यकों का दिल जीता तो यह सिलसिला कम-ज्यादा जरूर होता रहा, लेकिन कभी थमा नहीं. बसपा ने इसमें सेंध लगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन इसमें वो बात नहीं आ पाई. सपा अधिक से अधिक मुसलमान प्रत्याशी उतारती, अल्पसंख्यकों के लिए तमाम योजनाएं बनाती, लुभावने वायदे करती. सपा ने एम (मुस्लिम) वाई (यादव) का ऐसा समीकरण बनाया, जिससे विरोधी एक बार नहीं, कई बार चारों खाने चित हो गए. मुलायम की मुस्लिम राजनीति की एक और विशेषता यह रही कि सपा का बड़े से बड़ा मुस्लिम नेता भी कभी मुस्लिम वोट बटोरने के मामले में मुलायम की बराबरी नहीं कर पाया. अल्पसंख्यकों को मुलायम पर बेहद भरोसा था. सत्ता में जब समाजवादी पार्टी आई तो इस विश्वास को मजबूत करने के लिए तीन कैबिनेट और सात राज्य मंत्री मुस्लिम कोटे से बनाए गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही राज्य मंत्रियों ने कोई काम न होने का रोना शुरू कर दिया, जिसे दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया. इसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय नाराज भी दिखा. सपा में तमाम मुस्लिम नेताओं के बीच कैबिनेट मंत्री आजम खां की ही मात्र चल रही थी. सपा आलाकमान को इस बात की चिंता नहीं थी कि आजम खां की अल्पसंख्यक समाज में कोई खास पैठ नहीं है. वह अन्य मुस्लिम मंत्रियों और नेताओं के लिए सिरदर्द बने हैं. आजम के चलते जामा मस्जिद के ईमाम अहमद बुखारी पहले ही रूठ कर अलग हो गए थे. दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ रखने वाले मौलाना तौकीर रजा ने भी लाल बत्ती का मोह छोड़कर सपा से दूरी बना ली. सपा के घोषणा पत्र के अनुरूप प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं होने से और फखरूद्दीन अली अहमद कमेटी का गठन नहीं होने का इल्जाम भी आजम पर लग रहा है. इसका कारण है अल्पसंख्यक विभाग आजम के पास होना.

इधर, दंगों के बाद डैमेज कंट्रोल के तहत सपा नेतृत्व के इशारे पर अखिलेश सरकार ने बीस मुस्लिम नेताओं को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया. मकसद, किसी तरह मुस्लिमों में पकड़ बनाए रखना था. मुस्लिम वोट बैंक बचाने के चक्कर में सपा ने कई अल्पसंख्यकों को लाल बत्ती दी तो सरकार के अंदर उनके बीच आपस में ही तलवारें खिंचने लगीं. कई परस्पर विरोधी नेता आपस में उलझने लगे. नाराजगी का आलम यह था कि कई राज्यमंत्री तो कामकाज छोड़कर अपने विधानसभा क्षेत्रों में कैद हो गए. सपा के लिए मुसलमानों की बेरुखी मंहगी पड़ सकती है, लेकिन इससे बेफिक्र समाजवादी पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2014 में भी करीब दर्जन भर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर अपनी बिसात बिछा दी है. कैराना, मुरादाबाद, अमरोहा, सुल्तानपुर, मेरठ, बरेली, बिजनौर, अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत और श्रावस्ती लोकसभा सीट पर सपा ने मुस्लिम चेहरे उतारे हैं. यह और बात है कि 2009 में समाजवादी पार्टी का एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया था. एक तरफ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक वोट बैंक सहेजने में लगी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी (आप)का खतरा इस पर मंडरा रहा है. कई मुतियों-मौलानाओं ने फतवा जारी करके मुसलमानों को 'आप' की टोपी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, का फरमान सुनाया है, इससे सपा की धड़कन बढ़ी हुई है. फतवा सुनाने वालों में दारूल उलूम वक्फ बोर्ड के मुती आरिफ कासमी, तंजीम ऑल इंडिया के अध्यक्ष मुफ्ती अहसान कासती जैसी शख्सियतें शामिल हैं. इन लोगों ने एक मौलाना के इस फरमान को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, जिसमें इसने 'आप' की टोपी मुसलमानों को नहीं पहनने की हिदायत दी थी. दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने आप के पक्ष में खुलकर मतदान किया था, जिसका काफी बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था. ऐसी ही बयार लोकसभा चुनाव के समय यदि यूपी में 'आप' के पक्ष में चल गई तो समाजवादी पार्टी मुश्किल में आ सकती है. ऐसा इसलिए होता दिख रहा है, क्योंकि वर्षों से रूढ़िवादी सोच में लिपटा मुसलमान अब वोट बैंक से आगे निकल कर विकास में भागीदारी चाहता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा सांसद ने सीएम की तुलना मुगल शासक से की

रवि प्रकाश

सपा को पार्टी के भीतर से उठने वाले विरोध के स्वर रास नहीं आ रहे हैं. मुजफ्फरगर दंगों के बाद लोकसभा का टिकट वापस लौटा कर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सपा के बड़े नेताओं में शुमार सोमपाल शास्त्री और दबंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विरोध का जो बिगुल बजाया था, वह आगे ही बढ़ता जा रहा है. एक तरफ सोमपाल और बृज ने टिकट लौटाया था, वहीं दूसरी तरफ कई नेता इस बात से नाराज हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है. नाराजगी में कटाक्ष भी किए जा रहे हैं. ताजा मामला सपा के बाहुबली सांसद बृजभूषण से जुड़ा है, जिन्होंने हाल में ही सपा के टिकट से चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था. बृजभूषण ने पार्टी में रहते हुए ही बगावती तेवर अपनाया और पिछले दिनों यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव नाम के मुख्यमंत्री हैं. असली मुख्यमंत्री कई हैं. अखिलेश आखिरी मुगल बादशाह साबित हो रहे हैं. प्रदेश में जगह-जगह साम्प्रदायिक बवाल हो रहे हैं. चुनावी मौसम में पार्टी के भीतर से ही विद्रोह की चिंगारी उठना सपा को कभी रास नहीं आया. अपना दामन बचाने के लिए उसने इस मामले की तोहमत विरोधियों पर लगा दी. सपा के प्रदेश प्रवक्ता और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा की आगामी लोकसभा चुनावों में जनता के बीच दाल गलने वाली नहीं है. वे मतदाताओं के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं. समाजवादी पार्टी की लहर है और लोग समाजवादी सरकार की उपलब्धियों से प्रभावित हैं. समाज के हर वर्ग की समस्याओं के निपटारे में रुचि ली गई है. इस सबसे बौखलाए विपक्षी अब अपनी समस्त मर्यादाएं भूलकर ओछी बयानबाजी पर उतर आए हैं.

चौधरी का कहना था कि बसपा राज के पांच सालों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता और यहां तक कि कालिदास मार्ग पर चलने की आजादी का भी अपहरण हो गया था. पूर्व मुख्यमंत्री की सवारी निकलते वक्त दहशत से कर्फ्यू की स्थिति होती थी. आज धरना-प्रदर्शन की छूट है, बोलने-लिखने की आजादी है और मुख्यमंत्री आवास जाना तथा उनसे मिलना बहुत आसान हो गया है. यही लोकतंत्र की पहचान है. सपा नेता ने लगे हाथों सांसद बृजभूषण की बातों का भी जवाब दे दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वालों में बृजभूषण शरण सिंह जैसे तमाम नेता हैं, जो बसपा सरकार में दुबके-दुबके फिरते थे. हर वक्त उनकी जान सांसत में रहती थी. आज मुगल सल्तनत के बादशाह के तौर पर अखिलेश यादव का नाम लेते हुए उन्हें शर्म नहीं आती है. दरअसल, उन्हें पता है कि अखिलेश यादव आपराधिक छवि के लोगों को पसंद नहीं करते हैं. उनकी दिलचस्पी स्वच्छ एवं जनहित की राजनीति में है. जमीन कब्जा करने वाले और अवैध वसूली में लगे लोग मुख्यमंत्री की छाया के पास भी नहीं फटक सकते हैं. इसलिए विपक्ष के साथ भू-माफिया तथा असामाजिक तत्व मिलकर समाजवादी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने की साजिशों में लग गए हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी में ठौर नहीं दिख रहा है, वे दल बदल कर दूसरी जगह जाने के लिए छटपटा रहे हैं. ऐसे समाज विरोधी तत्वों को कांग्रेस, बसपा और भाजपा में ही जगह मिलती है. बसपा तो अपराधियों का गिरोह ही है, जिसकी नेता ने कभी खुद ही माना था कि इसके दल में 500 अपराधी हैं. हत्या, लूट, बलात्कार में बसपा के कई मंत्री विधायक जेल में हैं या जल्दी ही वहां जाने वाले हैं.

सपा ने तीखी बयानबाजी करते हुए कहा कि जनता के बीच जो तिरस्कृत हैं, वे समाजवादी पार्टी के प्रति जनता में भ्रम फैलाने में लगे हैं. जनता उनकी बातें अब सुनने वाली नहीं है. सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व पर आक्षेप लगाने वालों की चादर कितनी काली है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का विरोध ये तत्व इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सबके साथ इंसाफ होगा, लेकिन अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा. अपराधियों की जगह जेल में होगी. प्रदेश में कानून का राज है और कानून से खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सावधान रैली में खूब बरसीं मायावती
कांग्रेस-सपा-भाजपा 'थ्री इडियट'

अजय कुमार

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने भी आम चुनाव के लिए खास अंदाज में चुनावी शंखनाद कर दिया. लखनऊ में उन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया तो दिल्ली तक में इसकी गूंज सुनाई दी. यूपी की सत्ता गंवाने के बाद मायावती पहली बार इतने बड़े मंच पर अपने लाखों चाहने वालों के सामने नजर आईं थी. पूरी तैयारी के साथ वह 'सावधान रैली' में गरजीं. शायद ही कोई ऐसा मुद्दा रहा होगा, जिसे उन्होंने न छुआ हो. मायावती विरोधियों पर काफी बरस रही थीं. करीब दो घंटे के भाषण में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा. मंच से सिर्फ मायावती का भाषण हुआ. कोई ज्यादा तो कोई कम निशाने पर रहा. उन्होंने अपने वोटरों से बसपा के हाथ में शक्ति संतुलन की चाबी सौंपने को कहा तो उन लोगों को निराश भी किया, जो यह भविष्यवाणी कर रहे थे कि मायावती इस रैली में यूपीए से अपना गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर सकती हैं. माया ने अपने समर्थकों के सामने पार्टी का नजरिया रखा. उन्हें संभावित राजनीतिक खतरे का एहसास कराया. दलित शक्ति के खिलाफ विपक्षी गठजोड़ को तोड़ने की अपील करके वह दलितों की रहनुमा बनने की ख्वाहिश को और अधिक परवान चढ़ाती दिखीं. बसपा नेत्री ने भाजपा को सांप्रदायिक करार दिया तो कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय बताया. समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बता कर बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश शासन को यूपी को क्राइम प्रदेश बनाने का श्रेय दिया. वहीं आम आदमी पार्टी (आप) को नाटकबाज का खिताब दिया गया. यह और बात थी कि मंच से बिजली-पानी के बहाने जनता को लुभाने के फेर में वह 'आप' पार्टी के पद चिन्हों पर चलती दिखीं. सर्वसमाज का नारा देने वाली मायावती इस बार दलितों के अलावा पिछड़ों-मुसलमानों के मोहपाश में फंसी दिखीं. उन्होंने आरक्षण पर सपा की सोच पर सवाल खड़ा किया तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की जरूरत वाली बात को पुन: दोहराया.

माया विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ उग्र रहीं, वहीं कई नेताओं पर उन्होंने व्यक्तिगत हमले भी किए. खासकर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव उनके निशाने पर रहे. उन्होंने मोदी के वादों की विश्वसनीयता व नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए तो 'जो गरजते हैं, वह बरसते नहीं, का मुहावरा दोहरा कर उनकी ताकत कम करने की कोशिश की. मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बेतुके बयान पर उनको आड़े हाथों लिया. केजरीवाल के संबंध में उनका कहना था कि वह दलितों का भला नहीं कर सकते. माया का यह दावा बता रहा था कि बसपा में भी आप को लेकर सुगबुगाहट है. कांग्रेस के युवराज और संभावित कांग्रेसी प्रधानमंत्री राहुल गांधी के खिलाफ जरूर उनके तेवर लचर रहे. इसे बसपा की दूरगामी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

माया की सावधान रैली खत्म हो गई. पूरे देशभर से आए उनके लाखों प्रशंसक अपने घर चले गए, लेकिन माया की बातों का पोस्टमॉर्टम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. सावधान रैली करके बसपा ने क्या खोया, क्या पाया, यह बहस बुद्धिजीवियों के साथ राजनीति के गलियारे में भी चर्चा का विषय बनी हुई है. पिछले दो वर्षों में यूपी की सियासत में आए बड़े बदलाव से माया के पंख निकल आए हैं. सपा राज के दंगों और मोदी के उभार ने बसपा को नई ताकत प्रदान की है. माना जा रहा था कि माया लोकसभा चुनाव भी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर लड़ेंगी, लेकिन सावधान रैली में एक घंटा और 48 मिनट के भाषण के दौरान चालीस मिनट तक दलित एजेंडे पर उनके केंद्रित रहने से साफ हो गया कि दलित वोट बैंक को लेकर पार्टी पूरी तरह से गंभीर है. पूरे संबोधन में मयावती ने तीन बार खुद को दलित समाज की बेटी कहकर दलित शक्ति की ताकत की याद दिलाने की कोशिश की. हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे नारे दूर-दूर तक नजर नहीं आए. दलितों के बाद उनका फोकस मुसलमानों पर रहा. वह मौके का फायदा उठाकर सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने को आतुर दिखीं. माया ने आरोप लगाया कि सपा सरकार दलित महापुरुषों के नाम पर बने विश्वविद्यालयों और स्मारकों का नाम बदल कर उन्हें मुस्लिम समाज के महापुरुषों के नाम पर रखकर दलित-मुस्लिमों को लड़ाने की साजिश कर रहा है. मुस्लिमों की हमदर्दी हासिल करने के लिए माया ने गुजरात दंगों और गोधरा कांड का भी सहारा लिया. देखना यह है कि माया के तीर कितने निशाने पर बैठते हैं. बसपा सुप्रीमो लगातार अपने संबोधन से सपा-भाजपा और कांग्रेस की इमेज थ्री इडियट जैसी बनाने में लगी रहीं.

बहरहाल भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को माया का 'रौद्र' रूप रास नहीं आ रहा है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आरोप लगाया कि बसपा की रैली विफल रही. माया के भाजपा नेताओं पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. माया को आरोप लगाने से पहले सौ बार सोचना चाहिए था. वह मौजूदा समय में जो भी हैं, भाजपा की वजह से हैं. उन्हें भाजपा के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार भी नहीं है. भाजपा इसका जबाव 2 मार्च को लखनऊ में होने वाली मोदी की रैली में देगी. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने माया के बारे में सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय नहीं है. कांग्रेस का भविष्य अधंकारमय बताने वाले खुद गर्दिश में चले जाते हैं. यह बात 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगी. बसपा पर इसकी प्रबल प्रतिद्वंद्वी समाजवदी पार्टी ने तीखा हमला किया. बसपा की रैली खत्म होने के मात्र दो घंटे के भीतर सपा के महासचिव और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने मीडिया को बुलाकर भड़ास निकली. उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि मथेफ्फरनगर के पीड़ितों के आंसू पोंछने तो बसपा अध्यक्ष कभी उनके बीच गई नहीं, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाने में वे सबको पीछे छोड़ चुकी हैं. समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा से भी उन्हें खतरा लगता है, क्योंकि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ मिलने पर उन्होंने जिस तरह बंदिश लगाई थी, उसका भांडा फूट चुका है. शिवपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को क्राइम प्रदेश कहना प्रदेश की जनता को अपमानित एवं बदनाम करना है. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा बदहाल उनके समय रही. हत्या, बलात्कार, लूट में उनके समय ही आधा दर्जन मंत्री, विधायक अदालती आदेश पर जेल गए थे. खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने माना था कि उनकी पार्टी और सरकार में 500 अपराधी हैं. वे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के दिन से ही राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

गणतंत्र दिवस एवं महाशिवरात्रि पर जनपदवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं

रमेश वर्मा
प्रोपराइटर मेंसर्स सगम आभूषण भंडार, हरवंश गली, (हिंदी बाजार) गोरखपुर (उ.प्र.)

वृक्ष लगाओ, देश बचाओ

26 जनवरी, 2014 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वन परिवार की तरफ से जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

(टी.के.राय)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा. वा. वन प्रभाग, कुशीनगर

(आर.पी.सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सा.वा.वन प्रभाग, कुशीनगर

स्वच्छ गोरखपुर ! स्वस्थ गोरखपुर !! सुन्दर गोरखपुर !!!

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर निगम के तरफ से महानगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाए

माननीय आजम खाँ
नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश

डा. सत्या पाण्डेय
महापौर
नगर निगम, गोरखपुर

माननीय अखिलेश यादव
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

हम सृजन करें। आप रक्षा करें।।

नगर निगम, गोरखपुर

हम नगर निगम गोरखपुर महानगर के निरन्तर विकास एवं महानगर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुन्दर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और महानगरवासियों से अपील की जाती है।

- दूषित जल, खुले खाद्य सामग्री का प्रयोग न करें..अन्यथा..बीमारी !
- पालीथिन का प्रयोग बन्द करें..अन्यथा..नाली चोक, जलजमाव, बीमारी !
- करों का समय से भुगतान करें..अन्यथा..ब्याज में बढ़ोत्तरी , विकास में बाधा !
- अपने पशुओं को खुले में न छोड़े..अन्यथा..ट्रैफिक जाम, बच्चों व महिलाओं को खतरा !

कृपया महानगर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण में सहयोग दें और सुन्दर स्वच्छ वातावरण का सृजन करें।

राजेश कुमार त्यागी
नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

समस्त पार्षदगण

जियाउल इस्लाम
उपसभापति
नगर निगम, गोरखपुर

कार्यालय नगरपालिका परिषद, पडरौना जनपद-कुशीनगर

संख्या : 389/विज्ञापन/2013-14 दिनांक: 21.1.14

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2014) के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद-कुशीनगर विकास की ओर अग्रसर है तथा अपने नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है तथा जनहित में निम्न अपेक्षाएं रखती है.

अपेक्षाएं

1-नगर में चल रहे विकास कार्य में अपना सहयोग दें

2-नगर पालिका के समस्त बकाया करों/लाइसेन्सिंग फीस/दुकान किराया समय से अदा करें.

3-नगर पालिका के सड़क/पटरी/नाली/सार्वजनिक प्रायोजन की भूमि/कुंआ/भीटा पर अतिक्रमण कदापि न करें, क्योंकि यह संज्ञेय अपराध की परिधि में है और ऐसे अतिक्रमणकारी के विरुद्ध जुर्माने पर एवं कारावास का प्रावधान शासन द्वारा शासनादेशानुसार किया गया है.

4-नगरपालिका से जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण समय से कराएं.

5-नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें तथा निर्धारित स्थल पर ही कूड़ा फेकें.

6-नगर में सड़ा, गला, शाक-सब्जी, फल, मिष्ठान, मांस, मछली का सेवन न करें. ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु नगरपालिका परिषद, पडरौना को सूचित करें.

7-पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु वृक्षारोपण करें तथा अपने जेनरेटर को सड़क के किनारे संचालित न करें, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है

8-नगर के अंदर वाहन धीमी गति से चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन करें.

9-नगर के अंदर भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर ही भवन का निर्माण करें.

10-नगर में आवारा पशुओं/सुअरों आदि को खुला न छोड़ें, क्योंकि इससे नगर में गंदगी फैलती है.

11-अनावश्यक जल न बहाएं, क्योंकि जलाशय का भंडारण सीमित है.

शुभेच्छू

(सचिन कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी सदर/
अधिशासी अधिकारी
न.पा.परिषद, पडरौना

(शिवकुमारी देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
पडरौना-कुशीनगर

(रिग्जियान सैम्फिल)
जिलाधिकारी
कुशीनगर

एवं सभासदगण

1-संगीता श्रीवास्तव 2-भुअर प्रसाद 3-संगीता चौधरी 4-उषा सिंह 5-रजत 6-पूनम सिंह 7-ओमप्रकाश यादव 8-त्रलोकी मदेशिया 9-सुरेश गुप्ता 10-प्रमोद श्रीवास्तव 11-सुभाष सोनी 12-कृष्णा सिंह पटेल 13-गिरिजादेवी 14-सुरेश चौरसिया 15-प्रतिमा चौरसिया 16-लक्की सिंह 17-राकेश मदेशिया 18-विश्वनाथ जायसवाल 19-राजकुमार 20-राजन जायसवाल 21-रवि शर्मा 22-शायरा 23-महेनुर 24-शहनाज 25-राजन शाहा

शासन से नामित सभासद

1-विजय कुमार यादव 2-कौशल शुक्ला 3-कैसर जमाल टीटू 4-रामसहारे पाठक 5-क्यामुद्दीन

अजय कुमार , लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111